● वर्ष-4
● अंक-03
रायपुर, रविवार
11 अगस्त 2024
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.
samacharpacheesa@gmail.com

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6›› कृति सेनन के रांक्षणा बनेंगे धनुष

इंदिरा की तानाशाही के आगे न्यायपालिका ने टेके थे घुटने

आपातकाल पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बड़ा बयान

नई दिल्ली। आपातकाल को लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बड़ा बयान सामने आया है। जगदीप धनखड़ ने कहा कि यदि उच्चतम स्तर पर न्यायपालिका इंदिरा गांधी की तानाशाही के आगे झुकी नहीं होती, तो आपातकाल की स्थिति नहीं आती। उन्होंने कहा कि हमारा देश बहुत पहले ही अधिक विकास कर चुका होता। हमें दशकों तक इंतजार नहीं करना पड़ता। जगदीप धनखड़ ने आज कानून के शासन के प्रति न्यायपालिका की दृढ़ प्रतिबद्धता की सराहना की, साथ ही भारत के इतिहास के एक दर्दनाक अध्याय - जून 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी

द्वारा लगाया गया आपातकाल - पर भी विचार किया।

आपातकाल के दौर को आजादी के बाद का सबसे क्रूर और काला दौर बताते हुए, धनखड़ ने चिंता व्यक्त की कि इस दौरान न्यायपालिका का सर्वोच्च स्तर, जो आमतौर पर बुनियादी अधिकारों का एक दुर्जेय गढ़ होता है, निर्लज्ज तानाशाही शासन के आगे झुक गया। उपराष्ट्रपति ने कहा, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि आपातकाल के दौरान कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकता। उन्होंने असंख्य नागरिकों की स्वतंत्रता पर इस फैसले के गंभीर प्रभावों की ओर इशारा किया।

उन्होंने कहा कि सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया है, ताकि यह याद दिलाया जा सके कि जब एक व्यक्ति ने भारत के संविधान को लापरवाही से रौंद दिया था, तब क्या हुआ था। संविधान के किसी भी हिस्से का पालन नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान, एक व्यक्ति ने स्वतंत्रता को बंधक बना लिया था। बिना किसी गलती के गिरफ्तार किए गए लोगों को न्यायिक मदद लेने से रोक दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने 9 उच्च न्यायालयों के उन फैसलों को पलट दिया, जिन्होंने पीड़ितों के पक्ष में फैसला सुनाया था। यह न्यायालय 9 उच्च न्यायालयों की उस सचित्र सूची में था। मुझे वास्तव में इस संस्था का हिस्सा होने पर गर्व है!!

उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति ने स्वतंत्रता को बंधक बना लिया और देश भर में हजारों लोगों को बिना किसी गलती के गिरफ्तार कर लिया गया, सिवाय इसके कि वे भारत माता और राष्ट्रवाद में दिल से विश्वास करते थे। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) ने क्रमशः भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ली है और ये एक जुलाई से प्रभावी हो गए हैं।

उन्होंने कहा, ''ये कानून हमें औपनिवेशिक विरासत से मुक्त करने और उसकी मानसिकता से छुटकारा दिलाने के लिए हैं। ये कानून हमारे द्वारा, हमारे लिए हैं...।''

धनखड़ ने जोधपुर में एक राज्य स्तरीय सम्मेलन में न्यायिक अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा, '' (नए कानूनों को लेकर) 'मिशन मोड' में रहें, इनके प्रति जुनूनी बनें, लोगों को इनकी जरूरत है।

क्रांतिकारी बदलाव आए हैं। इन कानूनों को लागू करने में आपकी तैयारी और भागीदारी ही इस क्रांतिकारी कदम की सफलता को निर्धारित करेगी।''

बांग्लादेशः सड़कों पर उतरे हजारों हिंदू, नई सरकार से मांग रहे इंसाफ

ढाकाः पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में शेख हसीना के इस्तीफा देने के बाद और देश छोड़ने के बाद हिंदुओं पर हिंसा लगातार बढ़ गई है। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन हो चुका है। लेकिन अभी भी हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। राजधानी ढाका की सड़कों से पुलिस गायब है और सेना ने पूरी तरह मोर्चा संभाल रखा है। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय मंदिरों पर हमलों के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है। देशभर में शनिवार को हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के विरोध में हिंदू समुदाय ने मार्च किया।

प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि यह सभी का है, इसपर किसी एक समुदाय का अधिकार नहीं है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कदम उठाने की मांग की। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने जमकर नारेबाजी भी की। लोगों ने कहा- %यह देश किसी के बाप का नहीं है, इसके लिए हमने खून दिया है, जरूरत पड़ी तो फिर से खून देंगे। बांग्लादेश नहीं छोड़ेंगे।% उन्होंने

हिंदुओं पर हो रही हिंसा के दौरान मूकदर्शक बने रहने को लेकर सिविल सोसाइटी के सदस्यों पर नाराजगी जताई। इस प्रदर्शन में भाग लेने वाले कनु कुमार के हवाले से बताया कि बांग्लादेश के हिंदू अपने घरों और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा चाहते हैं।

प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि सरकार उन लोगों को मुआवजा दे जिन्होंने अपनी संपत्ति खो दी है और जिन मंदिरों को तोड़ दिया गया है उनका पुनर्निर्माण किया जाए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे देश छोड़ने वाले नहीं हैं, अपना अधिकार पाने के लिए सड़कों पर रहेंगे। उन्होंने जमात-ए-इस्लामी, बीएनपी और हिंदुओं पर हमले की निंदा करने वालों को धन्यवाद दिया।

बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा पर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता ने कहा कि वह नस्लीय आधार पर किसी भी हमले या हिंसा के खिलाफ हैं। महासचिव के उप प्रवक्ता फरहान हक ने गुरुवार को कहा, %हमने स्पष्ट किया है, हम सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हाल के हफ्तों में बांग्लादेश में होने वाली हिंसा को शांत किया जाए। निश्चित रूप से, हम किसी भी नस्लीय आधारित हमले या नस्लीय आधार पर हिंसा भड़काने के खिलाफ हैं।

बांग्लादेश में हिंसा भड़कने के बाद कई हिंदू मंदिरों, घरों और व्यवसायों को निशाना बनाया गया है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी से जुड़े कम से कम दो हिंदू नेता हिंसा में मारे गए हैं। बांग्लादेश में जॉब कोटा को लेकर शुरू हुआ छात्रों का विरोध प्रदर्शन शेख हसीना सरकार के पतन के का कारण बना. उन्हें देश छोड़कर भागने के लिए मजबूर होना पड़ा।

हसीना के देश छोड़ने के बाद देशव्यापी हिंसा में कम से कम 232 लोग मारे गए। उपद्रवियों ने हिंदुओं, उनके धार्मिक स्थलों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया। कई पुलिस थाने आग के हवाले कर दिए गए, पुलिस वालों पर जानलेवा हमले हुए। इसके विरोध में बांग्लादेश पुलिस के कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। अब जबकि बांग्लादेश में नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हो गया है, देश में सामान्य स्थिति बहाल करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं।

अब अमेरिका देगा सीधा दखल?

दो प्रमुख भारतीय-अमेरिकी सांसदों श्री थानेदार और राजा कृष्णमूर्ति ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ टारगेटेड अटैक को रोकने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के सीधे हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने तर्क दिया कि धार्मिक असहिष्णुता और हिंसा से प्रेरित क्षेत्र में अस्थिरता अमेरिका या उसके सहयोगियों के हित में नहीं है। अंतरिम सरकार के प्रमुख मुहम्मद यूनुस को लिखे पत्र में दो हिंदू संगठनों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, सोमवार से 52 जिलों में अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों पर कम से कम 205 हमले हुए हैं, जब शेख हसीना (76) ने इस्तीफा दे दिया और व्यापक विरोध के बाद भारत भाग गईं। 9 अगस्त को अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को लिखे एक पत्र में कांग्रेसी श्री थानेदार ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों के खिलाफ वह अकेले नहीं हैं। उनके अपने जिले के कुछ लोगों सहित अंतरराष्ट्रीय समुदाय के कई लोगों ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समूहों के खिलाफ की जा रही हिंसक कार्रवाइयों की निंदा की है। थानेदार ने लिखा कि मुहम्मद यूनुस के बांग्लादेश के अंतरिम प्रधान मंत्री के रूप में आगे बढ़ने के साथ, संयुक्त राज्य अमेरिका का दायित्व है कि वह इस नई सरकार की सहायता करे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हिंसा और नागरिक अशांति समाप्त हो। मैं बाइडेन प्रशासन से सताए गए बांग्लादेश को अनुदान देने का आग्रह करता हूं। हिंदुओं और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों को शरणार्थियों के रूप में अस्थायी रूप से संरक्षित दर्जा दिया गया है।

निकटतम सहयोगी और अमूल्य साझेदार, मोदी के जय के सामने भारत की शान में कसीदे पढ़ने लगे मुइज्जू

नई दिल्ली। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने शनिवार को पड़ोसी देश भारत के साथ संबंधों को संरक्षित और मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की और इसे द्वीपसमूह राष्ट्र के निकटतम सहयोगियों और अमूल्य भागीदारों में से एक बताया। उन्होंने मालदीव के 28 द्वीपों पर पूर्ण जल आपूर्ति और सीवरेज सुविधाओं को सौंपने के लिए राष्ट्रपति कार्यालय में आयोजित एक समारोह में अपनी टिप्पणी की, जिसे एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से भारत सरकार की लाइन ऑफ क्रेडिट सुविधा द्वारा वित्त पोषित किया गया था। मुइज्जू ने स्वीकार किया कि भारत ने जब भी मालदीव को जरूरत पड़ी है सहायता प्रदान की है और पहल महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ प्रदान करेगी, स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देगी और साथ में देश की समृद्धि में योगदान देगी। उन्होंने मालदीव को उदार और निरंतर सहायता के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार का आभार व्यक्त किया। समारोह में बोलते हुए, मालदीव के राष्ट्रपति ने कहा कि ये परियोजनाएं दोनों पड़ोसियों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण मील का पत्थर हैं.

उद्धव और शरद दंगे भड़काने के लिए मराठा आरक्षण आंदोलन का इस्तेमाल करने की कोशिश में लगेः राज ठाकरे

मुंबई। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने 10 अगस्त को आरोप लगाया कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे राज्य में खासकर मराठवाड़ा क्षेत्र में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले दंगे भड़काने के लिए मराठा आरक्षण आंदोलन का इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने दावा किया कि ये दोनों मनोज जारांगे के नेतृत्व वाले आरक्षण आंदोलन को जाति की राजनीति के लिए ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे। राज ठाकरे ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि उनके आंदोलन को ढाल के रूप में इस्तेमाल करके शरद पवार और उद्धव ठाकरे जैसे लोग मराठवाड़ा में राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर शिवसेना (यूबीटी) और एनसीपी (शरदचंद्र पवार) उनके मराठवाड़ा दौरे में बाधा डालने की कोशिश करेंगे तो वे महाराष्ट्र में एक भी रैली नहीं कर पाएंगे। उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब एक दिन पहले बीड शहर में उनके काफिले के गुजरने के दौरान कुछ कार्यकर्ताओं, जिन पर संदेह है कि वे शिवसेना (यूबीटी) से जुड़े हुए थे, ने सुपारी फेंकी थी। इस कृत्य के लिए चार शिव सेना (यूबीटी) कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया।

इससे पहले दिन में शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने स्वीकार किया कि राज ठाकरे के खिलाफ विरोध करने वाले लोग ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट के पदाधिकारी हो सकते हैं। हालांकि, उन्होंने शुक्रवार के प्रदर्शन से शिवसेना (यूबीटी) को अलग कर दिया।

प्रमुख समाचार

14 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया दुष्कर्म-हत्या का आरोपी

कोलकाता। कोलकाता की एक अदालत ने महिला स्नातकोत्तर प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ कथित दुष्कर्म और हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार आरोपी को शनिवार को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया। आरोपी को गिरफ्तारी के बाद शनिवर को सियालदह अदालत में पेश किया गया। उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64 (दुष्कर्म) और 103 (हत्या) के तहत मामला दर्ज है। इससे पहले, कोलकाता पुलिस आयुक्त विनीत गोयल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पुलिस यह सुनिश्चित करेगी कि एक महिला स्नातकोत्तर प्रशिक्षु डॉक्टर के कथित यौन उत्पीड़न और हत्या के आरोपी को अदालत में आरोप साबित होने पर अधिक से अधिक सजा मिले। महिला डॉक्टर का शव शुक्रवार को उत्तरी कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल के सेमिनार हॉल के अंदर पाया गया। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनकी हत्या से पहले यौन शोषण की पुष्टि हुई। गोयल ने कहा, यह एक जघन्य अपराध है। आरोपी को कथित परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर गिरफ्तार किया गया, जिसमें रात की ड्यूटी के दौरान मौजूद अन्य डॉक्टरों के विवरण भी शामिल हैं। उन्होंने कहा, एक एसआईटी का गठन किया गया है.

सोमनाथन को मोदी सरकार ने बनाया कैबिनेट सचिव

नई दिल्ली। नरेंद्र मोदी सरकार ने शनिवार को 1987 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी टीवी सोमनाथन को दो साल के कार्यकाल के लिए कैबिनेट सचिव नियुक्त किया। वह 1982 बैच के आईएएस अधिकारी राजीव गौबा का स्थान लेंगे, जिनका कैबिनेट सचिव के रूप में पांच साल का कार्यकाल अभूतपूर्व था। बयान में कहा गया है कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने टीवी सोमनाथन, आईएएस को कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से कैबिनेट सचिव के रूप में कार्यभार संभालने तक कैबिनेट सचिवालय में विशेष कर्तव्य अधिकारी के रूप में नियुक्ति को भी मंजूरी दे दी है। आईएएस अधिकारी के पास अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि है और वह एक योग्य चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए), लागत लेखाकार और कंपनी सचिव हैं। उन्होंने पत्रिकाओं और समाचार पत्रों में अर्थशास्त्र, वित्त और सार्वजनिक नीति पर 80 से अधिक पत्र और लेख प्रकाशित किए हैं, और दो पुस्तकों के साथ-साथ कई अन्य अध्यायों के लेखक हैं। उन्होंने आईएएस से प्रतिनियुक्ति पर विश्व बैंक, वाशिंगटन डी.सी. में निदेशक के रूप में भी काम किया है।

सुरक्षाबलों की आतंकियों से मुठभेड़, दो जवान शहीद

जम्मू। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के कोकरनाग इलाके के सुदूरवर्ती जंगल क्षेत्र में आतंकियों से शनिवार शाम शुरू हुई मुठभेड़ में दो जवान बलिदान हो गए। तीन अन्य घायल हैं। सुरक्षा बलों की ओर से पूरे इलाके की घेराबंदी कर रखी गई है ताकि दहशतगर्द मौके से भाग न निकलें। हालांकि, सेना की ओर से फिलहाल जवानों के घायल होने की बात कही जा रही है। पुलिस ने बताया कि कोकरनाग के अहलान गडोल इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी। इसके बाद तुरंत सुरक्षाबलों ने इलाके की घेराबंदी कर बड़े स्तर पर तलाशी अभियान शुरू किया। सुरक्षाबलों को नजदीक आते देख छिपकर बैठे आतंकियों ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। जवानों ने तुरंत मोर्चा संभालते हुए आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। इससे मुठभेड़ शुरू हो गई। गोलीबारी में पांच जवान घायल हो गए। इन्हें तत्काल निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। इलाज के दौरान इनमें से दो जवानों ने दम तोड़ दिया। सेना के अनुसार फायरिंग के दौरान दो नागरिक भी घायल हुए हैं। इन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह जानने का प्रयास किया जा रहा है कि दोनों नागरिकों के आतंकियों के साथ संबंध तो नहीं रहे हैं। ऑपरेशन में जम्मू-कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी), सेना की 19 राष्ट्रीय राइफल्स (आरआर) और सीआरपीएफ के जवानों को लगाया गया है।

उप्र जातीय जनगणना के मुद्दे पर पैनी होगी कांग्रेस की रणनीति

लखनऊ। कांग्रेस जातिगत जनगणना कराने और आरक्षण पर लगी 50 फीसदी की सीमा हटाने, सामाजिक न्याय सहित विभिन्न मांगों को लेकर हर मंडल में सम्मेलन करेगी। इसकी शुरुआत रविवार को कानपुर से होने जा रही है। कांग्रेस के रणनीतिकारों का मानना है कि लोकसभा चुनाव में जातिगत जनगणना और सामाजिक न्याय के मुद्दा कारगर साबित हुआ। इसकी वजह से इंडिया गठबंधन को काफी फायदा हुआ। ऐसे में पार्टी इस मुद्दे को खोना नहीं चाहती। इसी रणनीति के तहत कांग्रेस पिछड़ा विभाग, अल्पसंख्यक विभाग और फिशरमैन विभाग की ओर से 26 जुलाई से छह अगस्त तक हस्ताक्षर अभियान चलाया गया और एक लाख से अधिक हस्ताक्षर वाले पत्र राज्यपाल के जरिये राष्ट्रपति को भेजे गए। अब पार्टी की ओर से मंडलीय सम्मेलन की शुरुआत की जा रही है। पिछड़ा वर्ग विभाग के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव ने बताया कि रविवार को कानपुर के काकादेव में मंडलीय सम्मेलन होगा। इस सम्मेलन में जातिगत जनगणना और आर्थिक सर्वे, आरक्षण पर लगी 50 फीसदी की सीमा को हटाने, एससी-एसटी आरक्षण में उपवर्गीकरण न करने, वक्फ कानून में बदलाव न करने, नौकरी में निजीकरण बंद करने आदि की मांग की जाएगी।

हिंडनबर्ग ने सेबी चेयरपर्सन माधबी बुच को लपेटा,

मुंबई। भारतीय बिजनेसमैन गौतम अडानी के खिलाफ सनसनीखेज रिपोर्ट लाकर सुर्खियां बटोरने वाली हिडेनबर्ग रिसर्च ने एक बार फिर बड़ा खुलासा किया है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने 10 अगस्त को कहा कि व्हिसलब्लोअर दस्तावेजों से पता चला है कि सेबी की चेयरपर्सन माधबी बुच और उनके पति की अडानी मनी साइफनिंग घोटाले में इस्तेमाल किये गए दोनों अस्पष्ट ऑफशेयर फंडों में हिस्सेदारी थी। व्हिसिलब्लोअर दस्तावेजों के अनुसार, ऐसा प्रतीत होता है कि माधबी बुच और उनके पति धवल बुच ने पहली बार 5 जून, 2015 को सिंगापुर में आईपीई प्लस फंड 1 के साथ एकाउंट ओपन किया था। दस्तावेजों में आगे कहा गया कि आईआईएफएल के एक प्रिंसिपल द्वारा हस्ताक्षरित धन की घोषणा में इन्वेस्टमेंट के स्रोत को सैलरी बताया गया और जोड़े की कुल संपत्ति .10 मिलियन होने का अनुमान है। इससे पहले आज सुबह अमेरिकी शॉर्ट सेलर ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि भारत में जल्द ही कुछ बड़ा होगा। पिछले साल 24 जनवरी को हिंडनबर्ग रिसर्च ने अदानी एंटरप्राइजेज की योजनाबद्ध शेयर बिक्री से ठीक पहले अदानी समूह की तीखी आलोचना करते हुए एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी।

कहां गये मानवाधिकारी और मोहब्बत की दुकान के ठेकेदार

बांग्लादेश संकट, हिंदुओं के साथ नफरती हिंसा और भारतीय सेक्युलर

मृत्युंजय दीक्षित

बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद वहां रहने वाले 1.35 करोड़ हिंदु समाज के साथ जो बर्बर हिंसा की जा रही है वह पूरी मानवता को शर्मसार करने वाली है। शेख हसीना के तख्तापलट के बाद से राजधानी ढाका सहित पूरे बांग्लादेश में हिन्दुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं । उनके घरों, प्रतिष्ठानों, दुकानों, मंदिरों को आग लगाई जा रही है उन्हें लूटा जा रहा है। बांग्लादेश में हो रही हिन्दुओं के विरुद्ध हिंसा में इस्कॉन के प्रसिद्ध मंदिर के साथ साथ कम से कम 300 मंदिरों को क्षतिग्रस्त किया जा चुका है, लूटा जा चुका है और आग के हवाले किया जा चुका है। हिंदू अल्पसंख्यकों के बाद सिख, जैन, बौद्ध व अल्पसंख्यक ईसाई समाज के साथ भी अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। बांग्लादेश के उपद्रवियों का मानना है कि है वहां के अल्पसंख्यक शेख हसीना के समर्थक रहे हैं और उन्हीं के वोटों से वह बार बार प्रधानमंत्री बनती रही हैं । छात्र आंदोलन को हाईजैक करने वाले इस्लामिक कट्टरपंथी अब हिंदू समाज से बदला ले रहे हैं।

बांग्लादेश में छात्र आंदोलनकारी यदि केवल आरक्षण विरोधी आंदोलन कर रहे थे तो वह आंदोलन अब तक समाप्त हो जाना चाहिए था किंतु अब इस हिंसा ने कुछ और ही परिदृष्य बना दिया है। बांग्लादेश से आज हिंदू पलायन करना चाहते हैं। बांग्लादेश में सरकार विरोधी हिंसा अब हिंदू विरोधी हिंसा में परिवर्तित हो चुकी है और लगातार जारी है।बांग्लादेश की हिंसा में साधारण हिंदू जनता से लेकर बांग्लादेश के विकास में अहम भूमिका निभाने करने वाले वहां के हिन्दू फिल्म अभिनेता, गायक, खिलाड़ियों के घरों व संपत्ति को भी नहीं छोडा गया है। बांग्लादेश के लोकप्रिय गायक राहुल आनंद के घर जमकर लूटपाट की गई फिर आग लगा दी गई । हिंदू नेताओं के शव बरामद हो रहे हैं तथा वहां पर रहने साधु -संत भी हिंसा का शिकार हो गये हैं। बांग्लादेश में जारी हिंदू विरोधी हिंसा के भयानक वीडियो सोशल मीडिया में लगातार आ रहे हैं। कट्टरपंथियों के निशाने से शमशान तक नहीं बचे हैं। बांग्लादेश में शायद ही कोई जिला बचा हो जो इनकी हिंसा व आतंक का निशाना न बना हो।

बांग्लादेश में हिंदुओ के साथ ऐसी हिंसा शेख हसीना सरकार के कार्यकाल में भी किसी न किसी बहाने होती रही है। आंकड़ों के अनुसार बांग्लादेश में 2013 से 2022 तक हिंदुओं पर 3600 हमले हुए थे, कभी ईशनिंदा के नाम पर कभी किसी बहाने। बांग्लादेश में विभाजन के समय हिंदू 32 प्रतिशत थे जो अब 8 प्रतिशत से भी कम बचे हैं और वह भी लगातार जेहादी उत्पीड़न के शिकार हो रहे हैं । अब ताजा हिंसा से बांग्लादेश से हिंदुओं का पलायन और तीव्रता के साथ होने की आशंका बलवती हो गयी है।यही कारण है कि देश की सभी सुरक्षा एजेंसियां सीमा पर हाई एलर्ट मोड में हैं।

भारत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित सभी हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ घट रही पीड़ादायक हिंसा की निंदा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वहां पर तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के नये अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद युनूस को बधाई देते हुए हिंदुओं की सुरक्षा करने की बात भी कही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी बांग्लादेश के हालात पर लगातार नजर रख रहे हैं।

भारत में बांग्लादेश की हिंसा पर दुख व चिंता है लेकिन दुर्भाग्य यह है भारत के विरोधी दल और उनके प्रवक्ता इसमें भी अपने वोट बैंक को खुश करने का प्रयास करते दिखाई पड़ रहे हैं। बांग्लादेश प्रकरण पर कांग्रेस अथवा इंडी गठबंधन दल के किसी भी नेता ने हिन्दुओं पर हो रही हिंसा की निंदा तक नहीं की है। कांग्रेस के सत्तालोलुप नेता तो यहाँ तक सपने देखने लगे कि 卐भारत में भी बबांग्लादेश जैसे हालात हो सकते हैं卐 जैसे बयान दे रहे हैं। इनमें कांग्रेस के नेता बैसाखी चोर नेता सलमान खुर्शीद से लेकर मणिशंकर अय्यर तक शामिल हैं। स्मरणीय है कि लोकसभा चुनावों के दौरान सलमान खुर्शीद की रिश्तेदार ने चुनाव पचार के दौरान वोट जिहाद करने की अपील की थी।

भारी निराशा में ये लोग सत्ता के लालच में भारत को बांग्लादेश जैसे हिंसक हालात में धकेलने के सुनियोजित षड्यंत्र के तहत ऐसे बयान दे रहे हैं । यह समय जन सामान्य के लिए भी बहुत ही सतर्कता व सावधानी बरतने वाला है क्योंकि सलमान खुर्शीद और मणि शंकर अय्यर अकेले नहीं हैं फारूख अब्दुल्ला से लेकर महबूबा मुफ्ती और उद्धव ठाकरे सरीखे नेता भी इनका समर्थन कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे एक समय हिंदूवादी नेता माने जाते थे किंतु बांग्लादेश में हिंदुओ के साथ जो अमानवीय अत्याचार हो रहे हैं उसकी निंदा तक नहीं कर रहे हैं अपितु इंडी गठबंधन के साथ जश्न ही मना रहे हैं। भारत में भी आज के विषम राजनीतिक वातावरण में हिंदुओं की सुरक्षा व अस्मिता ही सबसे सस्ती हो गई है क्योंकि वह जातियों में बंटा होने के कारण बड़ा वोट बैक नहीं बन सकता है। यह भी विचारणीय प्रश्न है कि क्या बांग्लादेश की घटनाओं से भारत के हिन्दू कुछ शिक्षा लेंगे ? बंगला देश में जो मारे जा रहे हैं वो केवल हिन्दू हैं कोई नहीं देख रहा कि वो दलित है, पिछड़ा है या सवर्ण है केवल यह देखा जा रहा है कि हिंदू है।

आक्रमणकारी शत्रुओं द्वारा अब तक सैकड़ों बार हिंदुओं का नरसंहार और बलात धर्म परिवर्तन कराया गया जो अनवरत आज भी चल रहा है। राहुल गांधी सरीखे लोग हिंदुओं को हिंसक बताते हैं और उनके उत्पीड़न का आम खाकर जश्न मनाते हैं।

जशपुर के बगीचा शहर में हाथी ने बरपाया कहर

■ चार लोगों को उतारा मौत के घाट

जशपुर/ जांजगीर चांपा। छत्तीसगढ़ से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जहां जशपुर जिले के बगीचा शहर में बीती रात जंगली हाथी ने कहर मचा दिया। इस हमले में एक ही परिवार के तीन सदस्यों समेत चार लोगों की मौत हो गई। घटना की पुष्टि जिला वनमंडलाधिकारी जितेंद्र उपाध्याय ने की है, जिसने पूरे इलाके में शोक और दहशत का माहौल बना दिया है।

खराब मौसम के कारण क्षेत्र में बिजली बाधित थी, जिससे रात के समय में अंधेरा छाया हुआ था। इसी बीच, गम्हरिया मोहल्ले में सड़क किनारे स्थित एक घर पर हाथी ने अचानक हमला कर दिया, जहां परिवार के छह सदस्य सो रहे थे। हाथी ने पहले पिता,

पुत्री, और चाचा पर हमला किया और फिर पड़ोस में रहने वाले एक युवक को भी निशाना बनाया। ग्रामीणों के अनुसार, हो-हल्ला सुनकर पड़ोसी का एक युवक बाहर निकला, लेकिन हाथी ने उसे भी पटककर मार डाला।

इन लोगों की हुई मौत

1. रामकेश्वर सोनी (उम्र 35 वर्ष) 2. रवीता सोनी (उम्र 09 वर्ष) 3. अजय सोनी (उम्र 25 वर्ष) 4. अश्विन कुजूर (उम्र 28 वर्ष)।

जांजगीर चांपा जिले के बलौदा क्षेत्र के हरदी विशाल गांव में एक दंतैल हाथी ने स्कूल परिसर में रखे मोटर साइकिल और साइकिल को अपनी सूंड से उठा लिया। इसका वीडियो वायरल हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में हाथी विचरण कर रहा है, जिसे लेकर लोगों में दहशत का माहौल है। वन विभाग और पुलिस ने हाथी पर नजर बनाकर रखी हुई है।

शुक्रवार को हाथी कोरबा जिले से होकर जांजगीर चांपा जिले के बलौदा वन मंडल में पहुंचा। हरदिविशाल गांव में शाम करीब पांच बजे के बाद स्कूल के अंदर घुसा गया और साइकिल को उठाकर इधर-उधर करने लगा और एक मोटरसाइकिल को नुकसान पहुंचाया है। हाथी की सारी हरकतों को गांव के लोगों ने अपने कैमरे में कैद किया। उत्पाद करने के बाद वह खेतों में चला गया और फसलों को नुकसान पहुंचाते हुए रात को खिसोरा गांव के ठेठवार पारा की चला गया।

डीएफओ प्रियंका पांडेय ने बताया कि झुंड से बिछड़ने के बाद वह चार दिन पहले बलौदा वन मंडल के क्षेत्र में पहुंचा था, जिसके बाद कोरबा चला गया था। शुक्रवार की शाम को फिर से हाथी बलौदा पहुंचा है। गांव के लोगों को बाहर नहीं निकलने की हिदायत दी गई है और हाथी के सामने नहीं आने की अपील की गई है। हाथी को सुरक्षित दूसरी जगह भेजना के लिए अचानक मार्ग से एक ट्रैकर हाथी को मंगाया गया है, जो कि अपनी आवाज से हाथी को बुलाकर उसे रिहायसी इलाकों से दूर जंगल में छोड़ सके।

छत्तीसगढ़ में नक्सल टेरर फंडिंग

पुलिस ने 5 माओवादी सहयोगियों को पकड़ा

राजनांदगांव। आईजी राजनांदगांव रेंज दीपक कुमार झा ने नक्सल टेरर फंडिंग का खुलासा किया। झा ने बताया कुछ समय पहले नक्सल सहयोगी सरजू टेकाम के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम और जनसुरक्षा अधिनियम में कार्रवाई की गई थी। सूचना के आधार पर उसके घर पर रेड की गई तो काफी विस्फोटक सामग्री और आपत्तिजनक दस्तावेज मिले थे। इस मामले में जांच जारी थी जिसमें और भी कई खुलासे हुए।

दीपक कुमार झा ने बताया सरजू टेकाम नक्सलियों के शहरी नेटवर्क के लिए काम कर रहा था। नक्सलियों की विचारधारा को अलग अलग घूम कर उसका प्रचार प्रसार कर रहा था। मार्च के महीने में सरजू टेकाम अपने एक साथी के साथ दिल्ली गया था। इन सब काम के लिए फंडिंग कहां से हो रही है? इसका जब हमने पता लगाया तो पता चला कि विवेक सिंह, वर्तमान में रायपुर का रहने वाला और मूलतः मोहला मानपुर का रहने वाला है। इसने ही ऑनलाइन टिकट करवाया था। विवेक सिंह की सरजू टेकाम से लगातार बात होती थी। सरजू टेकाम ने इसे किसी के माध्यम से पैसा भिजवाया और विवेक सिंह ने सरजू टेकाम और उसके एक अन्य साथी का टिकट करवाया। आईजी ने आगे बताया विवेक सिंह के बारे में जब और पता लगाया गया तो पता चला कि उसका एक बैंक खाता स्टेट बैंक ऑफ मोरेशस मुंबई ब्रांच में इसका खाता है। इसके बाद नक्सल लेवी के बारे में खुलासा हुआ जो तेंदूपत्ता ठेकेदारों से लेवी कर वापस नक्सलियों को भेजते थे। जो बीजापुर भैरमगढ़ के नक्सल सहयोगी है। सोनाराम फरसा, विजय दुर्गी, रामलाल करमा, राजेंद्र कड़ती यह चारों बीजापुर जिले के रहने वाले हैं। विवेक सिंह मानपुर वर्तमान रायपुर का रहने वाला है जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। ये सभी तेंदुपत्ता ठेकेदारों को धमकी देते थे और उनसे वसूली करते थे।

राइस मिलरों पर गिरी गाज, खाद्य विभाग ने 8700 कुंतल चावल किए रिजेक्ट

■ निर्धारित की गई एफआरके की मात्रा मिली कम

गौरेला पेंड्रा मरवाही। भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुरूप चावल नहीं पाए जाने पर भारत सरकार के खाद्य विभाग की टीम ने जांच करते हुए पेंड्रा मरवाही के नागरिक आपूर्ति निगम के गोदाम में रखे हुए 35 लाट चावल रिजेक्ट कर दिए हैं। इन चावलों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित स्त्रक्च्य की मात्रा कम पाई गई थी। सैंपल जांच के बाद गोदाम में जमा चावल को रिजेक्ट करने की यह अब तक की बड़ी कार्रवाई है। नागरिक आपूर्ति निगम के क्वालिटी इंस्पेक्टर ने सैंपल जांच के बाद सभी चावलों को गुणवत्तापूर्ण बताकर जमा कर लिया

था।

कुपोषण और एनीमिया को खत्म करने के लिए राशन दुकानों के माध्यम से फोर्टीफाइड राइस बांटने की योजना पर राइस मिल पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। भारत सरकार के खाद्य विभाग की टीम ने आकस्मिक निरीक्षण कर नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा जमा किए गए राइस मिलरों के चावल की बड़ी खेप निर्धारित गुणवत्तापूर्ण न पाकर रिजेक्ट कर दिया है। रिजेक्ट किए गए चावल की मात्रा भी थोड़ी नहीं, बल्कि कुल 35 लाट हैं। इसमें 50 किलो प्रति बोरी वजन के 17,400 बोरे हैं।

ये वो चावल हैं, जिसे नागरिक आपूर्ति निगम के क्वालिटी इंस्पेक्टर ने पूर्ण गुणवत्तायुक्त बताकर जमा कर लिया था। भारत सरकार द्वारा हुए इस अचानक जांच से राइस मिलरों में हड़कंप मचा हुआ है। नागरिक आपूर्ति निगम के पेंड्रा गोदाम में 30 लाट, जबकि मरवाही गोदाम से एक लॉट चावल को रिजेक्ट किया गया है। यह सभी अमानक चावल जिले के ही छह राइस मिलरों के द्वारा जमा किया गया था।

फोर्टीफाइड राइस में आयरन फोलिक एसिड विटामिन ड्ड12 के साथ जिंक विटामिन ए1, विटामिन बी 2, विटामिन बी ड्ड3 जैसे ड्ड6 पोषक तत्व मौजूद होते हैं। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में कुपोषण से निपटने के लिए फोर्टीफाइड बांटने की योजना सभी राशन दुकानों में शुरू की हैं, जिसके लिए 4270 करोड रुपये खर्च का बजट भी स्वीकृत कर रखा है। सरकार की महत्वपूर्ण योजना पर नागरिक आपूर्ति निगम राइस मिलों के साथ सांठ-गांठ कर पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। मामले में जब नागरिक आपूर्ति निगम के क्वालिटी इंस्पेक्टर से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कमरे पर कुछ भी बोलने से इनकार करते हुए हाथ जोड़ लिया। वहीं, जिला प्रबंधक ने पूरे मामले पर जानकारी दी है।

मुख्यमंत्री की संवेदनशील पहल से पुनः 2 लोगों को मिली अनुकंपा नियुक्ति

परिवार के भरण-पोषण का मिला सहारा

गरियाबंद। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव के सुशासन में त्वरित एवं संवेदनशील पहल से गरियाबंद जिले के 2 लोगों को अनुकंपा नियुक्ति मिली है। जिला प्रशासन श्रीमती बबली विश्वकर्मा एवं श्रीमती भामिनी दीवान को अनुकंपा नियुक्ति सौंपकर निष्ठा एवं लगन से शासकीय सेवा करने की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। पति के निधन पश्चात परिवार के भरण पोषण के लिए चिंतित दोनों महिलाओं की समस्या दूर हो गई है। शासन के सहयोग से मिले अनुकंपा नियुक्ति के फलस्वरूप अब उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई एवं देखरेख की भी चिंता दूर हो गई है। दोनों को भृत्य पद पर नियुक्ति दी गई है।

श्रीमती बबली को शासकीय हायर सेकंडरी स्कूल परसदाकला एवं श्रीमती भामिनी को शासकीय कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल छुरा में पोस्टिंग दी गई है। प्रशासन की त्वरित कार्रवाई के द्वारा अनुकंपा नियुक्ति मिलने से आज दोनों महिलाओं के परिजनों ने खुशी जताते हुए मुख्यमंत्री एवं जिला प्रशासन के प्रति अपना आभार जताया। अनुकंपा नियुक्ति मिलने के बाद उन्होंने कहा कि राज्य शासन की नीति के तहत त्वरित पहल से नौकरी मिल गई है। जिससे आर्थिक समस्याओं को दूर करने एवं परिवार के पालन पोषण में सहायक होगी।

शासन के प्रावधानों के तहत गरियाबंद जिले के कलेक्टर श्री दीपक अग्रवाल ने अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों को तेजी से निराकृत करने के निर्देश दिये हैं। इसी के तहत अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों को तेजी से पूर्ण किया जा रहा है। आज अनुकंपा नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाली फिंगेश्वर निवासी श्रीमती बबली विश्वकर्मा ने बताया कि उनके पति शिक्षक के रूप में सेवारत थे। उनके निधन के बाद परिवार चलाना मुश्किल हो गया था। बच्चों के भविष्य को लेकर चिंता रहती थी। उन्होंने बताया कि अनुकंपा नियुक्ति मिलने से परिवार के पालन पोषण एवं देखरेख में सहायता मिलेगी, साथ ही भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। इसी प्रकार छुरा विकासखंड के ग्राम अकलवारा की रहने वाली श्रीमती भामिनी दीवान के पति भी शिक्षा विभाग में पदस्थ थे। उनके निधन के पश्चात उन्हें भृत्य के रूप में नियुक्ति मिली है। उन्होंने बताया कि पति के जाने के बाद भविष्य चिंतित था। शासन की पहल से अनुकंपा नियुक्ति मिलने से परिवार के खुशहाली में मदद होगी।

बारिश से लगातार बढ़ रहा जलस्तर, कभी भी टूट सकता है बांध

■ डूब सकते कई गांव, शिकायत के बाद भी नहीं की गई मरम्मत

कांकेर। प्रशासन और विभाग की लापरवाही के चलते तीन गांव के लोगों की जिंदगी अब खतरे में आ गई है। ग्रामीण अपना जरुरी सामान, अनाज और परिवार को लेकर सुरक्षित स्थान की ओर भाग रहे हैं। परलकोट क्षेत्र के में स्थित जलाशय के बांध में दरार पड़ चुकी है और जलाशय से बड़ी तेजी से पानी निकल रहा है। अब बांध के टूटने का खतरा मंडरा रहा है।

बता दें कि इस जलाशय में तीन साल पहले से दरार पड़ चुकी थी, जिसकी जानकारी ग्रामीणों द्वारा लगातार सिंचाई विभाग सहित प्रशासन को दी जा रही थी।

ग्रामीणों ने जनदर्शन में भी इस खतरे को लेकर आवेदन दिया था, लेकिन हर बार रिपेयरिंग के नाम पर विभाग द्वारा बस लीपापोती ही किया गई। इसका खामियाजा अब ग्रामीणों को उठाना पड़ सकता है। ग्रामीणों में डर का माहौल बना हुआ है। ग्रामीण बड़ी संख्या में बांध पर पहुंचने लगे और अपने घरों में रखे अनाज और जरुरी सामानों को ट्रैक्टर में भरकर सुरक्षित स्थानों की ओर जाने लगे।

विभाग को जानकारी लगते ही सिंचाई विभाग के एसडीओ और इंजीनियर मौके पर पहुंचे। फिलहाल ग्रामीण और विभाग द्वारा दरार को भरने की कोशिश की जा रही है। दरार का आकार धीरे-धीरे बढ़ रहा है, ऐसे में यदि जल्द से जल्द दरार को नहीं भरा गया तो बांध कभी भी टूट सकता है। जिससे कई गांव डूब सकते हैं और किसानों को फसल और जान-माल का बहूत बड़ा नुकसान हो सकता है। यदि समय रहते ग्रामीणों की विभाग सुन लेता और दरार को भरने के लिए उच्च गुणवत्ता के साथ रिपेयरिंग करवाता तो आज कई लोगों की जिंदगी खतरे में न होती।

बाबाधाम में श्यामबिहारी जायसवाल सपरिवार भोलेनाथ को चढ़ाया जल

मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। सावन के पावन महीने में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने सपरिवार बाबा बैजनाथ के दर्शन कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की है। मनेन्द्रगढ़ विधायक और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल अपनी पत्नी कांति जायसवाल और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ बाबा बैजनाथ के दर्शन करने के लिए बाबा धाम पहुंचे थे। इसके पूर्व श्यामबिहारी जायसवाल ने सुल्तानगंज की गंगा नदी में स्नान किया और वहां से जल लेकर बाबा बैजनाथ को अर्पित किया।

गुरुवार को बोल बम का नारा लगाते हुए सपरिवार श्याम बिहारी जायसवाल सुल्तानगंज पहुंचे। कुछ देर के विश्राम के बाद उन्होंने गंगा नदी में स्नान किया। इसके बाद उनका काफिला कांवड़ में जल लेकर

बाबा बैद्यनाथ के दर्शन के लिये पहुंचा।बाबा को जल चढ़ाकर प्रदेश के सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की।

इस दौरान उन्होंने आम भक्तों की तरह लाइन में लगकर बाबा का आशीर्वाद लिया। आपको बता दें की पिछले 25 वर्षों से स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल सावन महीने में बाबा बैजनाथ का दर्शन करने जाते रहे हैं।इस बार भी वो एक आम भक्त की ही तरह बैजनाथ धाम में पहुंचे और बाबा के दर्शन किए।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

खेत में मिला मगरमच्छ, गांव में दहशत का माहौल

बिलासपुर। अक्सर आपने समुद्र, ताबाल में मगरमच्छ को देखा होगा लेकिन रतनपुर के खेत में विशालकाय मगरमच्छ मिलने से लोग हैरान रह गए। गांव में दहशत का माहौल है। खेत में मगरमच्छ की सूचना के बाद भी वन अमला नहीं पहुंचा तो ग्रामीणों ने खुद रेस्क्यू कर खूंटाघाट जलाशय में मगरमच्छ को छोड़ा। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा। बता दें कि रतनपुर के बिकमा तालाब में बड़ी संख्या में मगरमच्छ हैं। आए दिन मगरमच्छ रिहायशी इलाकों में पहुंच जाते हैं, जिसके चलते हमेशा गांव में दहशत और जान का खतरा बना रहता है।

नेशनल जूनियर गर्ल्स फुटबॉल चैंपियनशिप के लिये टीम रवाना

बीजापुर। एनटीपीसी कोरबा में 17 जुलाई से 20 जुलाई 2024 तक आयोजित प्रतियोगिता में डीएफए (डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन) बीजापुर एवं डीएफए बस्तर के बीच खेला गया था, जिसमें डीएफए बस्तर ने 5-0 से जीत दर्ज किया था। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट खेल के आधार पर नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप के लिए छत्तीसगढ़ टीम का चयन किया जाना था, जिसके कैंप के लिये तीस खिलाड़ियों का चयन किया गया। इसमें बीजापुर के आठ खिलाड़ियों का चयन हुआ था। कैंप 21 जुलाई से 7 अगस्त तक एनटीपीसी कोरबा में लगाया गया। कैंप के बाद तीस खिलाड़ियों में से बाईस खिलाड़ियों का चयन स्किल के आधार पर नेशनल टीम के लिये किया गया, जिसमें बीजापुर के सात खिलाड़ियों का चयन छत्तीसगढ़ टीम के लिये हुआ। इसमें प्रेमा यालम, सुजाता कोर्राम, कौशल्या हपका, मुस्कान यालम, दीपिका, माधवी और जहान्वी हैं। छत्तीसगढ़ की टीम कोरबा से आंध्रप्रदेश के लिए रवाना हुई।

डायरिया ने ली दो की जान स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप

जांजगीर-चांपा। छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले में डायरिया का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। आज फिर डायरिया ने अमोदा गांव के दो मासूम बच्चों को की जान ले ली। वहीं तीन ग्रामीणों का अस्पताल में इलाज चल रहा। मासूमों की मौत के बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। बीएमओ सहित स्वास्थ्य विभाग की टीम अमोदा गांव पहुंची है। जांजगीर चांपा जिला के अमोदा गांव में 3 वर्षीय बालक और 7 वर्षीय बच्ची को रात से उल्टी दस्त हो रही थी। परिजनों ने दोनों को इलाज के लिए अस्पताल ले जा रहे थे, इस दौरान रास्ते में ही दोनों बच्चों ने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा कि गांव के 3 लोगों का चापा अस्पताल में इलाज चल रहा है।

अंतरराज्यीय चोरों पर भारी पड़ी पुलिस, भेष बदलकर रेकी

बिलासपुर। बिलासपुर के सीपत थाना क्षेत्र में 15-16 जुलाई की रात दामोदर ज्वेलर्स का शटर तोड़कर चोरों ने करीब साढ़े 24 लाख का माल उड़ाया था। इस चोरी में सोने चांदी के गहने के साथ कैश भी चोरों ने उड़ाए थे। जिसकी रिपोर्ट अगले दिन ज्वेलर्स के मालिक ने थाने में दर्ज करवाई। पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद इतनी बड़ी चोरी करने वालों की पतासाजी शुरु की। पुलिस ने चोरी के बाद आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी खंगालने शुरु किए। पुलिस ने शहर में लगे करीब 500 सीसीटीवी फुटेज खंगाले। आखिरकार पुलिस के हाथ चोरी वाली रात के दिन का एक वीडियो लगा। जिसमें चोरों के शरीर में बना एक टैटू था। पुलिस ने टैटू के आधार पर मध्यप्रदेश के सिंगरौली, बैढन, सरई, बरगवा, लामादीह, बांधा, उज्जैनी, देवरी और उत्तरप्रदेश के मिर्जापुर, बनारस, जौनपुर में कैम्प लगाया। इन जगहों पर भी पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले। आखिरकार पुलिस को टेक्नीकल इनपुट के आधार पर सफलता मिली। पुलिस ने इस केस में चोरी करने वाले आरोपियों को धर दबोचा।

तातापानी में मिशन हरियाली पौधारोपण में उमड़े लोग

बलरामपुर। रामानुजगंज के प्रसिद्ध तातापानी तपेश्वर महादेव धाम में शनिवार को पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वन विभाग महिला बाल विकास विभाग जनपद पंचायत और उद्यानिकी विभाग के संयुक्त प्रयास से जिले में विकासखंड स्तरीय पौधारोपण अभियान चलाया गया। इस दौरान मंदिर परिसर के आसपास फलदार और छायादार पौधे लगाए गए। इस मुहिम को लेकर बलरामपुर के डीएफओ अशोक तिवारी ने बताया कि, महतारी वंदन योजना की हितग्राही जितनी भी माताएं बहनें हैं। सभी से एक पौधा मां के नाम लगाने का आग्रह किया गया है। इसके तहत पौधारोपण किया जा रहा है। पूरे जिले में दो लाख से ज्यादा हितग्राही हैं। इसमें कलेक्टर के निर्देश पर विकासखंड स्तरीय कार्यक्रम तय किया गया। बलरामपुर और राजपुर विकासखंड में शनिवार को यह आयोजन किया गया। बलरामपुर में वनों की कटाई से पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है। इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए जगह-जगह पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है।

घर में नल कनेक्शन से तोरनकट्टा एवं मनकी की महिलाएं खुश

महिलाओं को अब नहीं करनी पड़ती पानी के लिए अपनी बारी का इंतजार, ग्रामीणों ने राज्य सरकार का माना आभार

राजनांदगांव। जल जीवन मिशन योजना के तहत ग्राम पंचायत तोरनकट्टा एवं उसके आश्रित ग्राम मनकी में शुद्ध पेयजल मिलने से अब ग्रामीणों की स्थिति पहले की अपेक्षा सुधरने लगी है। हर घर नल कनेक्शन लग जाने से अब महिलाओं को पहले की तरह नल के सामने लाईनें नहीं लगानी पड़ती है। इससे उनकी समय की बचत होती है। वहीं पर्याप्त शुद्ध पेयजल भी मिल रही है। तोरकट्टा ग्राम पंचायत के ग्रामीण अब खुश है, उनके गांव के हर घर में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित हो गयी है। शासन की जनकल्याणकारी योजना जल जीवन मिशन अंतर्गत हर घर-नल कनेक्शन से ग्राम की महिलाएं प्रसन्न है,

अब उन्हें हैंडपंप के सामने लाइन नहीं लगानी पड़ती है।

कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला जल एवं स्वच्छता मिशन श्री संजय अग्रवाल के मार्गदर्शन में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के द्वारा ग्राम तोरनकट्टा एवं मनकी में जल जीवन मिशन के तहत डिस्ट्रीब्यूशन 400-400 मीटर की पाइप लाइन बिछाकर दोनों ग्रामों के लगभग 304 परिवारों को नल से जल की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। ग्राम तोरनकट्टा की सरपंच श्रीमती सेवती साहू ने बताया कि गांव के प्रत्येक घर में सभी को पानी मिल रहा है, जिससे पूरे गांव में खुशहाली का माहौल है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा एक सतत अभियान चलाकर शासन की योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। वार्ड नंबर 11 की श्रीमती तीरथ बाई और वार्ड नंबर 8 की श्रीमती प्रमिला साहू ने सरकार के प्रति कृतज्ञता प्रकट की। उन्होंने बताया कि उन्हें पानी के लिए दूर-दूर तक जाना पड़ता था, पानी के लिए लम्बी लाइन लगाना, बोरिंग एवं कुंआ पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब जल जीवन मिशन से उन्हें घर पर ही नल के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में शुद्ध पानी मिल रहा है, जिससे उनके समय की बचत भी हो रही है।

पेय जल प्रबंधन से जुड़ी सदस्य श्रीमती सीता बाई ने बताया कि हर 3 महीने में जल वाहिनियों द्वारा जल की शुद्धता का परीक्षण एफटीके किट के माध्यम से किया जाता है, ताकि सभी को गुणवत्ता युक्त पेयजल प्राप्त हो सके। स्कूली छात्रा पल्लवी यादव ने कहा कि पहले पानी की समस्या की वजह से स्कूल जाने में देरी होने के साथ ही घर के बाकि कामों में भी देरी होती थी। एक महिला के समय के साथ-साथ उनके पूरे घर वालों के समय का नुकसान होता था, किन्तु योजना के आने के बाद उन सभी के काम समय से पूरे हो रहे है। जिसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार का धन्यवाद भी ज्ञापित किया।

प्रदेश में स्कूलों और शिक्षकों का होगा युक्तियुक्तकरण

■ , सरकार ने हाईकोर्ट में दायर किया कैविएट

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश में स्कूलों व शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण करने जा रही है। इसे लेकर एडवोकेट जनरल के माध्यम से राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में कैविएट दायर किया है, ताकि शासन के निर्णय के खिलाफ न्यायालय में प्रकरण आने पर शासन का भी पक्ष सुना जाए।

दरअसल 2 अगस्त को शिक्षा विभाग ने युक्तियुक्तकरण को लेकर 10 पेज का नियम निर्देश जारी किया है, जिसमें प्रधानपाठक सहित केवल दो शिक्षकों के न्यूनतम सेटअप है। सरकार ने नियम निर्देश जारी करने के साथ ही हाईकोर्ट में कैविएट दायर किया है।

युक्तियुक्तकरण को लेकर जो नियम निर्देश जारी हुए हैं, उससे 10 से 15 हजार शिक्षक प्रभावित होंगे। युक्तियुक्तकरण से कई शिक्षक अतिशेष होंगे तो कुछ स्कूल मर्ज होने की वजह से प्रभावित होंगे। इधर युक्तियुक्तकरण को लेकर शिक्षक संगठनों ने मांग की थी कि पहले प्रमोशन की प्रक्रिया पूरी होगी, उसके बाद युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया किया जाए।

संक्षिप्त समाचार

हर घर तिरंगा के तहत संभाग स्तरीय तिरंगा रैली, स्कूली बच्चों ने निकाली रैली

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव

साय के आह्वान पर हर घर तिरंगा कार्यक्रम की शुरूआत की गई है। इसी कार्यक्रम के तहत शनिवार को रायपुर जिले में संभाग स्तरीय तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में बड़े जोश और उत्साह के साथ लगभग साढ़े चार सौ स्कूली बच्चे शामिल हुए। साथ ही देशभक्ति नारों के साथ रैली निकाली गई। इसमें रैली में शिक्षा विभाग के संयुक्त संचालक राकेश पांडे, जिला शिक्षा अधिकारी विजय खंडेलवाल, सहायक संचालक अजीत सिंह जाट, सहायक संचालक एम मिंज, दानी गर्ल्स स्कूल के प्राचार्य हितेश कुमार दीवान और शिक्षकों ने भी भाग लिया।

कोचिंग सेंटर, स्कूल, शॉपिंग मॉल, हॉस्टल, अस्पतालों का होगा सुरक्षा ऑडिट

रायपुर। पिछले दिनो दिल्ली के कोचिंग सेंटर में हादसे के बाद छत्तीसगढ़ सरकार के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने कोचिंग, स्कूल, हॉस्टल, अस्पताल, शॉपिंग मॉल व शैक्षणिक संस्थानों का एक महीने के भीतर ऑडिट कराने के निर्देश जारी किए हैं। ऑडिट में फायर फाइटिंग सिस्टम, फायर अलार्म आदि का परीक्षण किया जाना है। साथ ही बिल्डिंग सेफ्टी, सीसीटीवी, सुरक्षा स्टाफ सहित अन्य मानकों का बारीकी से पड़ताल किया जाना है। यह ऑडिट नगर-निगम, नगर पालिका व नगर पंचायत क्षेत्रों में किया जाना है। ऑडिट के लिए गठित समिति को एक महीने के भीतर प्रतिवेदन संबंधित निकायों के कमिश्नरों को सौंपा जाना है।

ओला पीड़ित किसानों को मिला 9 लाख का मुआवजा

रायपुर। राज्य शासन द्वारा किसानों को खेती-किसानी में प्राकृतिक रूप से 33 प्रतिशत से अधिक नुकसान होने पर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा दिए जाने का प्रावधान है। इस कड़ी में बिलासपुर जिले के बेलगहना तहसील के 4 गावों के 164 ओला पीड़ित किसानों को 9 लाख रुपए की मुआवजा राशि के चेक का वितरण किया गया है। कलेक्टर श्री अवनीश शरण के निर्देश पर एसडीएम युगल किशोर उर्वशा ने कोनचरा में आयोजित कार्यक्रम में प्रभावित किसानों को मुआवजा राशि के चेक वितरित किए। शेष किसानों को आरटीजीएस के जरिए राशि बैंक खातों में जमा करा दी गई। उल्लेखनीय है कि प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत प्रति हेक्टेयर नुकसान के लिए 8500 रुपए की मुआवजा दी जाती है। 33 प्रतिशत अथवा इससे अधिक नुकसान पर मुआवजा दिए जाने का प्रावधान है।

अग्र सावन उत्सव आज

रायपुर। अग्रवाल सभा के द्वारा रविवार को अग्रसेन धाम छोकरानाला में अग्र सावन उत्सव का आयोजन किया गया है। जिसमें अग्रवाल महिला मंडल, युवती व युवक मंडल के सदस्य शामिल होंगे। इस दौरान कई प्रतियोगिताओं तो आयोजित की जाएंगी साथ ही सावन झूले का भी आनंद अग्रवाल समाज की महिलाएं उठाएंगी। अग्र सावन उत्सव का आयोजन सुबह 11 बजे से शाम को 4 बजे तक किया गया है।

दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिये आईजीकेवी के विक्रम चन्द्रवंशी का चयन

रायपुर। नई दिल्ली के लाल किला परिसर में

15 अगस्त को आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में छत्तीसगढ से 16 स्वंयसेवक चयनित हुए हैं, जिसमे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर से एकमात्र स्वंसेवक विक्रम चंद्रवंशी पिता श्री माखन लाल चंद्रवंशी ग्राम- मोहतरा कला जिला-कबीरधाम का चयन हुआ है। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के अधीन राष्ट्रीय सेवा योजना अन्तर्गत उन्हें स्वतंत्रता दिवस समारोह कार्यक्रम मे शामिल होने हेतू चयन किया है। विक्रम विगत सात वर्षों से राष्ट्रीय सेवा योजना के कर्मठ स्वयं सेवक है। विक्रम को एन. एस. एस. मे जुलाई 2024 मे सी- प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है।

आज दिखेगी आरके किड्स टैलेंट रनवे में बच्चों की प्रतिभा

रायपुर। 77वें स्वतंत्रता दिवस से पहले आरके किड्स टैलेंट रनवे 2024 का आयोजन कल रविवार को एक निजी होटल में होने जा रहा है जहां कैटेगिरी में बच्चे अपनी प्रतिभा का जोहर दिखाएंगे। इस प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के अलावा, ओडिशा, बिहार व महाराष्ट्र के भी प्रतिभागी हिस्सा ले रहे है, इस दौरान 11 दिव्यांगजनों को सम्मानित भी किया जाएगा। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में मुंबई की बॉलीवुड अभिनेत्री और सामाजिक सेविका हेमा शर्मा उपस्थित होंगी। आयोजनकर्ता कविता सोनी ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि आरके किड्स टैलेंट रनवे 2024 में भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व किया जाएगा। प्रतियोगिता को विभिन्न आयु समूहों में विभाजित किया गया है जैसे 3 से 6 साल, 7 से 11 साल, 12 से 16 साल और 17 से 21 साल जहां कविता, नृत्य, फैशन शो, गायन, अभिनय और अन्य प्रतिभाओं का प्रदर्शन 60 से अधिक बच्चे करेंगे।

नक्सलियों से मिली हुई है कांग्रेस, समय-समय पर मिल रहे प्रमाणः बृजमोहन

■ दिल्ली से लौटे सांसद अग्रवाल

रायपुर। संसद सत्र में हिस्सा लेने के बाद सांसद बृजमोहन अग्रवाल शनिवार को राजधानी नई दिल्ली से रायपुर लौटे। पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने ट्रेनों के लेट लतीफी, एयरपोर्ट विस्तार, नक्सली समस्या, बस्तर जनजातीय विवि आदि पर अपने विचार व्यक्त किए। नक्सली समस्या को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस नक्सलियों से मिली हुई है और इसके प्रमाण समय-समय पर आते रहते हैं।

उन्होंने कहा कि पहले विधानसभा का नेता था अब पूरे छत्तीसगढ़ का सेवा करने का मौका मिला है। संसद का अनुभव बहुत अच्छा रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला है। उन्होंने बताया कि सदन में रायपुर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की मुद्दा उठाया। इसके अलावा रेलवे की समस्या और विस्तार का प्रश्न उठाया। इस पर आश्वासन दिया गया है कि बहुत जल्द ही ट्रेन रद्द और लेटलतीफी का समाधान किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में तीसरी पटरी बिछाने का काम चल रहा है इसलिए दिक्कत हो रही है। पहले जिस काम में चार दिन लगता था अब तकनीक का उपयोग करके तीन दिन में करने का आश्वासन दिया गया है। उन्होंने बताया कि रेलवे की लगभग 22 परियोजनाएं चल रही है, रेलवे स्टेशनों का विकास किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के विकास के लिए केंद्र ने 7 हजार करोड़ दिए है। कांग्रेस के समय में तो पांच साल में 300 करोड़ मिलता था।

छत्तीसगढ़ में नक्सली घटना को लेकर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि हमारी नीति स्पष्ट है। कांग्रेस ने पांच साल में जितने नक्सलियों को नहीं मारा उससे ज्यादा हमने छह महीने में मार गिराए है। उन्होंने कहा कि हम तो पहले से कहते रहे हैं कि कांग्रेस नक्सलियों से मिली हुई है। अब गिरफ्तारी भी हो रही है और प्रमाण भी मिल रहे हैं। कांग्रेस नक्सलियों से मिली हुई है इसका प्रमाण समय समय पर आता है।

छत्तीसगढ़ी भाषा आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर सांसद अग्रवाल ने कहा कि अभी सिर्फ दो माह ही हुए है सांसद बने। छत्तीसगढ़ी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल होना चाहिए। ये मांग आगे हम उठाएंगे और शामिल करने की मांग करेंगे।

उन्होंने कहा कि बस्तर में जनजातीय विश्वविद्यालय खोलने की केंद्रीय शिक्षा मंत्री से बात की है। 33 हजार शिक्षक भर्ती को लेकर सांसद अग्रवाल ने कहा अभी तो राज्य सरकार को छह माह ही हुए है। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होगा, आगे भर्ती की जाएगी।

नंदकुमार बघेल के सलाहकार की नक्सलियों के साथ गिरफ्तारी सांसद पांडेय का भूपेश से सवाल- 'बताएं ये रिश्ता क्या कहलाता है'

रायपुर। मोहला-मानपुर पुलिस ने 4 नक्सलियों समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, इनमें से एक विवेक सिंह के दिवंगत नंदकुमार बघेल का सलाहकार होने का आरोप लगाते हुए भाजपा सांसद संतोष पांडेय ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से सवाल किया है कि बताएं यह रिश्ता क्या कहलाता है।

भाजपा सांसद संतोष पांडेय ने मीडिया से चर्चा में कहा कि गिरफ्तार किया गया विवेक सिंह स्वर्गीय नंदकुमार बघेल का सलाहकार रहा है। उसके नक्सलियों के साथ 7 लाख रुपए की लेन-देन की जानकारी भी सामने आई है। इससे स्पष्ट है कि नंदकुमार बघेल के नक्सलियों से संबंध थे। वे मोहला मानपुर के अंदरूनी क्षेत्रों में जाकर बैठकें लेते थे। अब भूपेश बघेल बताएं यह रिश्ता क्या कहलाता है। सांसद संतोष पांडे ने लोकसभा सत्र में रेल के मुद्दे को लेकर कहा कि 18वीं लोकसभा बजट सत्र पोटेंशियल रहा। बजट में सभी क्षेत्रों का ध्यान रखा गया। छत्तीसगढ़ में रेलवे में ही 6 हजार 922 करोड़ का प्रावधान है, जिसके अमृत स्टेशन, ओवर ब्रिज, तीसरा ट्रेक बहुत से निर्माण होंगे।

लोकसभा में बृजमोहन अग्रवाल के सवाल पर कांग्रेस के सवाल उठाने पर संतोष पांडे ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय से 18 गुना ज़्यादा बजट है। कांग्रेस के समय में कुछ भी नहीं था। कम से कम कांग्रेस इस प्रकार की बात ना करे। मनमोहन सरकार के कार्यकाल में सभी रेलवे गति को अवरुद्ध कर दिया था। कांग्रेस सरकार में 5 बजे शाम में पहुँचे वाली ट्रेन अगले दिन पांच बजे पहुंचती थी।

बांग्लादेश की स्थिति कांग्रेस की चुप्पी पर सांसद ने कहा कि हमास ने जब इजराइल पर हमला किया था, तब राहुल गांधी कहाँ थे। जो इसराइल के पक्ष में बोलते वो हमास के पक्ष में बोल रहे थे। हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस के प्रवक्ता हमास के पक्ष में बोलते थे। बांग्लादेश में नरसंहार हुआ, एक शब्द भी संवेदना विपक्ष में नाते नहीं की। सब जान चुके हैं, इसमें किसका हाथ है।

बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किए जाने पर संतोष पांडेय ने कहा कि सब प्रकार की चर्चा हुई है। गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की निगाह है। भारत सरकार पूरी तैयारी में है।

रायपुर की ट्रैफिक व्यवस्था बदहाल एनएसयूआई ने एएसपी को सौंपा ज्ञापन

रायपुर। एनएसयूआई ने रायपुर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर आज मोर्चा खोला। एनएसयूआई के वाइस चेयरमैन पुनेश्वर लहरे ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात के नाम ज्ञापन सौंपकर जल्द कार्यवाही की मांग की है। लहरे ने कहा कि किसी भी शहर को खूबसूरत बनाने मे वहां के यातायात व्यवस्था का मुख्य रोल होता है, लेकिन लोधीपारा ओवरब्रिज से लेकर मोवा थाना चौक तक शहर के कई मार्गों में ट्रैफिक ज्यादा वाहन आने-जाने से हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है। यातायात व्यवस्था सही तरह से न होने से आम नागरिकों को पैदल और बाइक पर निकलना कठिन हो गया है।

ट्रैफिक जाम होने के वजह से आपस में गाड़ी टकराने से लोगों के बीच लड़ाई और दुर्घटना होने की भी संभावना बनी रहती है। यह लगातार विकराल होती जा रही है। कई-कई बार इस भीषण जाम में फंस कर लोग अपने गतव्य तक पहुंचने में लेट हो जाते हैं। स्कूली बच्चों को भी देरी का सामना करना पड़ता है।

उन्होंने कहा कि यातायात व्यवस्था काफी खराब हो चुकी है। शहरवासी राजधानी में लगातार जाम से जूझ रहे हैं। कुछ-कुछ चौक को छोड़ दें तो ज्यादातर

जगहों पर ट्रैफिक जाम होने की वजह से आमजनों को घंटों लाइनों में लगा रहना पड़ता है। एनएसयूआई ने लोधीपारा ओवरब्रिज, दलदल सिवनी मोड़, मोवा थाना चौक आदि जगहों पर ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को तैनात कर यातायात व्यवस्था को सही करने की मांग की है। ओवरब्रिज दलदल सिवनी मोड़ और मोवा थाना चौक में स्थाई रूप से ट्रैफिक लाइट बनाया जाये।

ज्ञापन सौंपने वालों में एनएसयूआई के प्रदेश सचिव मोनू तिवारी, विधानसभा उपाध्यक्ष अंकित बंजारे,धनजय कोशले, तिरुपति राव आदि मौजूद रहे।

साय सरकार की पहल, राज्य के 160 आईटीआई होंगे अपग्रेड

मॉडल आईटीआई के रूप में उन्नयन के लिए 484.22 करोड़ रूपए जारी

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की पहल पर छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोजगार से जोडने के लिए राज्य के 160 आईटीआई को मॉडल आईटीआई के रूप में उन्नयन किया जा रहा है। इसके लिए रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा 484 करोड़ 22 लाख रूपए की स्वीकृति जारी की गई है। मॉडल आइटीआई में उन्नयन के पश्चात युवाओं को स्थानीय उद्योगों की मांग के मुताबिक प्रशिक्षण मिल सकेगा।

राजस्व मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने मॉडल आईटीआई में उन्नयन को राज्य के युवाओं के लिए बड़ी उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की मंशा के अनुरूप राज्य के आईटीआई को मॉडल आईटीआई में अपग्रेड करने की योजना तैयार की गई है। उन्होंने बताया कि योजना के पहले चरण में प्रदेश के 160 आईटीआई के लिए 484.22 करोड़ रूपए का तीन वर्षीय प्रस्ताव स्वीकृत

किया गया है। बलौदाबाजार के सकरी स्थित आईटीआई को मॉडल आईटीआई बनाने का काम जल्द शुरू होगा। इसके लिए सिडबी योजना के तहत 20 करोड़ 13 लाख रुपए की राशि की स्वीकृति जारी की गई है।

राजस्व मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने बताया कि बलौदाबाजार के सकरी शासकीय आई टी आई के विभिन्न ट्रेड का उन्नयन और अधोसंरचना के कार्य किये जाएंगे। शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में मशीन टूल्स और उपकरण के लिए 3 करोड़ 23 लाख रुपए जारी किया गया है। इसमें कंप्यूटर, हार्डवेयर और नेटवर्क मेंटनेंस के लिए 1 करोड़ 5 लाख रूपए, इलेक्ट्रिशियन के लिए 75 लाख रूपए, फीटर के लिए 46 लाख, मेकेनिक डीजल के लिए 44 लाख रूपए और वेल्डर के लिए 53 लाख रूपए शामिल है। इसी तरह सिविल वर्क में आईटीआई के नए भवन निर्माण के लिए 3 करोड़ 44 लाख रूपए, गार्ड रूम के लिए 7 लाख 42 हजार रूपए, मोटर गाडियों के पार्किंग के लिए 1 करोड़ 25 लाख रूपए, स्टाफ क्वार्टर्स निर्माण के लिए 11 करोड़ 78 लाख रूपए तथा प्रवेश द्वार और बाऊण्ड्रीवाल के लिए 34 लाख 80 हजार रूपए की राशि स्वीकृत की गई है।

पं. प्रदीप मिश्रा का शिवमहापुराण कथा आज से

नया रायपुर में करेंगे कथा वाचन, पुलिस ने जारी किया रूट चार्ट

रायपुर। नया रायपुर के ग्राम गनौद-खरखराडीह में 11 से 16 अगस्त तक श्री शिवमहापुराण कथा का आयोजन होगा। कथा सुनने वाले श्रद्धालुओं के सुगम आवागमन के लिए यातायात पुलिस ने ट्रैफिक प्लान बनाया है। इसके साथ ही कथा स्थल पहुंच मार्गों के आस-पास मध्यम और भारी मालवाहक वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।

श्री शिवमहापुराण कथा कार्यक्रम का 11 अगस्त को प्रस्तावित है। जिसमें कथा वाचक पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा कथा वाचन किया जाना है। उक्त कार्यक्रम में भारी संख्या में श्रद्धालुओं के सम्मिलित होने की संभावना है। जिसे देखते हुए सुगम आवागमन के लिए मार्ग, पार्किंग और डायवर्सन की व्यवस्था की गई है।

यातायात पुलिस ने जारी किया रूट चार्ट

रायपुर शहर के पचपेड़ीनाका की ओर से कथा में सम्मिलित होने वाले श्रद्धालु पचपेड़ीनाका-धमतरी रोड-माना बस्ती से होते हुए प्रशासनीक अकादमी निमोरा के आगे से नया

रायपुर-मुक्तांगन-उपरवारा चौक से सेक्टर 29-30 होते हुए आईडीटीआर टर्निंग से ग्राम तेंदुआ होकर ग्राम पौंता से आगे स्थित तालाब पार्किंग में अपना वाहन पार्क कर पैदल कार्यक्रम स्थल में प्रवेश करेंगे।

रायपुर शहर के तेलीबांधा होकर आने वाले श्रद्धालु सेरीखेड़ी ब्रीज से होकर नया रायपुर मार्ग होते हुए विमानतल टर्निंग-चीचा चौंक से ग्राम कयाबांधा-कोटराभाठा चौक होकर पुलिस मुख्यालय के सामने से ग्राम तांदुल स्थित पार्किंग स्थल में अपना वाहन पार्क कर पैदल कार्यक्रम स्थल की ओर प्रेवश करेंगे।

आरंग की ओर से कथा में सम्मिलित होने आने वाले श्रद्धालु नयापारा-आरंग मार्ग से ग्राम तामासिवनी से ग्राम बिरबिरा होते हुए ग्राम खरखराडीह होकर गनौद पेट्रोल पम्प के बगल पार्किंग में अपना वाहन पार्क कर पैदल कार्यक्रम स्थल में प्रवेश करेंगे।

मंदिर हसौद की ओर से आने वाले श्रद्धालु ग्राम पलौद से प्रवेश कर कलिंगा युनिवर्सिटी से आगे बढ़कर शास.उच्च.मा.शाला गनौद पार्किंग में अपना वाहन पार्क कर पैदल कार्यक्रम स्थल में प्रवेश करेंगे।

अभनपुर की ओर से आने वाले श्रद्धालु मोंटफोर्ड स्कूल के सामने से नया रायपुर प्रवेश कर सेक्टर 29 एवं 30 से होते हुए आईडीटीआर टर्निंग से ग्राम तेंदुआ होकर ग्राम पौंता से आगे स्थित तालाब पार्किंग में अपना वाहन पार्क कर पैदल कार्यक्रम स्थल में प्रवेश करेंगे।

राजिम-गरियाबंद की ओर से आने वाले श्रद्धालु गोबरा नयापारा से नवागांव होकर नया रायपुर मार्ग से ग्राम सुन्दरकेरा-खंडवा होते हुए बालकों अस्पताल के सामने से सेक्टर 29 एवं 30 होते हुए आईडीटीआर टर्निंग से ग्राम तेंदुआ होकर ग्राम पौंता से आगे स्थित तालाब पार्किंग में अपना वाहन पार्क कर पैदल कार्यक्रम स्थल में प्रवेश करेंगे।

बलौदाबाजार में फैला डायरिया, 40 से अधिक बीमार, अब जागा स्वास्थ्य विभाग

डायरिया के प्रकोप से गांव में पसरा सन्नाटा

बलौदाबाजार। बलौदाबाजार जिले में लगातार डायरिया फैलने से स्वास्थ्य विभाग परेशान नजर आ रहा है। कलेक्टर दीपक सोनी ने स्वास्थ्य विभाग को लगातार मुस्तैद रहने कहा है। ताजा मामला करमदा का आया है, जहां अचानक बीती शाम से लोगों को उल्टी दस्त की शिकायत हुई और देखते ही देखते 40 से अधिक लोग बीमार हो गए। इसको लेकर स्वास्थ्य अमला गांव में ही कैंप लगाकर ईलाज कर रहे हैं। 10 से अधिक मरीज को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। डायरिया के प्रकोप से गांव में सन्नाटा पसर गया है।

गांव वालों ने बताया कि नलजल योजना के तहत, जो पानी सप्लाई हो रहा है उसका पाइप जगह जगह से लीकेज है और यही गंदा पानी लोगों ने पीया है, जिसके बाद गांव के सभी बोर बंद कर दिए गए है। पानी टैंकर से गांव में पानी सप्लाई की जा रही है।

डॉ. अभिजीत बैनर्जी ने बताया कि बीती शाम से डायरिया के मरीज आ रहे सभी का गांव में कैंप लगाकर ईलाज कर रहे हैं। पर्याप्त मात्रा में दवाईयां उपलब्ध है और स्थिति नियंत्रण में है। लगभग नौ मरीजों को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। लोगों को उबालकर पानी पीने की सलाह दी जा रही है।

कोटवार के माध्यम से मुनादी भी करवाई जा रही है। डॉ. बैनर्जी ने कहा कि मैं जिले के सभी गांव वालों से अपील करूंगा कि सफाई बरते और पानी उबालकर पीएं साथ ही यदि उल्टी दस्त हो तो शासकीय चिकित्सा विभाग से संपर्क करें।

एनआईटी रायपुर और एमएनएनआईटी इलाहाबाद के इनक्यूबेशन केंद्रों के बीच एमओयू

■ इनक्यूबेशन संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए हुआ समझौता

रायपुर। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) रायपुर हमेशा से ही नवाचार, उद्यमिता और स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध रहा है। इसी तर्ज पर, संस्थान ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशन (निधि)- टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर (टीबीआई) कार्यक्रम के तहत स्टार्टअप्स को समर्थन और सलाह देने के लिए एनआईटी रायपुर फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप नाम से एक गैर-लाभकारी टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर कंपनी की स्थापना की है।

मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद (एमएनएनआईटी इलाहाबाद) ने इनोवेशन एंड इनक्यूबेशन हब एमएनएनआईटी फाउंडेशन (आईआईएचएमएफ) के नाम से कंपनी अधिनियम

2013 की धारा-8 के तहत एक गैर-लाभकारी कंपनी की स्थापना की है, जिसका उद्देश्य नवाचार, उद्यमिता विकास, स्टार्टअप इनक्यूबेशन, उद्योग सहयोग और नेटवर्किंग को बढ़ावा देना है। एनआईटीआरआरएफआईई ने 9 अगस्त 2024 को आईआईएचएमएफ के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए, जिसका मुख्य उद्देश्य सह-इनक्यूबेशन, साझा बुनियादी ढांचे के संसाधनों और संयुक्त मेंटरशिप प्रदान करके इनक्यूबेशन संबंधी गतिविधियों और तकनीक आधारित स्टार्टअप्स का समर्थन करना है, जिससे इनक्यूबेशन प्रक्रिया को समृद्ध किया जा सके। इस एमओयू के तहत, दोनों इनक्यूबेशन केंद्र नवाचार, उद्यमिता और इनक्यूबेशन गतिविधियों के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए जानकारी, ज्ञान, सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान और संयुक्त रूप से संगोष्ठियों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं और प्रौद्योगिकी-चालित स्टार्टअप्स/उद्यमियों के लिए विषयों पर कार्यक्रमों का आयोजन करने पर सहमत हुए हैं।

एमओयू पर एनआईटीआरआरएफआईई के बोर्ड निदेशक डॉ. समीर बाजपेई और आईआईएचएमएफ के बोर्ड निदेशक डॉ. अनुभव रावत ने एनआईटी रायपुर के निदेशक डॉ. एन. वी. रमना राव और एमएनएनआईटी इलाहाबाद के प्रोफेसर डॉ. अनिमेष कुमार ओझा की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर डॉ. आर. के. त्रिपाठी, डीन (योजना एवं विकास), एनआईटी रायपुर के संकाय प्रभारी इनक्यूबेशन सेल और एनआईटीआरआरएफआईई के अंतरिम सीईओ डॉ. अनुज के. शुक्ला और एनआईटी रायपुर के सहायक कुलसचिव और एनआईटीआरआरएफआईई के अंतरिम प्रबंधक श्री पवन कटारिया भी उपस्थित थे। इस एमओयू पर हस्ताक्षर दोनों संस्थानों की नवाचार, उद्यमिता, इनक्यूबेशन और उद्योग सहयोग में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। यह रणनीतिक साझेदारी दोनों इनक्यूबेशन केंद्रों की वृद्धि और विकास में योगदान करेगी, जिससे स्टार्टअप्स, इनक्यूबीज, छात्र, संकाय और व्यापक उद्योग को लाभ मिलेगा।

तख्तापलट का दंश पाकिस्तान भी झेल चुका है

मरिआना बाबर

जुलाई, 2022 की एक बेहद दिलचस्प तस्वीर है, जिसमें श्रीलंका के प्रदर्शनकारी वहां के तत्कालीन राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के देश छोड़कर भाग जाने के बाद कोलंबो स्थित राष्ट्रपति निवास के स्वीमिंग पूल में तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने बाद में राष्ट्रपति भवन को लूटने के बाद उसमें आग भी लगा दी थी। इस हफ्ते दुनिया ने देखा कि किस तरह बांग्लादेशी छात्रों ने अन्य प्रदर्शनकारियों के साथ मिलकर तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना के आधिकारिक आवास पर धावा बोल दिया और वहां काफी लूटपाट की। हालांकि तब तक वह मुल्क छोड़कर भारत भाग चुकी थीं। तस्वीरों में प्रदर्शनकारी उनके बिस्तर पर भी दिखाई दे रहे हैं, जबकि कुछ अन्य लोग रसोईघर में घुसकर जो भी मिला, उसे खाते दिखे। क्या दक्षिण एशिया के इस क्षेत्र में तीसरी बार भी ऐसी घटना होगी? क्या अगला नंबर पाकिस्तान का है? यह सवाल पूर्व मंत्री और सांसद सैयद मुशाहिद हुसैन ने पूछा, जो पीएमएल (एन) के सदस्य हैं और कई दशक पहले ढाका में रह चुके हैं। मुशाहिद हुसैन यह सवाल इसलिए पूछ रहे हैं, क्योंकि इस समय पाकिस्तान में भी कई आंदोलन चल रहे हैं। पिछले एक हफ्ते से ज्यादा समय से रावलपिंडी शहर के मुख्य केंद्र मुर्री रोड पर सड़क को बंद करके जमात-ए इस्लामी का धरना चल रहा है, जहां हजारों लोग बैठे हैं और मांग कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ सरकार बेरोजगारी, मुद्रास्फीति का तत्काल समाधान करे और विशेष रूप से नागरिकों के बिजली बिलों में वृद्धि को कम करे। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे जमात-ए इस्लामी के नवनिर्वाचित प्रमुख हाफिज नईमुर्रहमान ने शहबाज शरीफ को चेतावनी दी कि यदि वह उनकी पार्टी की मांगें नहीं मानेंगे, तो उनका हश्र शेख हसीना से भी बुरा होगा, क्योंकि उन्हें मुल्क छोड़ने की इजाजत भी नहीं दी जाएगी। इस बीच बलूचिस्तान के एकमात्र बंदरगाह शहर ग्वादर सहित कई अन्य शहरों में पिछले दो हफ्ते से धरना-प्रदर्शन जारी है। रावलपिंडी के विरोध प्रदर्शन के विपरीत बलूचिस्तान में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें भी देखी गई हैं, जहां गोलीबारी में कई लोग मारे गए, दर्जनों घायल हुए और कई लोगों को सरकारी एजेंसियों द्वारा उठा लिया गया। इन विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व एक युवा बलोच महिला डॉ. महरंग बलोच कर रही हैं, जो मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। उन्होंने उस पुरानी बलोच परंपरा को तोड़ा है, जिसमें महिलाओं को घरों तक ही सीमित रखा जाता था। वह अब नागरिक अधिकारों की मांग करने वाले हजारों पुरुष एवं महिलाओं का नेतृत्व कर रही हैं। हजारों बलोच नागरिक मांग कर रहे हैं कि पुरुषों को लगातार सरकारी एजेंसियों द्वारा उठाकर गायब किया जाना हमेशा के लिए बंद हो। गौरतलब है कि उठाकर गायब किए जाने वाले लोगों में ज्यादातर युवा हैं। वे यह भी मांग कर रहे हैं कि सभी चेकपोस्ट हटा लिए जाएं, ताकि लोग आसानी से आ-जा सकें। इसके अलावा बलोच प्रदर्शनकारियों की सबसे महत्वपूर्ण मांग है कि बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधन उन्हें उपलब्ध कराए जाएं, न कि दूसरे प्रांतों को भेजे या निर्यात किए जाएं। इस बीच उत्तरी इलाकों में भी लोग कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्होंने काराकोरम हाईवे को जाम कर दिया है, जो खुंजराब दर्रे के माध्यम से पाकिस्तान को चीन से जोड़ रहा है। वे संघीय राजस्व बोर्ड और पाकिस्तान सीमा शुल्क के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, जिन्होंने हाल ही में व्यापारियों पर कर लगाया है। पाकिस्तान से चीन जाने के इच्छुक कई विदेशी भी यहां फंस गए हैं और उन्हें प्रदर्शनकारियों के साथ बैठे देखा जा सकता है। इस तरह से देखा जा सकता है कि पाकिस्तान के हर हिस्से में विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। बांग्लादेश में जारी घटनाएं इस क्षेत्र एवं पश्चिम में अब भी सुर्खियों में हैं। इसलिए पाकिस्तान में यह सवाल पूछा जा रहा है कि क्यों कई मुस्लिम देश गंभीर राजनीतिक अस्थिरता का सामना कर रहे हैं। सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल तलत मसूद कहते हैं, %ऐसा इसलिए है, क्योंकि वे सत्ता बरकरार रखने के लिए लोगों से शक्ति प्राप्त करने के बजाय सेना या सुरक्षा संगठनों पर ज्यादा निर्भर हैं। इससे उनकी प्रगति में बाधा आई है और वे महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले लेने के लिए प्रमुख वैश्विक शक्तियों पर ज्यादा निर्भर हो गए हैं।

जमीन कब्जाने वालों पर शिकंजा कसने की तैयारी

संजय सक्सेना

वक्फ और वक्फ की संपत्तियों को लेकर हिंदुस्तान में अक्सर सही-गलत चर्चा होती रहती है। हममें से अधिकांश लोगों ने वक्फ का नाम तो सुना है, लेकिन वह इसके बारे में बहुत कुछ जानते नहीं हैं। वक्फ होता क्या है। किसी मस्जिद या दूसरे धर्मस्थल के वक्फ होने का मतलब क्या है? और क्या मोदी सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड के संविधान में तब्दीली की कोशिशों का असर मुस्लिम धर्मस्थलों के स्टेटस पर पड़ सकता है? चूंकि भारत में रेलवे और रक्षा मंत्रालय के बाद सबसे बड़ा भूस्वामी वक्फ बोर्ड ही है। इसलिए हम इन सारे सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यह जान लेना जरूरी है कि भारत में इस्लाम की आमद के साथ वक्फ के उदाहरण मिलने लगे थे। दिल्ली सल्तनत के वक्त से वक्फ संपत्तियों का लिखित जिक्र मिलने लगता है। मुगल शासन काल में क्योंकि ज्यादातर संपत्ति राजा महाराजाओं के पास ही होती थी, इसीलिए प्राय: वही वाकिफ होते, और वक्फ कायम करते जाते। जैसे कई बादशाहों ने मस्जिदें बनवाईं, वो सारी वक्फ हुईं और उनके प्रबंधन के लिए स्थानीय स्तर पर ही इंतजामिया कमेटियां बनती रहीं।

इसके पश्चात 1947 में आजादी के बाद पूरे देश में पसरी वक्फ संपत्तियों के लिए एक स्ट्रक्चर बनाने की बात उठने लगी। इस तरह 1954 में संसद ने वक्फ एक्ट 1954 पास किया। इसी के नतीजे में वक्फ बोर्ड बना। ये एक ट्रस्ट था, जिसके तहत सारी वक्फ संपत्तियां आ गईं। 1955 में यानी कानून लागू होने के एक साल बाद, इस कानून में संशोधन कर राज्यों के लेवल पर वक्फ बोर्ड बनाने का प्रावधान किया गया। इसके बाद साल 1995 में नया वक्फ बोर्ड एक्ट आया। 2013 में मनमोहन सरकार के समय इसमें कई संशोधन करके इसे पूरी तरह से तानाशाही रूप दे दिया गया। फिलहाल जो व्यवस्था है, वो इन्हीं कानूनों और संशोधनों के तहत चल रही है, इसमें सबसे खतरनाक संशोधन यह था कि वक्फ बोर्ड जिस किसी सम्पति को अपना बता दे तो फिर वह उसकी बिना किसी जांच पड़ताल के हो जाती है और जिसकी सम्पति छीनी जाती है,वह कोर्ट या पुलिस के पास भी

अपनी फरियाद लेकर नहीं जा सकता है। प्राय: मुस्लिम धर्मस्थल वक्फ बोर्ड एक्ट के तहत ही आते हैं। लेकिन इसके अपवाद भी हैं। जैसे ये कानून अजमेर शरीफ दरगाह पर लागू नहीं होता। इस दरगाह के प्रबंधन के लिए दरगाह ख्वाजा साहिब एक्ट 1955 बना हुआ है।

वक्फ बोर्ड को मिली असीमित शक्तियों पर अंकुश लगाने और बेहतर प्रबंधन व पारदर्शिता के लिए मोदी सरकार ने आठ अगस्त 2024 को लोकसभा में दो विधेयक पेश किये। पहले विधेयक के जरिये सरकार मुसलमान वक्फ अधिनियम 1923 को समाप्त करने को कटिबद्ध लगती है, जबकि दूसरे से मुसलमान वक्फ अधिनियम 1995 में 44 संशोधन किए जाएंगे। सरकार इस विधेयक में बोहरा-आगाखानी के लिए अलग वक्फ बोर्ड का प्रावधान करेगी और किसी की संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित करने के अधिकार से संबंधित धारा 40 को समाप्त कर देगी।

मोदी सरकार ने वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक संसद में पेश करने से एक दिन पहले कहा कि विधेयक लाने का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन और संचालन करना है। विधेयक पेश किए जाने के बाद सरकार ने इसे व्यापक विमर्श और सर्वसम्मति के लिए प्रवर समिति को भेज दिया है। दूसरे विधेयक में वक्फ अधिनियम 1995 का नाम बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता विकास अधिनियम करने का प्रावधान है। इसमें वक्फ बोर्डों के केंद्रीय परिषद और ट्रिब्यूनल की संरचना में व्यापक बदलाव लाने का भी प्रावधान है। मसलन केंद्रीय परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड में दो महिलाओं का प्रतिनिधित्व अनिवार्य बनाया जाएगा। इसके अलावा कानून में संशोधन के बाद अब वक्फ ट्रिब्यूनल के आदेश को 90 दिन के अंदर हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकेगी। वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण के लिए सर्वे कमिश्नर का अधिकार अब जिला कलेक्टर या उसके की ओर से नामित डिप्टी कलेक्टर के पास होगा।

विधेयक की खास बातों पर नजर डाली जाए तो मोदी सरकार वक्फ अधिनियम, 1923 को वापस लेगी। पारदर्शिता, बेहतर प्रबंधन और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए 44 संशोधन किये जायेंगे। जिसके द्वारा आगाखानी व बोहरा वक्फ को परिभाषित किया जाएगा। पांच साल तक मुस्लिम धर्म का पालन करने वालों की संपत्ति वक्फ हासिल कर सकेगा। वक्फ के धन से विधवा, तलाकशुदा व अनाथों के कल्याण के लिए सरकार के सुझाए तरीके से काम करने होंगे। संपत्ति वक्फ को देने के दौरान उत्तराधिकारियों और महिलाओं के अधिकार नहीं छीने जा सकेंगे। वहीं रजिस्टर्ड वक्फ संपत्तियों को 6 माह में पोर्टल पर डालना होगा। वक्फ संपत्तियों से मिलने वाले भू राजस्व, सेस, उसका रेट, कर, आय, कोर्ट मामले की जानकारी भी बतानी होगी।सरकारी संपत्ति को वक्फ अपनी संपत्ति घोषित नहीं कर पाएगा

वक्फ बोर्ड में जो बदलाव होंगे उसके अनुसार मुसलमान वक्फ कानून 1923 खत्म होगा। वक्फ अधिनियम होगा एकीकृत वक्फ प्रबंधन कानून, धारा 40 होगी खत्म, जिससे किसी की संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित करने का अधिकार मिल जाता है। दरअसल, केंद्र की मोदी सरकार यूपीए-2 में मनमोहन सिंह सरकार ने 2013 में वक्फ अधिनियम में संशोधन कर वक्फ बोर्ड को किसी की भी संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित करने और वक्फ बोर्ड के निर्णयों को किसी भी कोर्ट में चुनौती देने का अधिकार खत्म करने जैसे बदलाव किए गए थे।

सरकारी सूत्रों के अनुसार तब से मुस्लिम समाज से जुड़े व्यक्तियों व संगठनों की करीब 60 हजार शिकायतें सरकार के पास लंबित हैं। इन सभी शिकायतों में वक्फ बोर्ड में भारी अनियमितता व जबरन संपत्ति पर कब्जा जैसी समान बातें थीं। संशोधन विधेयक में वक्फ परिषद में भी बदलाव का प्रावधान है। मसलन परिषद के अध्यक्ष अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री होंगे।तीन सांसद, मुसलमानों के तीन प्रतिनिधि, मुस्लिम कानून के तीन जानकार, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के दो पूर्व जज, एक वरिष्ठ वकील, देश की चार नामचीन हस्तियां व केंद्र सरकार के अतिरिक्त या संयुक्त स्तर के अधिकारी व दो महिलाएं इसकी सदस्य होंगी।

उधर, विपक्षी दलों ने बिल पेश होने से पहले ही सरकार से आग्रह किया कि वक्फ (संशोधन) विधेयक को पेश किये जाने के बाद इस पर विचार करने के लिए संसद की स्थायी समिति को भेजा जाए। वहीं सरकार ने कहा कि कार्य मंत्रणा समिति (बीएसी) की भावना का आकलन करने के बाद वह इस पर फैसला करेगी। इसी क्रम में मोदी सरकार ने बहुचर्चित वक्फ अधिनियम में संशोधन वाला विधेयक लोकसभा में पेश करने के बाद विपक्ष की मांग पर ध्यान देते हुए उसे संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने का जो फैसला लिया, वह इस दृष्टि से सही कदम है, क्योंकि इस समिति में उस पर विस्तार से और संभवत: दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विचार हो सकेगा। इससे सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि विपक्ष के पास यह बहाना नहीं रह जाएगा कि सरकार ने एक महत्वपूर्ण विधेयक बिना बहस आनन-फानन पारित करा लिया और उसकी कोई बात नहीं सुनी गई।

ध्यान रहे कि मोदी सरकार के पहले और दूसरे कार्यकाल में अनेक विधेयकों के संसद से पारित होने और उनके कानून में परिवर्तित हो जाने के बाद विपक्ष ने यह माहौल बनाया कि उन पर संसद में चर्चा नहीं होने दी गई। ऐसे कुछ कानूनों को लेकर जनता को बरगलाने का भी काम किया गया। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए और फिर कृषि संबंधी तीन कानूनों को लेकर विपक्ष ने अपने संकीर्ण राजनीतिक हितों के लिए किस तरह जनता को गुमराह किया। देखना है कि शीघ्र गठित होने वाली संयुक्त संसदीय समिति वक्फ संशोधन अधिनियम पर किस तरह विचार करती है और वह कोई आम सहमति कायम कर पाती है या नहीं यह अब यक्ष प्रश्न होगा।

पुराण दिग्दर्शन .... परिचयाध्याय

अविशिष्ट-क्रम (भाग-7)

गतांक से आगे...

श्री वैङ्कटेश्वर प्रेस बम्बई में मुद्रित भविष्यपुराण की प्रति में उपयुक्त लक्षण प्राय: घटित नहीं होता। पद्यसंख्या का भी बिलकुल मेल नहीं। हो सकता है कि इसमें कुछ अंश असली भविष्यपुराण का सम्मिलित हो, तथापि यह प्राय: उपेक्षणीय है। खासकर प्रतिसर्ग पर्व तो सर्वथा अमान्य है। हमें कहते हुए दु:ख होता है कि आपस्तम्बधर्मसूत्र (2। 24 । 5-6) आदि प्राचीन ग्रन्थों में जिस भविष्यपुराण%का ससम्मान उल्लेख मिलता है वह महामहिम उपयोगी ग्रन्थ आज अदृश्य हो रहा है।

12-ब्रह्मवैवर्त पुराण- जिस ग्रन्थ में सावर्ण ने नारद के प्रति रथन्तर कल्प के वृत्तान्त को लक्ष्य करके कृष्ण भगवान् का उत्तम माहात्म्य, और ब्रह्मा वराह का विस्तृत चरित्र वर्णन किया है, वह ब्रह्म-वैवर्त संज्ञा वाला पुराण है, जिसकी पद्यसंख्या अठारह हजार है। आनन्दाश्रम पूना में मुद्रित ब्रह्म-वैवर्त में तो यह लक्षण घटित नहीं होता, पद्यसंख्या की भी प्राय: यही दशा है। तथापि इसका अधिकांश असली ब्रह्मवैवर्त का अंग ही जान पड़ता है, कुछ अंश रूपान्तर प्राप्त एवं पश्चात्प्रक्षिप्त भी है। खासकर गणेशखण्ड तो प्रत्यक्ष ही अधूरा जान पड़ता है ।

13-मार्कण्डेय-पुराण-जिस ग्रन्थ में धर्म और अधर्म के विचारक पक्षियों के प्रसङ्ग से धर्माचरणयुक्त मुनियों ने अनेक प्रश्नोत्तर किये हों और उसी वृत्तान्त को मार्कण्डेयजी ने विस्तार पूर्वक सुनाया हो वही मार्कण्डेयपुराण है। इसकी श्लोक संख्या नौ हजार है।

उपलब्ध मार्कण्डेय पुराण में उपर्युक्त लक्षण सर्वथा घटित होता है। पद्यसंख्या इस समय 7 हजार के लगभग है। मुद्रित पुराण नरिष्यन्त के चरित पर समाप्त हो जाता है, परन्तु नारदपुराण की सूची के अनुसार यह पुराण इक्ष्वाकु से कुशपर्यन्त और पुरुरवा से श्रीकृष्ण चरित्र तक विशिष्ट वर्णन करके अन्त में मार्कण्डेय चरित पर समाप्त होना चाहिए। **क्रमश: ...**

नई पीढ़ी के लिए हमेशा प्रेरणा देता रहेगा शहीद खुदीराम बोस का व्यक्तित्व

युद्धवीर सिंह लांबा

'आओ झुक कर सलाम करें उनको, जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है, खुशनसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है। ये पंक्तियाँ अक्सर उन स्वतंत्रता सेनानियों के लिए गुनगुनायी जाती रही हैं जिन्होंने खुद को देश के लिए कुर्बान कर दिया। जंग-ए-आजादी की लड़ाई में कूदने वाले आजादी के मतवालों ने देश को अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने में जो भूमिका निभाई है उसे भुलाया नहीं जा सकता। देश की आन-बान और शान के लिए हंसते-हंसते अपने प्राण की बाजी लगाने वाले अमर शहीदों की कुर्बानियों के कारण ही हम आजादी की सांस ले रहे हैं। शहीदों के बलिदान को याद न रखने वाली कौम नष्ट हो जाती है। देश को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराने के लिए लाखों क्रांतिकारियों ने शहादत दी, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, कितने सपूतों ने हंसते हंसते मौत को गले लगा लिया।

इतिहास के पन्नों में भारत की आजादी के लिए अंग्रेजों से लोहा लेने वाले देशभक्त क्रांतिकारियों के बलिदान की शौर्यगाथाएं भरी पड़ी हैं। ऐसा ही एक नाम है खुदीराम बोस, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई में महज 18 साल की छोटी-सी उम्र में फांसी का फंदा चूम लिया था। देश की आजादी के लिए 18 साल की उम्र में फांसी के फंदे पर चढ़ने वाले स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस की आज 11 अगस्त को पुण्यतिथि है। भारत के स्वातंत्र्य संग्राम के इतिहास में खुदीराम बोस का नाम अमिट है। देश की बलिवेदी पर अपने प्राणों की आहूति देने वाले अमर शहीद खुदीराम बोस में वतन के लिए मर मिटने का जज्बा कुछ ऐसा था जो भावी पीढ़ी को सदैव देशहित के लिए त्याग, सेवा और कुर्बानी की प्रेरणा देता रहेगा।

बंगाल में उभरते हुए राष्ट्रीय आन्दोलन को नष्ट करने के लिए 16 अक्टूबर 1905 को लार्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। 1905 में हुए बंगाल विभाजन के बाद तो खुदीराम बोस क्रांतिकारी सत्येन बोस की अगुवाई में क्रांतिकारी बन गए। 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में चले आंदोलन में भी खुदीराम बोस ने बढ़-चढ़ कर भाग लिया। पुलिस ने 28 फरवरी, 1906 को सोनार बंगला नामक एक इश्तहार बांटते हुए खुदीराम बोस को दबोच लिया। लेकिन वह पुलिस के शिकंजे से भागने में सफल रहे।

11 अगस्त, 1908 को सुबह 6 बजे हाथ में गीता लेकर खुदीराम बोस हंसते-हंसते फांसी पर झूल गए। तब उनकी आयु मात्र 18 साल 8 महीने और 8 दिन थी। महान क्रांतिकारी खुदीराम बोस की शहादत के बाद देश में देशभक्ति की लहर उमड़ पड़ी। खुदीराम बोस देश युवाओं के लिए अनुकरणीय हो गए। भारत के कई जाने माने इतिहासकारों ने शहीद खुदीराम बोस को देश को आजाद कराने के लिए हंसते-हंसते अपनी जान देश के खातिर कुर्बान करने वाला सबसे कम उम्र का क्रांतिकारी माना है। सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि आज भौतिकवाद की चकाचौंध में हिन्दुस्तान के लोग धीरे-धीरे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को भूलते जा रहे हैं।

ढाका यूनिवर्सिटी के दो छात्र ने पलट दी बांग्लादेश की सत्ता

नीरज कुमार दुबे

नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में कामकाज संभाल लिया है। हिंसा और अराजकता की स्थिति से जूझ रहे बांग्लादेश को वापस पटरी पर लाना उनके लिए बड़ी चुनौती है। साथ ही जल्द ही चुनाव करा कर नई सरकार को कामकाज सौंपना भी उनके लिए बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य है। देखना होगा कि वह कितने सफल हो पाते हैं। वैसे शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद उपजी परिस्थितियों को देखते हुए बांग्लादेश को फिर से अपने पैरों पर खड़ा करने का भार सिर्फ मोहम्मद यूनुस ही नहीं बल्कि उनकी 16 सदस्यीय सलाहकार परिषद के कंधों पर भी है। हम आपको बता दें कि इस सलाहकार परिषद में छात्र आंदोलन के दो प्रमुख चेहरे मोहम्मद नाहिद इस्लाम और आसिफ महमूद भी शामिल हैं। इसके अलावा सलाहकार परिषद में महिला अधिकार कार्यकर्ता फरीदा अख्तर, दक्षिणपंथी पार्टी हिफाजत-ए-इस्लाम के उप प्रमुख एएफएम खालिद हुसैन, ग्रामीण दूरसंचार ट्रस्टी नूरजहां बेगम, स्वतंत्रता सेनानी शर्मीन मुर्शिद, चटगांव हिल ट्रैक्ट्स डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष सुप्रदीप चकमा, प्रोफेसर बिधान रंजन रॉय और पूर्व विदेश सचिव तौहीद हुसैन शामिल किये गये हैं। हम आपको बता दें कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार एक निश्चित अवधि के लिए देश का नेतृत्व करेगी और निर्वाचित सरकार को सत्ता हस्तांतरित करने के लिए चुनाव की देखरेख करेगी।

देखा जाये तो अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के सहयोग के लिए बनाई गयी यह सलाहकार परिषद एक तरह से बांग्लादेश की नई कैबिनेट के रूप में काम करेगी। इस सलाहकार परिषद में वैसे तो एक से बढ़कर एक अनुभवी लोग शामिल किये गये हैं लेकिन इसमें दो नाम ऐसे हैं जिन्हें प्रशासनिक कामकाज का कोई अनुभव नहीं है और शायद पिछले सप्ताह तक उन दोनों ने सोचा भी नहीं होगा कि वह जल्द ही सरकार चलाने वाली टीम में शामिल हो जाएंगे। हम बात कर रहे हैं छात्र नेताओं- मोहम्मद नाहिद इस्लाम और आफिस महमूद की।

26-वर्षीय इन दोनों युवाओं ने अंतरिम सरकार के सबसे कम उम्र के सलाहकारों के रूप में जब शपथ ली तो एक नया रिकॉर्ड बन गया। हम आपको बता दें कि यह सलाहकार पद मंत्री पद के समकक्ष है और बांग्लादेश में इससे पहले कभी इतनी कम उम्र के मंत्री नहीं रहे। हम आपको बता दें कि जब 1 जुलाई को आरक्षण विरोधी आंदोलन शुरू हुआ था तब नाहिद इस्लाम और आसिफ महमूद ढाका विश्वविद्यालय के साधारण छात्र मात्र थे। इन दोनों छात्रों ने कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर उस आंदोलन को आगे बढ़ाने और उसे पूरे देश में फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। धीरे-धीरे छात्रों का आंदोलन जन विद्रोह में बदल गया और शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने और 5 अगस्त को देश से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा था।

विरोध प्रदर्शन के दौरान, इन दोनों छात्र नेताओं ने तमाम यातनाएं सहन कीं लेकिन सिर झुकाने या अधिकारों की

लड़ाई से पीछे हटने से इंकार कर दिया था। इन दोनों छात्रों की ओर लोगों का ध्यान तब आकर्षित हुआ जब कोटा सुधार आंदोलन को दबाने के लिए हसीना सरकार द्वारा लगाए गए कर्फ्यू के पहले दौर के दौरान उन्हें पुलिस द्वारा उठा लिया गया था। मीडिया रिपोर्टों में बताया गया है कि कैसे उन्हें प्रताड़ित किया गया और बाद में सड़क किनारे छोड़ दिया गया। बताया जाता है कि बाद में डिटेक्टिव ब्रांच (डीबी) के सदस्यों ने चार अन्य छात्र समन्वयकों के साथ इन दोनों छात्र नेताओं को तब फिर से उठाया, जब उनका राजधानी के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था। लेकिन तब भी पीछे हटने के बजाय, उन्होंने अन्य छात्र नेताओं की अन्यायपूर्ण गिरफ्तारी और देश भर में छात्रों पर क्रूर कार्रवाई के विरोध में 30 जुलाई को डीबी कार्यालय पर ही भूख हड़ताल शुरू कर दी थी।

हसीना सरकार ने इन छात्र नेताओं को हिरासत में रखने के दौरान इन पर दबाव बढ़ाया और इनसे एक वीडियो जारी करवाया जिसमें नाहिद और आसिफ सहित छह समन्वयकों ने छात्र आंदोलन को वापस लेने की घोषणा की। लेकिन वहां से रिहा होते ही उन्होंने बताया कि उन पर दबाव बनाकर यह वीडियो बनवाया गया था। इन छात्र नेताओं ने आंदोलन को जारी रखने की कसम खाई। उनकी दृढ़ता रंग लाई क्योंकि आंदोलन से जल्द ही जनता भी जुड़ गयी। बाद में आंदोलन के खिलाफ बढ़ती पुलिस की क्रूरता को देखते हुए छात्र नेताओं ने शेख हसीना के इस्तीफे की एक सूत्रीय मांग की घोषणा की, जिसने अंतत: अवामी लीग के शासन को समाप्त कर दिया।

इस तरह भेदभाव के खिलाफ लड़ाई शुरू करने वाले दो छात्र एक महीने में ही अंतरिम सरकार में सलाहकार बन गए। हम आपको बता दें कि नाहिद ढाका विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के स्नातकोत्तर छात्र हैं। उन्होंने 2016-2017 सत्र में विश्वविद्यालय में दाखिला लिया था। वह गणोतांत्रिक छात्र शक्ति (डीयू इकाई) के सदस्य सचिव भी हैं, जो नुरुल हक नूर के नेतृत्व में छात्र अधिकार परिषद से अलग हुए सदस्यों द्वारा गठित एक समूह है। इसके अलावा आसिफ ढाका विश्वविद्यालय में भाषा विज्ञान के छात्र हैं। नाहिद का करीबी सहयोगी, आसिफ गणोतांत्रिक छात्र शक्ति के संयोजक के रूप में कार्य करता है।

सलाहकार के रूप में शपथ लेने के बाद, नाहिद और आसिफ, दोनों ने कहा कि वे लोगों के मतदान के अधिकार के लिए लड़ेंगे और देश में लोकतंत्र को बहाल करने के लिए काम करेंगे। उन्होंने समाज से भेदभाव और अन्याय को खत्म करने की भी कसम खाई। नाहिद ने कहा, अगर बांग्लादेश अपने युवाओं के हाथ में है तो देश अपने लक्ष्य से नहीं भटकेगा। उन्होंने कहा कि लोगों ने युवाओं पर भरोसा किया और (आंदोलन के दौरान) सड़कों पर उतर आए। उन्होंने कहा कि युवाओं ने देश के लिए अपना खून दिया। उन्होंने कहा कि अगर लोग सोचते हैं कि युवाओं को कमान संभालनी चाहिए, तो वे तैयार हैं।

नाहिद ने साथ ही कहा कि अंतरिम सरकार में युवा और अनुभवी लोगों का मिश्रण है क्योंकि इसका प्रतिनिधित्व सभी मत के लोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा, भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन में भाग लेने वाले न केवल सरकार के हिस्से के रूप में काम करेंगे बल्कि सड़कों पर भी रहेंगे। उन्होंने कहा कि संयुक्त रूप से, हम देश को समृद्धि की ओर ले जाएंगे। उन्होंने कहा, बांग्लादेश के लोग लंबे समय से मतदान के अधिकार से वंचित हैं। सरकार का मुख्य उद्देश्य मतदान का अधिकार सुनिश्चित करके लोकतंत्र को बहाल करना है। उन्होंने कहा कि जब तक चुनाव आयोग सहित अन्य संस्थानों में संरचनात्मक सुधार नहीं किया जाता तब तक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना संभव नहीं है। पत्रकारों से बात करते हुए आसिफ ने कहा कि वे देश के सबसे युवा सलाहकारों के रूप में मिली चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि हम इस चुनौती को लेने के लिए तैयार हैं। फासीवादी सरकार के तहत सभी संस्थान बर्बाद हो गए थे। हमारा लक्ष्य इन संस्थानों में सुधार करके फासीवाद को खत्म करना है। उन्होंने कहा कि प्रमुख दल पिछले 17 वर्षों में निरंकुश सरकार को हटा नहीं सके, लेकिन वे अपनी एक सूत्री मांग की घोषणा के बाद केवल चार दिनों में ऐसा करने में कामयाब रहे। आसिफ ने कहा, हम साबित करेंगे कि युवा पीढ़ी भी जुनून और देशभक्ति के साथ देश की सेवा कर सकती है।

आज का इतिहास

1951 रेने प्लीवेन फ्रांस के प्रधानमंत्री बने।
1952 जॉर्डन के राजा तलाल को स्वास्थ्य कारणों के कारण त्याग दिया गया और उनके सबसे बड़े बेटे हुसैन (चित्र) ने उनका त्याग कर दिया।
1960 अफ्रीकी देश चाड़ ने फ्रांस से स्वतंत्रता हासिल की।
1962 वोस्तोक 3 को बैकोनूर कोस्मोड्रोम से लॉन्च किया गया और कॉस्मोनॉटएंड्रियन निकोलेयेव माइक्रोगेविटी में तैरने वाले पहले व्यक्ति बने।
1965 कैलिफोर्निया के लॉस एंजिल्स के वाट्स पड़ोस में रेस दंगे शुरू होते हैं। दंगों के अंत में 34 लोगों की मौत हो गई और 1,000 से अधिक घायल हो गए
1965 वॉट्स, लॉस एंजिल्स, कैलिफ़ोर्निया में हिंसक दौड़ दंगे शुरू हुए, छह दिनों तक चले और 34 लोग मारे गए और 1,032 लोग मारे गए।
1973 न्यूयॉर्क शहर के अपार्टमेंट के पुनर्निर्माण के मनोरंजन कक्ष में एक पार्टी में, डीजे कूल हर्क ने हिप-हॉप संगीत के लिए एक विस्तृत विराम के दौरान रैपिंग शुरू की।
1975 ब्रिटिश लेलैंड मोटर कॉर्पोरेशन ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में आयी।
1985 रोनाल्ड रीगन अमेरिका के 40वें राष्ट्रपति बने।
1988 अल-कायदा का गठन ओसामा बिन लादेन ने किया।
1991 911 आपातकालीन नंबर, जो बीमार या घायल व्यक्ति के पक्ष में पुलिस और पैरामेडिक्स लाता है, का शुम्भुर्ग में नेतृत्व किया जा रहा है। अन्य पश्चिमोत्तर शहर भी नई प्रणाली का परीक्षण करने के लिए भाग लेंगे और संख्या को याद रखना बहुत आसान है।
1999 सूरज का कुल ग्रहण अटलांटिक से कुछ सौ मील पहले, बोस्टन में शुरू होता है, और दुनिया भर में देखा जाता है।
2003 उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो ने अफगानिस्तान में शांति बल की कमान संभाली।
2006 पाकिस्तान ने तीसरी अगोस्टा 90बी श्रेणी की पनडुब्बी का जलावतरण किया।
2009 बहुत से लोग नेपाल के रामेछाप में चार भुजाओं और चार पैरों वाले एक बच्चे का सम्मान करते हैं, जो उसे गणेश के अवतार के रूप में दर्शाता है।
2011 उमर पटेक, एक प्रमुख संदिग्ध, अगर 2002 बाली बम विस्फोट, पाकिस्तान से इंडोनेशिया के लिए निकाले जाने के बाद जकार्ता में आतंकवाद के आरोपों की सुनवाई के लिए जाता है।

वक्फ संशोधन : मुस्लिम समुदाय के लिए एक सकारात्मक पहल क्यों है?

डॉ. जसीम मोहम्मद

भारत सरकार द्वारा संसद में प्रस्तुत किया गया 'वक्फ (संशोधन) विधेयक-2024' मौजूदा 'वक्फ अधिनियम-1995' में व्यापक एवं आवश्यक बदलाव का प्रस्ताव करता है। इसका मुख्य उद्देश्य वक्फ बोर्डों की देखरेख करनेवाले नियमों को अद्यतन करते हुए उनकी कार्यक्षमता को बढ़ाना है। विधेयक में वक्फ बोर्डों के प्रबंधन को बेहतर और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से कई संशोधन पेश किए गए हैं। इसका लक्ष्य वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग से संबंधित चिंताओं को दूर करना और इस दिशा में प्रभावी प्रशासन सुनिश्चित करना है।

दरअसल, कुछ लोग वक्फ (संशोधन) विधेयक-2024 के विषय में मुस्लिम समुदाय को यह सुझाव देते हुए कि संशोधन हानिकारक हो सकते हैं, अनावश्यक रूप से गुमराह करने का प्रयास कर सकते हैं, हालांकि यह समझना महत्त्वपूर्ण है कि ये सुधार मूल रूप से वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हैं। देखा जाए, तो वक्फ संपत्तियों को ऐतिहासिक रूप से प्रायः कुप्रबंधन और अतिक्रमण से संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। पंजीकरण, वित्तीय रिपोर्टिंग और प्रशासन-प्रबंधन के लिए नए नियमों को लागू कर, विधेयक का उद्देश्य इन मुद्दों से सीधे निपटना है।

इस दृष्टि से संपत्ति पंजीकरण और विस्तृत वित्तीय प्रकटीकरण के लिए एक केंद्रीय पोर्टल के माध्यम से इन संपत्तियों को अनधिकृत उपयोग से बचाने में सहायता मिलेगी और यह सुनिश्चित होगा कि उनका प्रबंधन उनके इच्छित उद्देश्यों के अनुरूप किया जाए। ये परिवर्तन वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग और कुप्रबंधन को रोकने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जो कई वर्षों से चिंता का विषय रहे हैं।

विधेयक में पेश किए गए सुधार उन समस्याओं के लिए एक आवश्यक प्रतिक्रिया हैं, जिन्होंने अतीत में वक्फ प्रबंधन को परेशान किया है। बढ़ी हुई पारदर्शिता और जवाबदेही के कारण वक्फ संपत्तियों को अतिक्रमण और दुरुपयोग से बचाने में निस्संदेह सहायता मिलेगी। ये संशोधन वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और सुरक्षा के लिए एक प्रतिबद्धता है। इस क्रम में समुदाय के दीर्घकालिक लाभ के लिए इन परिवर्तनों का समर्थन करना अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

वक्फ (संशोधन) विधेयक-2024 को लेकर अनेक चिंताएं और भ्रामक सूचनाएं प्रसारित होती रही हैं, विशेषकर उन लोगों की ओर से जिनके पास यथास्थिति बनाए रखने में निहित स्वार्थ हो सकते हैं। कुछ लोग तर्क दे सकते हैं कि विधेयक हानिकारक है, लेकिन इन संशोधनों को पारदर्शिता और जवाबदेही के चश्मे से देखना आवश्यक है।

प्रस्तावित परिवर्तन मूल रूप से वक्फ प्रणाली में सुधार के बारे में हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संपत्तियों का प्रबंधन अधिक प्रभावी और नैतिक रूप से किया जाए। विधेयक में संशोधनों में वक्फ संपत्तियों के लिए एक केंद्रीय डेटाबेस और पोर्टल की स्थापना सम्मिलित है, जो सभी संपत्तियों का एक व्यापक रिकॉर्ड सुरक्षित एवं संरक्षित करेगा। यह विधेयक वक्फ भूमि के कुप्रबंधन और अनधिकृत उपयोग की संभावनाओं को कम करने की दिशा में एक विकासात्मक पहल है।

अतीत में, ऐसे कई उदाहरण हैं, जहां एकीकृत और पारदर्शी प्रणाली की कमी के कारण वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण किए गए या उनका दुरुपयोग किया गया। नए नियम यह सुनिश्चित करके इस तरह के दुरुपयोग को रोकने का प्रयास करते हैं कि सभी संपत्तियों का उचित रूप से दस्तावेजीकरण और उनकी निगरानी की जाए। इसके अतिरिक्त, विधेयक वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में विभिन्न हितधारकों की भूमिका को बढ़ाता है, जिसमें केंद्रीय वक्फ परिषद् में गैर-मुस्लिम सदस्यों को सम्मिलित करना भी है।

यह समावेशी दृष्टिकोण इस दिशा में निर्णय लेने की प्रक्रिया में विविधता और विशेषज्ञता लाने के लिए बनाया गया है। इस क्रम में बढ़ा हुआ प्रतिनिधित्व और जवाबदेही तंत्र हितों के टकराव को रोकने में सहायता करेगा और यह

सुनिश्चित करेगा कि वक्फ संपत्तियों का उपयोग उनके इच्छित उद्देश्यों के लिए किया जाए, जिससे पूरे समुदाय को लाभ हो। विधेयक में यह स्पष्ट किया गया है कि सरकारी संपत्तियों को वक्फ संपत्ति नहीं माना जाएगा। यह एक तर्कसंगत और आवश्यक समायोजन है।

यदि वक्फ संपत्तियों ने सरकारी भूमि पर क़ब्ज़ा कर रखा है, तो इस स्थिति को पारदर्शी और व्यवस्थित तरीक़े से संबोधित करना महत्त्वपूर्ण है। भूमि के उचित प्रबंधन और सही उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए ऐसे मामलों की समीक्षा करने में स्वाभाविक रूप से कुछ भी गलत नहीं है। इस समीक्षा का प्राथमिक लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी संपत्तियों, चाहे वह वक्फ रूप में या सरकारी रूप में वर्गीकृत हों, का उपयोग कानूनी और नैतिक मानकों के अनुरूप किया जाए। सत्यापन की यह प्रक्रिया वक्फ संपत्तियों और सरकारी भूमि दोनों की अखंडता को बनाए रखने के लिए महत्त्वपूर्ण है।

ऐसे मामलों की समीक्षा करना, जहां वक्फ संपत्तियों ने सरकारी भूमि पर क़ब्ज़ा किया है, स्वामित्व और उपयोग के अधिकारों को स्पष्ट करने में मददगार है। यह किसी भी अनुचित कार्य का सुझाव नहीं देता है, बल्कि यह सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखता है कि सभी संपत्तियों का प्रबंधन सही और कानूनी तरीक़े से किया जाए। इसके अलावा, यह समीक्षा प्रक्रिया किसी भी विसंगति को ठीक करने और वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को मजबूत करने का अवसर प्रदान करती है।

यह सुनिश्चित करके कि सभी संपत्तियों का सही तरीके से दस्तावेजीकरण और उपयोग किया गया है, यह प्रणाली बेहतर निगरानी को बढ़ावा देती है और विवादों के जोखिम को कम करती है। अधिनियम में एक महत्त्वपूर्ण संशोधन वक्फ बोर्डों में मुस्लिम महिलाओं और ग़ैर-मुस्लिमों का बढ़ा हुआ प्रतिनिधित्व है। वक्फ बोर्ड में मुस्लिम महिलाओं और गैर-मुस्लिम सदस्यों को सम्मिलित करना पारदर्शिता की दिशा में एक समावेशी और प्रगतिशील पहल है। यह समावेशी प्रतिनिधित्व बोर्ड को संभवतः अधिक संतुलित और न्यायसंगत प्रबंधन की ओर ले जाएगा और सभी हितधारकों की ज़रूरतों को पूरा करेगा, जिससे विभिन्न समूहों के बीच एकता और समझ की भावना विकसित करने में सहायता मिलेगी।

वक्फ संपत्तियों का इतिहास भ्रष्टाचार और शोषण के उदाहरणों से भरा पड़ा है, जहां उनके प्रबंधन की जिम्मेदारी संभालनेवालों ने कई बार निजी लाभ के लिए अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है। परिणामस्वरूप मुस्लिम समुदाय के भीतर शैक्षिक, सामाजिक और धार्मिक कारणों का समर्थन करने के लिए बनाई गई मूल्यवान संपत्तियों का नुकसान हुआ है। नए नियम और निगरानी तंत्र आरंभ करने से वक्फ संपत्तियों को न केवल शोषण से बचाया जा सकेगा, बल्कि यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि उनका उपयोग व्यापक समुदाय के लाभ के लिए किया जाए।

आगाख़ानी वक्फ और बोहरा वक्फ जैसे शब्दों के लिए नई परिभाषाएं और स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना वक्फ प्रबंधन में अधिक स्पष्टता और सटीकता की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। विभिन्न प्रकार की वक्फ संपत्तियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने का यह प्रयास ग़लतफ़हमी और विवादों से बचने में सहायता करेगा। इससे विभिन्न प्रकार की वक्फ संपत्तियों को बेहतर ढंग से समझने और उनका प्रबंधन करने में सहायता मिलेगी। अगाखानी और बोहरा के लिए अलग-अलग औक़ाफ़ बोर्ड स्थापित करना एक सराहनीय निर्णय है, जो इन समुदायों की अनूठी ज़रूरतों और चिंताओं को पहचानता है।

केंद्रीय वक्फ परिषद् का विस्तार करके गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना एक दूरदर्शी कदम है, जो समावेशिता और संतुलित शासन को बढ़ावा देता है। यह परिवर्तन निर्णय लेने की प्रक्रिया में अधिक विविध दृष्टिकोणों की अनुमति देता है, जिससे वक्फ संपत्तियों का अधिक न्यायसंगत और सुव्यवस्थित प्रबंधन हो सकता है। केंद्र सरकार को विस्तृत वित्तीय रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता, उचित निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा क़दम है। नियमित और विस्तृत वित्तीय रिपोर्ट वक्फ फंड के उपयोग की निगरानी और किसी भी अनियमितता की पहचान करने में मदद करेगी। यह एक सकारात्मक विकास है, जो वक्फ संसाधनों के अधिक प्रभावी और जिम्मेदार प्रबंधन में योगदान देगा।

मुतवल्लियों (वक्फ संपत्तियों के संरक्षक या प्रबंधक) के लिए योग्यता और अयोग्यता के मानदंड निर्दिष्ट करना इन संपत्तियों के प्रभावी प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए एक तर्कसंगत और आवश्यक उपाय है। वक्फ संपत्तियों के रखरखाव और उचित उपयोग की देखरेख में मुतवल्ली की भूमिका महत्त्वपूर्ण है, जो मुस्लिम समुदाय की धार्मिक, शैक्षिक और सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हैं। हालाँकि, अतीत में ऐसे उदाहरण रहे हैं, जहाँ अपर्याप्त योग्यता या यहाँ तक कि संदिग्ध इरादोंवाले व्यक्तियों को इस भूमिका के लिए नियुक्त किया गया है, जिससे इन मूल्यवान संसाधनों का कुप्रबंधन और दुरुपयोग हुआ है।

वक्फ बोर्ड, जो वक्फ संपत्तियों की देखरेख के लिए जिम्मेदार हैं, अक्सर मुतवल्लियों की नियुक्ति से संबंधित मुद्दों पर पूर्वाग्रहों से ग्रस्त रहा है। इस पद के लिए आवश्यक योग्यताओं पर स्पष्ट दिशा-निर्देशों के बिना, कभी-कभी योग्यता के बजाय व्यक्तिगत संबंधों या राजनीतिक विचारों के आधार पर नियुक्तियाँ की जाती रही हैं। इसके परिणामस्वरूप वक्फ प्रणाली में विश्वास का क्षरण हुआ है, क्योंकि सार्वजनिक भलाई के लिए बनाई गई संपत्तियों का प्रबंधन हमेशा समुदाय के सर्वोत्तम हितों में नहीं किया जाता है।

इसके अलावा, अयोग्यता मानदंड की शुरूआत भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि जो लोग भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन या अन्य प्रकार के कदाचार के दोषी पाए गए हैं, उन्हें ऐसी भूमिकाओं में बने रहने की अनुमति नहीं है, जहाँ वे और अधिक नुकसान पहुँचा सकते हैं। वक्फ अधिनियम में ये संशोधन एक महत्त्वपूर्ण और सकारात्मक कदम है।

सरकार को ऐसे उपाय करने के लिए सराहना की जानी चाहिए, जो पारदर्शिता, जवाबदेही और वक्फ संपत्तियों के उचित प्रबंधन को बढ़ाएँगे। बहुत लंबे समय से, वक्फ संपत्तियों का प्रशासन भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन और दुरुपयोग के मुद्दों से ग्रस्त रहा है, जिसने मुस्लिम समुदाय को उन सभी लाभों से वंचित कर दिया है, जो इन संपत्तियों द्वारा उनके लिए लाभप्रद बनाने का इरादा और उद्देश्य है। स्पष्ट विनियमन, सख़्त लेखा परीक्षा प्रक्रियाएँ और वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के प्रभारी लोगों के लिए योग्यताएं प्रस्तुत करके, सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि इन संपत्तियों की सुरक्षा की जाए, जिससे उनका उपयोग उनके सही उद्देश्यों के लिए किया जा सके।

वक्फ अधिनियम के बहाने ये संशोधन अतीत में हुए शोषण और कुप्रबंधन पर अंकुश लगाएँगे और वक्फ प्रणाली की अखंडता को बहाल करेंगे। इस क्रम में मुसलमानों को सतर्क और जागरूक रहना चाहिए, क्योंकि कुछ राजनेता, जिनके पास इन सुधारों के ख़िलाफ़ मजबूत या वैध तर्क नहीं हो सकते हैं, वे ग़लत सूचना फैलाकर, लोगों को भ्रमित कर या भावनाओं से खेलकर समुदाय को प्रभावित करने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे बहकावे या भ्रमित करनेवाले कारकों से प्रभावित होने के बजाय, समुदाय के लिए इन संशोधनों के दीर्घकालिक लाभों और प्रभावों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्हें उनके लिए उन उपायों का समर्थन करना महत्त्वपूर्ण है, जो वक्फ संपत्तियों को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह प्रबंधन की ओर ले जाएँगे।

दिल्ली में हो रही महाराष्ट्र के दिल की बात!

अमिताभ श्रीवास्तव

एक जमाना था जब क्षेत्रीय दलों की ताकत के चलते सारे राजनीतिक समझौते राज्यों की राजधानियों में होते थे, लेकिन तालमेल की सियासत आरंभ होने के बाद से जहां गठबंधन का वजन अधिक होता है, वहीं पर प्रादेशिक दलों को अपने दिल की बात कहने जाना पड़ता है। इसी क्रम में महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की तैयारियों का केंद्र दिल्ली बन चुका है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस, अजित पवार से लेकर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे अपने बेटे आदित्य ठाकरे के साथ तीन दिन तक दिल्ली में ताल ठोंक चुके हैं। यह इसलिए भी हो रहा, क्योंकि बीते कुछ सालों में राज्य में राजनीतिक गठबंधन कुछ इस तरह तैयार हो गए हैं कि दल एक-दूसरे का हाथ पकड़े बिना आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। अतीत में भगवा दलों का मेलमिलाप और धर्मनिरपेक्ष दलों का एकजुट होना विचारधारा का सीधा विभाजन कर दिखाता था। मगर इन दिनों मतदाता से लेकर पार्टियों के कार्यकर्ता तक संभ्रम में जीने के लिए मजबूर हैं।

ताजा घटनाक्रम में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने गत छह अगस्त से तीन दिन का दिल्ली दौरा किया। उन्होंने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। गत गुरुवार को वह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से भी मिले। वैसे यह लोकसभा चुनाव के बाद उनका पहला और राजनीतिक जीवन का सबसे लंबी अवधि का दिल्ली दौरा था। बीते सालों, खास तौर पर नब्बे के दशक की महाराष्ट्र की सियासी तस्वीर में शिवसेना प्रमुख बालासाहब ठाकरे का कद बहुत ऊंचा नजर आता था। वह राजनीति के समीकरणों को अपने घर पर बैठकर तय करते थे और सभी दलों के नेता उनसे मिलने उनके घर पर ही जाते थे। उसके बाद जब तक राज्य में भगवा गठबंधन कायम रहा, तब तक मुंबई का दबाव बना रहा। किंतु वर्ष 2019 में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनने के बाद से राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ठाकरे का घर से बाहर निकलना आरंभ हो गया। वह अनेक बार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता शरद पवार के मुंबई स्थित निवास स्थान सिल्वर ओक तक जाते दिखाई दिए। जब वर्ष 2022 में उनकी सरकार गिर गई और कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए क्षेत्रीय दलों को साथ लाना आरंभ किया और 'इंडिया' गठबंधन बना तो वह उसकी बैठक में शामिल होने पटना भी पहुंचे। ठाकरे लोकसभा चुनाव के दौरान मुंबई में हुई 'इंडिया' गठबंधन की रैली का भी हिस्सा बने, जिससे लोकसभा चुनाव के अच्छे परिणाम सामने आए। साथ ही उन्हें धर्मनिरपेक्ष गठबंधन की राजनीति का महत्व समझ आया। बावजूद इसके अब विधानसभा चुनाव के मुहाने पर स्थितियां अलग हैं। महाराष्ट्र में 'इंडिया' गठबंधन के अनेक घटक दल चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे हैं। यहां तक कि कांग्रेस बार-बार पूरी सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा को सामने रख रही है। मुंबई में आम आदमी पार्टी (आप) की भी चुनाव लड़ने की तैयारी है। राज्य की कुछ सीटों के साथ मुंबई में समाजवादी पार्टी (सपा) भी अपने उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतार सकती है। ऐसे में राज्य में धर्मनिरपेक्ष मतों के बंटवारे की प्रबल संभावना है, जो 'इंडिया' गठबंधन के आधार हैं।

यह बात लोकसभा चुनाव में शिवसेना के उद्धव गुट को अच्छी तरह समझ में आ गई है। उसका स्वतंत्र रूप से लड़कर खुद के वोट बैंक के सहारे चुनाव जीतना असंभव है। यूं भी विधानसभा चुनाव में कुल मतदाता कम होने से मामूली अंतर से जीत-हार का खतरा हमेशा बना रहता है। इसलिए किसी तालमेल की घोषणा के पहले आपसी सामंजस्य का होना आवश्यक है। राज्य में कांग्रेस के शीर्ष नेता, आप के नेता और सपा के नेता अपनी जमीन बनाए रखने की स्थिति में चुनाव मैदान से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं। यह संभव है कि शिवसेना उद्धव गुट राकांपा के पवार गुट को सीट बंटवारे में समझाने में सफलता पा सकता है, लेकिन 'इंडिया' गठबंधन के बाकी दलों को सीमाओं में बांधने के लिए दिल्ली से संदेश की जरूरत होगी। उधर, सत्ताधारी महागठबंधन में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) महाराष्ट्र में 150 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही है। उसने वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में 152 सीटों पर चुनाव लड़ा था। शिवसेना का शिंदे गुट लगभग 125 सीटों की मांग कर रहा है। राकांपा का अजित पवार गुट 80 सीटों पर सर्वेक्षण कर चुनाव की तैयारी कर रहा है। इस परिस्थिति को समझने और समझाने के लिए मुख्यमंत्री शिंदे, उपमुख्यमंत्री फडणवीस और अजित पवार दिल्ली के दौरे कर रहे हैं। कोई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिल रहा है तो कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल रहा है। इन्हीं मुलाकातों के केंद्र में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्?डा भी हैं। शिंदे और अजित पवार दोनों को मालूम है कि भाजपा की महत्वाकांक्षा उनके अरमानों पर पानी फेर सकती है। इसलिए वे भाजपा के हाईकमान से दबाव बनाने के भरसक प्रयास में जुटे हैं। राज्य में सत्ताधारी गठबंधन के पास विधानसभा में 180 से अधिक विधायक हैं। यदि सभी को दोबारा चुनाव लड़ने का अवसर दिया जाता है तो बंटवारे के लिए अवसर कम रह जाता है। किंतु चुनाव में मत विभाजन की संभावना के चलते हर सीट पर दोबारा जीत का भरोसा नहीं किया जा सकता है।

इसलिए जीत की अधिक संभावना के साथ ही किसी उम्मीदवार को टिकट दिया जा सकता है। ऐसे में निजी भावना, समर्पण और निष्ठा को चुनाव में अधिक महत्व मिलने की गुंजाइश कम है। इस बीच, लोकसभा चुनाव में हारे हुए अनेक उम्मीदवार भी विधानसभा में चुनाव लड़ने का ख्वाब देख रहे हैं। उनको लेकर दलों की चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। इसलिए दिल्ली की दौड़ आवश्यक हो चली है, जहां पर दिल की बात की जा सकती है और कोई आसान रास्ता निकाला जा सकता है। साथ ही पक्ष-विपक्ष के चुनावी मुद्दों की तैयारी की जा सकती है। इसी कारण राज्य की नई राजनीति से दिल्ली की दूरियां खत्म हो चली हैं। मगर यह परिस्थिति उनके लिए परेशानी पैदा करने वाली है, जो यह कहते थे कि महाराष्ट्र पर दिल्ली की हुकूमत नहीं चल सकती है। अब वही अपनी हुकूमत चलाने-बचाने के लिए दिल्ली के गलियारों को नापते नजर आ रहे हैं। शायद उन्हें भी यह विश्वास हो चला है कि दिल्ली में दिल की बात से समाधान के दरवाजे खुल सकते हैं और राज्य की सियासत का रास्ता सीधा हो सकता है।

आरक्षण का ताना-बाना और कुछ सवाल

प्रभु चावला

सहस्राब्दियों से जाति भारतीय मानस में पत्थर की तरह ठोस पैठ बना चुकी है। विडंबना ही है कि लोकतंत्र बनने के बाद भी भारत में भेदभाव की विरासत जारी रही। सामाजिक ढांचे को सिर के बल खड़ा कर दिया गया, पर जाति आधारित परिवारवाद भी बिना चुनौती के फलता-फूलता रहा। राजनीति एवं नौकरशाही में धनी एवं ताकतवर वंशगत विरासत इस व्यवस्था को पोषित करती रही है, पर बीते सप्ताह आया सर्वोच्च न्यायालय का एक निर्णय इस व्यवस्था को पटरी से उतार सकता है।

संसद, चुनाव एवं संस्थानों में जाति पर चल रहे वर्तमान शोर ने शीर्षस्थ न्यायालय के सात न्यायाधीशों की एक संवैधानिक पीठ को उद्वेलित कर दिया। न्यायाधीश बी.आर. गवई के नेतृत्व में चार न्यायाधीशों ने रेखांकित किया कि जातिगत आरक्षण मेधा से संबंधित है, न कि नौकरशाही या धन तंत्र से। न्यायाधीश गवई ने लिखा कि सरकार को अनुसूचित जाति एवं जनजाति में क्रीमी लेयर की पहचान के लिए नीति बनानी चाहिए, जिससे उन्हें आरक्षण के दायरे से हटाया जा सके।

इसी उपाय से संविधान में निहित समानता को सही अर्थों में साकार किया जा सकता है। उन्होंने पूछा कि क्या एक बड़े अधिकारी की संतान को पंचायत या जिला परिषद के विद्यालय में पढ़ रहे बच्चे के समकक्ष रखा जा सकता है। यदि गीता भारत की आत्मा है, तो जाति इसका अभिशाप है, जो व्यवस्था सहस्राब्दियों पहले पेशेवर पहचान के रूप से प्रारंभ हुई, वह कालांतर में भ्रष्ट होकर चुनाव जीतने का एक पैंतरा बन गई।

जातिगत आरक्षण की शुरुआत लगभग 125 साल पहले हुई। अनुसूचित जातियों और जनजातियों की दुर्दशा को देखते हुए संविधान निर्माताओं ने कार्यपालिका एवं विधायिका में प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की, जो एक अस्थायी प्रावधान था और उसकी अवधि दस वर्ष थी। भारतीय राजनीति को यथास्थिति पसंद है और इसे बदलाव से परहेज है। किसी दल ने उस प्रावधान में फेरबदल नहीं किया है। उन्होंने जाति प्रथा को अपने चुनावी घोषणापत्र के लिए आरक्षित रखा है।

आरक्षण का उद्देश्य स्वतंत्रता के बाद की पहली वंचित पीढ़ी की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को बेहतर करना था, लेकिन वह अब तीसरी पीढ़ी का एक विशेषाधिकार बन गया है। आरक्षण का आशय समानता लाने का एक माध्यम बनना था। अब यह सामाजिक अभिजन के अल्पाधिकार और एकाधिकार का युग्म बन गया है। सत्ता पर अपने हिस्से के नियंत्रण से दलित एवं पिछड़े शाहों ने एक विशिष्ट सुरक्षा घेरा बना लिया है, जिसमें निचले पायदान पर खड़े लोगों का प्रवेश वर्जित है।

जब सत्ता ने अपने लाभ को सर्वोच्च बना लिया है, तो नियंत्रण एवं संतुलन के संवैधानिक सिद्धांत का हस्तक्षेप हुआ है। न्यायाधीश गवई ने रेखांकित किया है कि विषमता और सामाजिक भेदभाव, जो ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत अधिक व्याप्त हैं, शहरी क्षेत्रों की ओर आते-आते कम होने लगते हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अच्छे संस्थानों के छात्र तथा पिछड़े और दूर-दराज के क्षेत्रों में पढ़ रहे छात्र को एक ही श्रेणी में रखना संविधान के समता के सिद्धांत को भुला देना है।

न्यायाधीश पंकज मित्तल ने कहा है कि आरक्षण को पहली पीढ़ी या एक पीढ़ी तक सीमित रखा जाना चाहिए तथा अगर एक पीढ़ी ने आरक्षण का लाभ उठाकर उच्च हैसियत पा ली है तो तार्किक रूप से अगली पीढ़ी को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए।

बांग्लादेश में सेना की भूमिका पर उठते सवाल

शोभना जैन

बांग्लादेश में जारी उथल-पुथल के बीच सवाल यह भी उठा है कि क्या शेख हसीना का राज खत्म होने के पीछे सेना की भूमिका है और क्या सत्ता अब पिछले दरवाजे से जनरल वकार-उज-जमान के हाथ आ गई है? वैसे इतिहास बताता है कि पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश की सेना ने कभी लंबे समय तक देश की बागडोर नहीं संभाली है। वर्ष 1975 तथा फिर 1990 में सेना ने थोड़े समय तक ही सत्ता की बागडोर संभाली। उसके बाद दिसंबर 2008 में एक बार फिर उसने सत्ता की बागडोर संभाली। लोकतांत्रिक व्यवस्था दोबारा कायम होने के बाद वह देश की कमान से हट जाती थी। बांग्लादेश के सैन्य प्रमुख वकार-उज-जमान ने कई साल शेख हसीना के साथ नजदीकी तौर पर काम किया है। वे सेना के आधुनिकीकरण से भी जुड़े रहे हैं। जनरल जमान ने गत 23 जून को ही बांग्लादेश सेना की कमान संभाली थी। सेना अध्यक्ष बनने से पहले उन्होंने छह महीने से अधिक चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के रूप में कार्य किया। बांग्लादेश मामलों के एक जानकार के अनुसार सेना ने कानून और व्यवस्था के मुद्दों पर हसीना सरकार का तब तक समर्थन किया जब तक कि यह साफ नहीं हो गया कि विरोध प्रदर्शन बहुत बड़े थे और प्रदर्शनकारी सेना की अवहेलना करने के लिए तैयार थे। सेना प्रमुख ने यह साफ कर दिया था कि वह अपने सैनिकों को गोली चलाने का आदेश नहीं देंगे। इससे शेख हसीना की किस्मत तय हो गई। लेकिन फिर सेना ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई। जनरल वकार ने देश चलाने के लिए अंतरिम सरकार के गठन पर चर्चा करने के लिए राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया। सेना की नई सरकार में भूमिका के साथ ही और भी कई गहरे सवाल तो चल ही रहे हैं। क्या नई सरकार वहां हिंसा पर काबू कर पाएगी? एक अर्थशास्त्री के शासन प्रमुख हो जाने के बाद क्या वहां ध्वस्त अर्थव्यवस्था पटरी पर आ सकेगी। वहां चुनाव कब तक हो पाएंगे। इस पृष्ठभूमि में वहां सेना की भूमिका का मुद्दा दिनोंदिन और अहम होता जा रहा है। बहरहाल, फिलहाल तो यही लगता है कि बांग्लादेश में हालात काबू में करने के लिए सेना के तस्वीर में सीधे आने से हालात फौरी तौर पर तो जरूर सुधारे जा सकते हैं लेकिन यह समस्या का स्थायी हल नहीं होगा। प्रदर्शनकारी छात्र वहां सैन्य सरकार के पक्ष में कतई नहीं हैं और फिर सेना के लिए भी वहां स्थिर राजनीतिक व्यवस्था बना पाना एक बड़ी चुनौती है। वहां सरकार का स्वरूप क्या होगा, सेना का सिविल सरकार में कितना और कितने समय तक दखल रहेगा, इन तमाम उलझे सवालों का जवाब तो फिलहाल भविष्य के गर्भ में ही छिपा है।

लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा सभापति से सीधे क्यों भिड़ने लग गया है विपक्ष?

नीरज कुमार दुबे

संसद का मॉनसून सत्र इस बात के लिए खासतौर पर याद किया जायेगा कि इस दौरान कई बार ऐसा देखने को मिला कि लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला और राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ से विपक्षी सदस्यों ने जानबूझकर उलझने का प्रयास किया। दोनों सदनों के सभापतियों पर विपक्ष ने तमाम तरह के आक्षेप लगाने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाये। संभवतः ऐसा इसलिए किया गया ताकि आसन की निष्पक्षता को संदेह के कठघरे में खड़ा किया जा सके। खास बात यह है कि विपक्षी सदस्यों ने सदन की सदस्यता की शपथ लेते समय संविधान की प्रति हाथ में ले रखी थी लेकिन उसी संविधान के नियमों से बनी सदन के संचालन की नियम पुस्तिका में लिखे निर्देशों का पालन करने में वह कोताही बरतते हैं। ताजा मामला समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन का है जिन्होंने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को नाहक ही विवाद में घसीट कर गलत परम्परा कायम की। इस बार के सत्र के दौरान दोनों सदनों की कार्यवाही पर गौर करेंगे तो ऐसा लगेगा कि सरकार को छोड़ कर विपक्ष अब लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा सभापति से सीधे भिड़ते रहने की रणनीति पर चल रहा है।

इसके अलावा, इस बार यह भी देखने को मिला कि विभिन्न विधेयकों पर चर्चा के दौरान एक दूसरे पर हमला कर रहे पक्ष-विपक्ष के नेता मूल मुद्दों और समस्याओं पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे थे। नेताओं के संबोधनों में सुर्खियों में आने लायक और उनके भाषणों को वायरल बनाने लायक सामग्री तो थी लेकिन देश की वर्तमान समस्याओं का हल सुझाने या भविष्य की जरूरतों को पूरा करने वाले सुझावों का नितांत अभाव था। देखा जाये तो संसद की कार्यवाही के संचालन पर देश का करोड़ों रुपया खर्च होता है इसलिए सांसदों को चाहिए कि वह सिर्फ अपने राजनीतिक प्रभुत्व को बढ़ाने पर ध्यान देने की बजाय जनहित के मुद्दों को उठाने और जनता की समस्याओं का हल निकलवाने को प्राथमिकता दें।

हालांकि वर्तमान लोकसभा में एक बात यह अच्छी नजर आ रही है कि सरकार के साथ-साथ विपक्ष भी खूब सक्रिय नजर आ रहा है। पिछली दो लोकसभा में चूंकि औपचारिक रूप से कोई नेता प्रतिपक्ष ही नहीं था इसलिए विपक्ष प्रभावी भूमिका में नहीं दिख रहा था। उस समय संसद में बिना बहस के ही कई अहम विधेयक पारित हो जा रहे थे। लेकिन अब लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के बाद से राहुल गांधी जिस तरह जनहित के मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठा रहे हैं उससे सरकार अपने मन मुताबिक काम नहीं कर पा रही है। वैसे यह अच्छी बात है कि अब जिन विधेयकों पर आम राय नहीं बन रही है उन्हें संयुक्त संसदीय समिति को भेजा जा रहा है। गौरतलब है कि पिछली लोकसभा में ऐसा देखने को नहीं मिलता था।

कृति सेनन के रांझणा बनेंगे धनुष! आनंद एल राय की तेरे इश्क में के लिए मिलाया हाथ

साउथ सुपरस्टार धनुष इन दिनों रायन की सफलता का जश्न मना रहे हैं। इसके साथ ही वे अपनी आने वाली फिल्म कुबेर को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। वहीं, इस बीच अब अभिनेता को लेकर एक और दिलचस्प खबर सामने आ रही है, जो उनकी नई फिल्म को लेकर है। खबर है कि उनकी जोड़ी एक बार फिर बॉलीवुड अभिनेत्री के साथ बन सकती है। वह अभिनेत्री कृति सेनन है। सोशल मीडिया पर यह खबर प्रशंसकों का उत्साह बढ़ा रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार, जल्द ही एक नई फिल्म में धनुष और कृति सेनन एक साथ काम करते नजर आएंगे। 2013 में रांझणा की सफलता के बाद निर्देशक आनंद एल राय और अभिनेता धनुष एक बार फिर तेरे इश्क में नाम की एक और रोमांटिक फिल्म के लिए साथ आ रहे हैं। एक साल पहले एक विशेष वीडियो के साथ इसकी घोषणा की गई थी, लेकिन अभी तक कलाकारों की पुष्टि नहीं हुई है, जिससे चर्चा है कि कृति सेनन इस संगीतमय प्रेम कहानी में मुख्य भूमिका निभाने के लिए उत्साहित हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, कृति धनुष के साथ अभिनय करने के लिए बातचीत कर रही हैं। कृति सेनन और धनुष दोनों पहले भी निर्देशक आनंद एल राय के साथ अलग-अलग फिल्मों में काम कर चुके हैं। बताया जा रहा है कि फिल्म एआर रहमान की म्यूजिकल होगी, जिसके बोल इरशाद कामिल द्वारा लिखे जाएंगे। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कृति सेनन ने कुछ महीने पहले आनंद एल राय से कहानी सुनी थी और इस एक्शन लव स्टोरी की दुनिया में उतरने में दिलचस्पी दिखाई है।
रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि निर्माता धनुष और कृति के अलावा एक और अभिनेता को कास्ट करना चाह रहे हैं। निर्माता कथित तौर पर कई अभिनेताओं से बातचीत कर रहे हैं और जल्द ही उनका चयन करेंगे। तेरे इश्क में की शूटिंग अक्तूबर 2024 में शुरू होने की उम्मीद है और ऐसे में यह फिल्म 2025 में रिलीज होगी। कृति सेनन दो पत्ती की रिलीज की तैयार कर रही हैं। वहीं, धनुष अब कुबेर में रश्मिका मंदाना के साथ नजर आएंगे।

सामंथा से पहले इन साउथ अभिनेत्रियों ने अभिनय के दम पर चमकाई सीरीज

आज के दौर में ओटीटी पर फिल्मों और वेब सीरीज को दर्शकों द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है। भागदौड़ की जिंदगी में दर्शन भी अब घर बैठे सुकून से ओटीटी पर ही अपनी पसंदीदा सीरीज देखना पसंद करते हैं। ऐसे में सभी कलाकार ओटीटी प्लेटफॉर्म का रुख कर रहे हैं और अपने अभिनय का दाम दिखा रहे हैं। बॉलीवुड सितारे तो क्या साउथ सिनेमा के कलाकार भी अब ओटीटी पर अपनी धाक जमाने के लिए निकल चुके हैं। ऐसे में कई साउथ अभिनेत्रियों ने भी दमदार सीरीज में काम किया है, जिसका हालिया उदाहरण सामंथा रुथ प्रभु का है। वे एक बार फिर सिटाडेल के जरिए ओटीटी पर धमाल मचाने के लिए तैयार हैं।

सामंथा रुथ प्रभु

सबसे पहले शुरुआत सामंथा रुथ प्रभु से ही करते हैं। फैमिली मैन 2 के साथ सामंथा प्रभु ने अपनी सीरीज की शुरुआत की। राज और डीके शो के निर्देशन के प्रभारी थे। सामंथा ने राजी नाम की लड़की एक किरदार निभाया और आम जनता और आलोचकों दोनों ने वास्तव में उसके काम की प्रशंसा की। सीरीज में सामंथा ने खुद को एक विद्रोही नेता के रूप में बदल दिया, जो युद्ध में माहिर है और भयानक आघात का सामना कर चुकी हैं। अब वह सिटाडेल के भारतीय रूपांतरण के साथ दर्शकों को फिर से प्रभावित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। सीरीज में वे बॉलीवुड अभिनेता वरुण धवन के साथ नजर आएंगी। यह वरुण का ओटीटी डेब्यू होगा।

नित्या मेनन

नित्या मेनन भी इस लिस्ट में शामिल हैं। नित्या ने अभिषेक बच्चन के साथ वेब सीरीज ब्रीद- इन्टू द शैडो में काम किया था। उन्होंने अभिषेक बच्चन की पत्नी का किरदार निभाया था। मयंक शर्मा द्वारा निर्देशित विक्रम तुली, प्रिया सागगी और अभिजीत देशपांडे की मनोवैज्ञानिक अपराध थ्रिलर में अभिषेक बच्चन, अमित साध, निथ्या मेनन, सयामी खेर और इवाना कौर दिखे थे।

राशि खन्ना

अभिनेत्री राशि खन्ना भी इस लिस्ट में अपनी जगह बनाए हुई हैं। उन्होंने फर्जी सीरीज में काम किया था, जिसमें वे शाहिद कपूर के साथ नजर आई थीं। सीरीज में अपने काम के बाद से ही फर्जी एक्टर राशि खन्ना को प्रशंसा मिली। सीरीज में उन्होंने आरबीआई ऑफिसर मेघा का किरदार निभाया था। शो में वह खुद को एक ईमानदार और बहुत ग्लैमरस ऑफिसर के रूप में पेश करती हैं।

प्रियामणि

इस लिस्ट के साउथ अभिनेत्री प्रियामणि भी शामिल हैं। द फैमिली मैन 2 में प्रियमणि ने सुचित्रा अय्यर की भूमिका निभाई है, जिसे सुची के नाम से भी जाना गया। सीरीज में वे एक ऐसी पत्नी थीं, जो अपने परिवार के लिए अकेले कमाने वाली बनकर तंग आ चुकी हैं। उनकी दृढ़ता और अभिनय की बहुत प्रशंसा की गई।

एसएस राजामौली की फिल्म एसएसएमबी29 से नहीं जुड़े विक्रम

चियान विक्रम अपनी अगली फिल्म थंगलान को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। पा रंजीत के निर्देशन में बनी यह फिल्म 15 अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है। अभिनेता जोरो-शोरों से इसका प्रमोशन कर रहे हैं। हाल ही में वह फिल्म के प्रचार के लिए हैदराबाद में थे। इसी दौरान विक्रम ने थंगलान के प्रमोशन के साथ-साथ उस अफवाह पर भी चुप्पी तोड़ी, जिसका सच जानने के लिए प्रशंसक काफी ज्यादा उत्सुक थे। चियान ने निर्देशक एसएस राजामौली की आगामी फिल्म एसएसएमबी29 से जुड़ाव की अफवाहों पर प्रतिक्रिया दी। अस्थायी रूप से एसएसएमबी29 शीर्षक वाली यह फिल्म राजामौली और तेलुगु सुपरस्टार महेश बाबू के बीच पहले सहयोग का प्रतीक है। फिल्म ने वैश्विक ध्यान आकर्षित किया है, खासकर राजामौली की पिछली फिल्म आरआरआर के बाद, जिसने पिछले साल इतिहास रचते हुए ऑस्कर अपने नाम किया था। यह फिल्म एक वर्ष से अधिक समय से प्री-प्रोडक्शन में है। निर्माता, कलाकार और चालक दल इसकी वर्तमान स्थिति के बारे में चुप्पी साधे हुए हैं। महेश के बदलते हेयर स्टाइल के अलावा, फिल्म के घटनाक्रम के बारे में बहुत कम जानकारी जारी की गई है। विक्रम को एसएसएमबी29 में शामिल किए जाने को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं, जिससे चर्चा और भी बढ़ गई है। हालांकि, इस अफवाह में बहुत कम सच्चाई लगती है। विक्रम ने पुष्टि की कि वह भविष्य में राजामौली के साथ काम करने के लिए उत्सुक हैं, लेकिन अभी तक कोई विशेष फिल्म तय नहीं की गई है। विक्रम ने कहा, राजामौली एक अच्छे दोस्त हैं। हम पिछले कुछ समय से बात कर रहे हैं। बेशक, हम कभी एक फिल्म में काम भी करेंगे, लेकिन हमने किसी खास चीज पर विचार नहीं किया है।

नागेश कुकुनूर की मिसेज देशपांडे में नजर आएंगी माधुरी दीक्षित!

माधुरी दीक्षित निर्देशक नागेश कुकुनूर के साथ अपनी आगामी मनोवैज्ञानिक थ्रिलर वेब सीरीज मिसेज देशपांडे में नजर आएंगी। माधुरी दीक्षित ने पिछले कुछ सालों में कई फिल्मों में अपने बेहतरीन अभिनय से प्रशंसकों का दिल जीता है। अपने शानदार आभिनय के साथ ही माधुरी ने अपने बेहतरीन डांस के जरिए भी लोगों के दिलों में खास जगह बनाई है। वहीं मिसेज देशपांडे में माधुरी को एक अलग किरदार में देखना प्रशंसकों के लिए काफी मनोरंजक रहेगा। बॉलीवुड अभिनेत्री माधुरी दीक्षित ने टीवी रियलिटी शो और वेब सीरीज में भी बेहतरीन काम किया है। 2022 में द फेम गेम के साथ डिजिटल में अपनी शुरुआत करने के बाद अब माधुरी आगामी शो मिसेज देशपांडे में नजर आएंगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस आगामी सीरीज में माधुरी एक सीरियल किलर की भूमिका में नजर आ सकती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, माधुरी दीक्षित एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म में सीरियल किलर की भूमिका निभाने के लिए बातचीत कर रही हैं, जिसे नागेश कुकुनूर द्वारा निर्देशित किया जाएगा। इस वेब सीरीज का नाम मिसेज देशपांडे है। शो की कहानी बताती है कि कैसे पुलिस एक सीरियल किलर को काम पर रखती है और दूसरे सीरियल किलर के तरीके को समझने और उसे पकड़ने के लिए उसके दिमाग का इस्तेमाल करती है। बता दें यह शो एक फ्रेंच सीरीज का रीमेक है। बहरहाल, वेब सीरीज की कास्टिंग का काम चल रहा है। वहीं माधुरी के प्रशंसक उनको एक डार्क रोल में देखने के लिए बेहद उत्साहित हैं। नागेश कुकुनूर को मॉडर्न लव हैदराबाद के निर्देशन के लिए जाना जाता है। उन्होंने सिटी ऑफ ड्रीम्स नाम की वेब सीरीज का भी निर्देशन किया है।

पुष्पा 2 के क्लाइमैक्स की शूटिंग कर रहे अल्लू अर्जुन

पुष्पा 2 इस साल की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। फिल्म से जुड़ी छोटी सी छोटी जानकारी का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। अल्लू अर्जुन और फिल्म निर्माता सुकुमार के बीच संभावित झगड़े की अटकलें पिछले कुछ समय से चल रही हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, अभिनेता-निर्देशक के बीच पुष्पा 2- द रूल की शूटिंग में देरी को लेकर मनमुटाव हुआ था। हालांकि, निर्माताओं की ओर से इस बारे में पुष्टि नहीं की गई थी। वहीं अब निर्माताओं ने फिल्म को लेकर दिलचस्प जानकारी साझा की है। निर्माताओं ने आखिरकार अल्लू अर्जुन और पुष्पा 2 के बारे में एक नया अपडेट दिया है। अल्लू अर्जुन इन दिनों पुष्पा 2 के क्लाइमेक्स सीन की शूटिंग कर रहे हैं और इसके भव्य होने की उम्मीद है। पोस्ट साझा करते हुए निर्माताओं ने लिखा, शूट अपडेट- पुष्पा 2 द रूल वर्तमान में क्लाइमेक्स के लिए एक शानदार एक्शन एपिसोड की शूटिंग कर रहा है। 6 दिसंबर 2024 को दुनिया भर में ग्रैंड रिलीज होगी। पोस्ट के अनुसार, टीम वर्तमान में इसके क्लाइमेक्स सीक्वेंस को फिल्मा रही है। निर्माताओं ने पुष्पा 2 की रिलीज की तारीख की भी पुष्टि की। खबर की घोषणा करते हुए, निर्माताओं ने फिल्म से एक छोटा सा अंश साझा किया, जिसमें पुष्पा राज उर्फ अल्लू अर्जुन अपने रोमांचक अवतार में नजर आ रहे हैं। पुष्पा 2- द रूल के लिए उत्सुकता बढ़ने के साथ ही इस अपडेट ने फिल्म की रिलीज को लेकर उत्साह और बढ़ा दिया है। उम्मीद है कि सीक्वल में शानदार नाटकीय अनुभव के लिए हाई-ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंस दिखाए जाएंगे। पुष्पा 2 - द रूल की कहानी निर्देशक सुकुमार और श्रीकांत विसा द्वारा लिखी गई है।

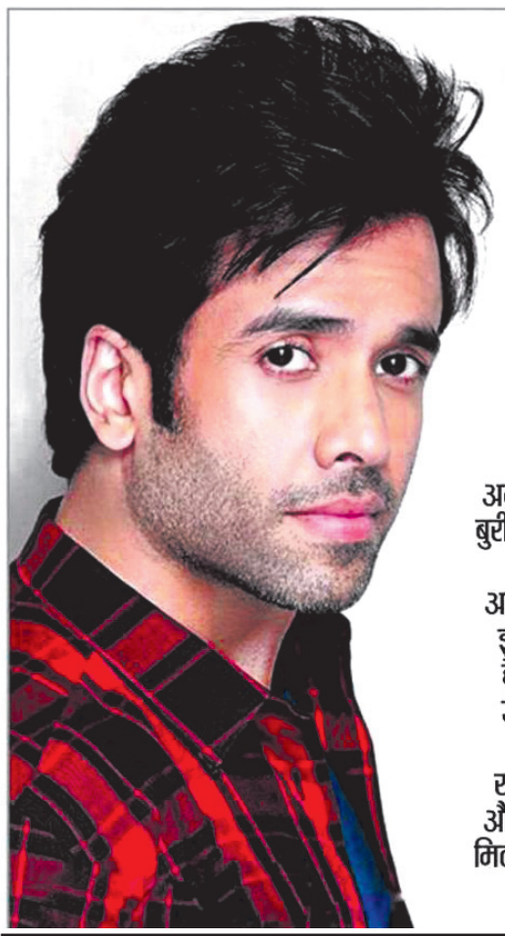

मैं अच्छी और बुरी किस्मत में विश्वास करता हूं, आज फिल्म रिलीज करना बहुत मुश्किल है

एक्टर-प्रड्यूसर तुषार कपूर बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। उनका मानना है कि अच्छी और बुरी किस्मत होती है और हम अपनी प्रार्थनाओं से भाग्य बदल सकते हैं। तुषार ने कहा, मैं अच्छे और बुरे भाग्य में यकीन करता हूं। हम इस दुनिया में कुछ खास कर्मों के साथ आए हैं। कुछ लोग कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हें एक निश्चित सीमा से ज्यादा कामयाबी नहीं मिल पाती, कुछ न कुछ बाधाएं उनके रास्ते में आती रहती हैं। एक्टर ने आगे कहा, और कभी-कभी, ऐसे लोगों को बड़ी कामयाबी मिल जाती है, जो लोग आलसी होते है, लेकिन चीजें उनके लिए सही हो जाती हैं।

मेरा मानना है कि यह सब आपके कर्म से जुड़ा है

उनका मानना है कि लंबे समय के लिए कड़ी मेहनत ज्यादा फायदेमंद होती है। एक्टर ने कहा, ये आपके टारगेट तक पूरा करने के लिए लगने वाले समय को कम कर सकता है या इससे चीजों में देरी भी हो सकती है, यह सब आपके भाग्य पर निर्भर करता है। मेरा मानना है कि यह सब आपके कर्म से जुड़ा है।

मैं बौद्ध धर्म को मानने वाला हूं

भाग्य को कैसे बदला जा सकता है, इस बारे में बात करते हुए तुषार ने कहा, मैं बौद्ध धर्म को मानने वाला हूं, इसलिए मुझे लगता है कि आप हमेशा अपने कर्म और भाग्य को बदल सकते हैं, अपने जीवन में और अधिक सौभाग्य जोड़ सकते हैं, अपनी किस्मत बदल सकते हैं। मैं अच्छे और बुरे भाग्य में विश्वास करता हूं, लेकिन मेरा मानना है कि यह तय नहीं है और आप इसे बदल नहीं सकते। मेरा मानना है कि प्रार्थना से आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं।

ओटीटी शो दस जून की रात में नजर आ रहे हैं

तुषार फिलहाल ओटीटी शो दस जून की रात में नजर आ रहे हैं। इसमें वह भागेश का किरदार निभा रहे हैं, जिसकी किस्मत खराब है। यह पूछे जाने पर कि उन्हें क्या ज्यादा पसंद है, फिल्में या ओटीटी, तुषार ने कहा, पहला प्यार हमेशा फिल्म ही है, लेकिन एक एक्टर के तौर पर सेट पर जाकर परफॉर्म करना और एक अच्छी टीम के साथ काम करना...मुझे लगता है कि यह हर जगह एक जैसा है, फिर चाहे वह कोई फिल्म हो या वेब-शो।

आज फिल्म रिलीज करना बहुत मुश्किल है

उन्होंने कहा कि इसकी तुलना रियलिटी शो के काम से की जा सकती है, जिसका अनुभव कुछ अलग है। तुषार ने कहा, मैं ये नहीं कहूंगा कि एक दूसरे से बेहतर है। लेकिन हां, आज फिल्म रिलीज करना बहुत मुश्किल है। बहुत तनाव है, अगर महामारी है या कई मल्टीपल फिल्म रिलीज है, तो स्क्रीन की परेशानी सामने आती है। लेकिन वेब शो के लिए, यह समस्या नहीं होती, क्योंकि यह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होता है और दर्शक इसे कभी भी और कहीं भी देख सकते हैं।

वेब शो कम चुनौतीपूर्ण है

उन्होंने कहा, मैंने फिल्मों से शुरुआत की, उसकी खुशी ही कुछ अलग है। यह उस मायने में बेहतर है। वहीं वेब शो कम चुनौतीपूर्ण है, लेकिन जहां तक अच्छी रिलीज का सवाल है, आपको उसका फल मिलता है। इसलिए, यह भी एक अलग ही खुशी देता है। बता दें किदस जून की रात जियो सिनेमा पर स्ट्रीम हो रही है।

गर्ल्स हॉस्टल से अहसास चन्ना को मिली थी पहचान

अहसास चन्ना आज अपना 25वां जन्मदिन मना रही हैं। वह कई वेब सीरीज में अपने अभिनय का दमखम दिखा चुकी हैं। सीरीज से पहले वह यूट्यूब चैनल की सीरीज और कई शॉर्ट वीडियोज में भी नजर आ चुकी हैं। अहसास ने अपने करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट की थी। महज पांच साल की उम्र में सुष्मिता सेन के साथ उनकी पहली फिल्म वास्तु शास्त्र आई थी। ओह माय फ्रेंड गणेशा, कभी अलविदा न कहना और आर्यन जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी हैं।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

कांग्रेस सिर्फ मुसलमानों के लिए! राहुल-प्रियंका पर हिमंता का वार

नईदिल्ली। बांग्लादेश में हिंदुओं के हालात को लेकर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर वार किया है। उन्होंने एक बयान में कहा कि कांग्रेस परिवार और प्रियंका गांधी ने गाजा के बारे में बहुत ट्वीट किए हैं। उन्होंने आगे कहा कि गाजा में जो हुआ वह एक आतंकवादी गतिविधि थी और अब जो हो रहा है वह एक आतंकवाद विरोधी कार्रवाई है। लेकिन, बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए, उन्होंने कितनी बार ट्वीट या विरोध किया है? बड़ा आरोप लगाते हुए हिमंत बिस्वा सरमा ने आगे कहा कि कांग्रेस ने साबित कर दिया है कि अगर दुनिया में कहीं भी मुसलमानों के लिए कोई समस्या है, तो वे उनके लिए मौजूद हैं, लेकिन अगर हिंदू समस्या में हैं, तो वे वहां नहीं होंगे। वे केवल हिंदुओं को जाति के आधार पर विभाजित करना चाहते हैं और कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने सीमा के दूसरी तरफ से किसी को भी स्वीकार करने की अनुमति नहीं दी है, आप 1-2 करोड़ लोगों को अनुमति नहीं दे सकते।

प्रधानमंत्री मोदी के इस कदम के मुरीद हुए राहुल गांधी

नईदिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को केरल के वायनाड जिले का दौरा किए। इसका उद्देश्य हाल ही में हुए भूस्खलन से हुई तबाही का आकलन करना है, जिसमें कम से कम 226 लोगों की जान चली गई है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आपदाग्रस्त क्षेत्र का दौरा करने के मोदी के फैसले की प्रशंसा की और उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री नुकसान की गंभीरता को प्रत्यक्ष रूप से देखने के बाद इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करेंगे। राहुल गांधी ने एक्स पोस्ट में लिखा कि मोदी जी, वायनाड में आकर इस भयानक त्रासदी का व्यक्तिगत रूप से जायजा लेने के लिए आपका धन्यवाद। यह एक अच्छा निर्णय है। उन्होंने आगे लिखा कि मुझे पूरा विश्वास है कि एक बार जब प्रधानमंत्री तबाही की भयावहता को प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे, तो वे इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित कर देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने वायनाड में भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण किया। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन भी उनके साथ हैं।

नितिन गडकरी ने भगवंत मान को पत्र लिखकर दी चेतावनी

नईदिल्ली। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पत्र लिखकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को चेतावनी दी है। नितिन गडकरी ने कहा है कि राज्य में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। अगर इसे पंजाब सरकार नहीं सुधारती है तो NHAI 8 हाइवे प्रोजेक्ट रद्द कर देगा। दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे पर हो रहीं लगातार हिंसक घटनाओं को देखते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यह चेतावनी भरा पत्र पंजाब सरकार को लिखा है। जानकारी के लिए बता दें कि इन 8 हाईवे प्रोजेक्ट की कुल लागत 14288 करोड़ है। दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे के निर्माण के दौरान कई स्थानों पर काम रोकने के लिए हिंसक घटनाएं देखने को मिलीं। यह एक्सप्रेसवे राजधानी नई दिल्ली से पंजाब होते हुए माता वैष्णोदेवी कटरा तक बनाया जा रहा है। इस हाईवे का एक हिस्से को पंजाब के अमृतसर से भी जोड़ा जाना है। इंजीनियरों और ठेकेदारों पर हमले को लेकर नितिन गडकरी ने ये नाराजगी पंजाब सरकार से जाहिर की है।

भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं : सिसोदिया

नईदिल्ली। दिल्ली शराब घोटाला मामले में जमानत पर रिहा होने के बाद आप नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी (आप) मुख्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल का नाम आज पूरे देश में ईमानदारी का प्रतीक बन गया है। अपना हमला जारी रखते हुए सिसोदिया ने कहा कि खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली बीजेपी एक भी राज्य में ये साबित नहीं कर पाई कि उनके किसी राज्य में ईमानदारी से काम हो रहा है। उन्होंने हुंकार भरते हुए का कि भ्रष्टाचार का एक ही काल, केजरीवाल, केजरीवाल। उन्होंने आगे कहा कि इन आंसुओं ने ही मुझे ताकत दी है, मुझे उम्मीद थी कि 7-8 महीने में न्याय मिल जाएगा लेकिन कोई बात नहीं 17 महीने लग गए। उन्होंने कहा कि 17 महीने लग गए लेकिन जीत ईमानदारी और सच्चाई की हुई है, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ संसद में कानून लाए मोदी सरकार

लखनऊ। एससी-एसटी में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर सियासत तेज हो गई है। बसपा प्रमुख मायावती ने भी इसको लेकर बड़ी बात कही है। मायावती ने शनिवार को कहा कि शुक्रवार को भाजपा के एससी/एसटी सांसदों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की और प्रधानमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि क्रीमी लेयर और उप-वर्गीकरण नहीं होगा। उन्होंने आगे कहा कि शुक्रवार को मैंने ट्वीट किया था कि अगर दिया गया आश्वासन पूरा होता है तो हमारी पार्टी इसका स्वागत करेगी। मैंने यह भी कहा था कि यह आश्वासन तभी पूरा हो सकता है जब केंद्र सरकार मौजूदा संसद सत्र में ही संविधान संशोधन लाए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रद्द करे। बसपा प्रमुख ने कहा कि मैंने यह भी कहा कि अगर केंद्र सरकार अपने अटॉर्नी जनरल के माध्यम से अपनी दलीलें मजबूती से रखती तो आज यह मुश्किल स्थिति पैदा नहीं होती।

भूस्खलन से टूटे हजारों परिवारों के सपने, यह बड़ी आपदा है: मोदी

पैदल ही मलबे में चल पड़े प्रधानमंत्री, पीड़ितो से भी मिले

नईदिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्थिति का आकलन करने के लिए भूस्खलन प्रभावित वायनाड का दौरा किया। 30 जुलाई को आई इस आपदा में कम से कम 226 लोगों की जान चली गई है और कई लोग अभी भी लापता हैं। इसे केरल में आई सबसे भयंकर प्राकृतिक आपदाओं में से एक माना जाता है। पीड़ितों से मुलाकात के पीएम मोदी ने बड़ी बैठक भी की। इसके बाद मोदी ने कहा कि जिस दिन यह घटना हुई, उस सुबह मैंने सीएम पिनाराई विजयन से बात की थी और उन्हें आश्वासन दिया था कि हम सहायता प्रदान करेंगे और जल्द से जल्द घटनास्थल पर पहुंचने की कोशिश करेंगे।

मोदी ने आगे कहा कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, पुलिस, डॉक्टर, सभी ने पीड़ितों की जल्द से जल्द मदद करने की कोशिश की। मैं मृतकों के परिवारों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि वे अकेले नहीं हैं। हम सभी उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार केरल सरकार के साथ खड़ी है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि पैसे की कमी के कारण कोई भी काम बाधित न हो। उन्होंने कहा कि भूस्खलन की घटना के बारे में जब से मुझे पता चला है, तब से मैं लगातार इसकी जानकारी ले रहा हूँ। केंद्र सरकार की सभी एजेन्सियाँ जो इस आपदा में मदद कर सकती थीं, तुरंत मदद के लिए जुट गई हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि यह आपदा सामान्य नहीं है। हज़ारों परिवारों के सपने चकनाचूर हो गए हैं। मैंने मौके पर जाकर हालात देखे हैं। मैंने राहत शिविरों में पीड़ितों से मुलाकात की है, जिन्होंने इस आपदा का सामना किया है। मैंने अस्पताल में घायल मरीजों से भी मुलाकात की है। अधिकारियों ने बताया कि मोदी कन्नूर हवाई अड्डे से वायुसेना के हेलीकॉप्टर के जरिये वायनाड पहुंचे और 30

जुलाई को बड़े पैमाने पर हुई भूस्खलन की घटनाओं से प्रभावित चूरलमाला क्षेत्र में पैदल चलकर नुकसान का जायजा लिया।

मोदी ने एक राहत शिविर का भी दौरा किया, जहां भारी भूस्खलन के कारण विस्थापित हुए कई लोग रह रहे हैं। उन्होंने घटना से प्रभावित कुछ लोगों से बातचीत की। इनमें दो बच्चे भी शामिल थे, जिन्होंने इस आपदा में अपने प्रियजनों को खो दिया। इस आपदा में 200 से अधिक लोगों की मौत हुई है। बाद में, प्रधानमंत्री ने दोपहर करीब ढाई बजे मेप्पाडी स्थित शिविर का दौरा किया और वहां करीब आधा घंटा बिताया तथा कुछ लोगों से बातचीत की।

केरल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वायनाड भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र के अफसरों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने बचाव कार्य के बारे में जानकारी ली। साथ ही आगे की रणनीति जानी। बैठक में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी भी मौजूद हैं।

बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि जब से मुझे घटना के बारे में जानकारी मिली है, तब से मैं भूस्खलन के बारे में लगातार अपडेट ले रहा हूं। केंद्र सरकार ने सभी एजेंसियों को आपदा में मदद करने के लिए लगाया। यह बहुत बड़ी आपदा है। यह सामान्य घटना नहीं है। भूस्खलन में हजारों परिवारों के सपने टूट गए। उन्होंने कहा कि मैंने राहत शिविरों में पीड़ितों से मुलाकात की और अस्पताल में घायल मरीजों से भी मुलाकात की।

प्रधानमंत्री ने कहा कि जब घटना हुई तो सुबह मैंने सीएम पिनाराई विजयन से बात की और उन्हें आश्वासन दिया कि हम सहायता प्रदान करेंगे। जितनी जल्दी हो सके घटनास्थल पर पहुंचने का प्रयास करेंगे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, पुलिस , डॉक्टर और सभी ने पीड़ितों की जल्द से जल्द मदद करने की कोशिश की। मैं मृतकों के परिवारों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि वे अकेले नहीं हैं। हम सभी उनके साथ खड़े हैं। केंद्र सरकार केरल सरकार के साथ खड़ी है। हम सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी काम बजट की कमी के कारण रुके नहीं।

प्रधानमंत्री के वायनाड दौरे पर जयराम रमेश का तंज

भूस्खलन से प्रभावित वायनाड का दौरा करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बीच कांग्रेस सांसद और महासचिव जयराम रमेश ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मणिपुर का भी दौरा करने को कहा। एएनआई से बातचीत में कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि वायनाड भूस्खलन में करीब 300 लोगों की मौत हो गई है। हमारी मांग थी कि इस घटना को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाना चाहिए। आज पीएम मोदी ने वायनाड का दौरा किया है। अच्छा होगा कि वह मणिपुर भी जाएं।

आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने केरल के वायनाड जिले के भूस्खलन प्रभावित इलाकों का शनिवार को हवाई सर्वेक्षण किया। अधिकारियों के मुताबिक, प्रधानमंत्री ने भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर से भूस्खलन प्रभावित चूरलमाला, मुंडक्कई और पुंचिरीमट्टम गांवों की स्थिति का जायजा लिया। वह पूर्वाह्न करीब 11.15 बजे वायुसेना के हेलीकॉप्टर के जरिये कन्नूर हवाई अड्डे से वायनाड के लिए रवाना हुए थे। अधिकारियों के मुताबिक, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और केंद्रीय पर्यटन तथा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी भी प्रधानमंत्री के साथ वायनाड पहुंचे।

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आपदाग्रस्त क्षेत्र का दौरा करने के मोदी के फैसले की प्रशंसा की और उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री नुकसान की गंभीरता को प्रत्यक्ष रूप से देखने के बाद इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करेंगे। राहुल गांधी ने एक्स पोस्ट में लिखा कि मोदी जी, वायनाड में आकर इस भयानक त्रासदी का व्यक्तिगत रूप से जायजा लेने के लिए आपका धन्यवाद। यह एक अच्छा निर्णय है। उन्होंने आगे लिखा कि मुझे पूरा विश्वास है कि एक बार जब प्रधानमंत्री जी तबाही की भयावहता को प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे, तो वे इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित कर देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वायनाड में भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण किया। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन भी उनके साथ हैं।

जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर साधा निशाना

नेतृत्व पर समाज को बांटने और एक परिवार को प्राथमिकता देने का लगाया आरोप

नईदिल्ली। भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने शनिवार को एक भाषण के दौरान कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा और उसके नेताओं पर नकली देशभक्त होने का आरोप लगाया, जो समाज को बांटते हैं और राष्ट्र के बजाय एक ही परिवार के हितों को प्राथमिकता देते हैं। नड्डा ने यह टिप्पणी गुजरात के राजकोट में भारतीय जनता पार्टी की तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाने से पहले एक भीड़ को संबोधित करते हुए की। नड्डा ने सीधे तौर पर नाम लिए बगैर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा और पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा पहल की आलोचना की।

जेपी नड्डा ने तर्क दिया कि अभियान के पीछे जो लोग हैं, जिन्हें उन्होंने संकीर्ण सोच और छोटी मानसिकता वाला बताया, उन्हें भारत को एकजुट करने में सरदार वल्लभभाई पटेल की महत्वपूर्ण भूमिका को याद रखना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस पर चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। नड्डा ने कहा, मुझे दुख है कि कांग्रेस का कोई भी नेता केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर श्रद्धांजलि देने नहीं आया, लौह पुरुष सरदार पटेल को श्रद्धांजलि देने नहीं आया, जिन्होंने 562 रियासतों को एकजुट करके हमारा महान राष्ट्र बनाया।

इसके अलावा, नड्डा ने कांग्रेस नेताओं से सरदार पटेल को सम्मानित करने के लिए गुजरात और केवडिया जाने का आग्रह किया और इस बात पर जोर दिया कि %भारत जोड़ो यात्रा% में शामिल लोगों को भारत की एकता में पटेल के अपार योगदान को स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस पर देश को राजनीतिक चश्मे से देखने और राष्ट्र के कल्याण से ज़्यादा अपने हितों को प्राथमिकता देने का भी आरोप लगाया। नड्डा ने दर्शकों को भारत के स्वतंत्रता संग्राम में गुजरात की महत्वपूर्ण भूमिका की भी याद दिलाई, जिसमें महात्मा गांधी और सरदार पटेल जैसे नेताओं ने नेतृत्व किया था। उन्होंने देश को एकजुट करने में सरदार पटेल के प्रयासों की प्रशंसा की और इसे एक ऐसी उपलब्धि बताया जिसे भुलाया नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा, अपने समापन भाषण में नड्डा ने कांग्रेस पर केवल गांधी परिवार पर ध्यान केंद्रित करने तथा अनगिनत अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान की उपेक्षा करने का आरोप लगाया।

खेल
प्रमुख समाचार

रीतिका हुड्डा ने नागी को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया

पेरिस। रीतिका हुड्डा ने पेरिस ओलंपिक 2024 अभियान की शानदार शुरुआत की है। भारतीय पहलवान ने हंगरी की बर्नडेट नेगी को हराकर महिलाओं की 76 किग्रा फ्रीस्टाइल स्पर्धा में तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर 12-2 से निर्णायक जीत हासिल की और क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। यह प्रभावशाली जीत ऐतिहासिक महत्व रखती है क्योंकि हुड्डा 76 किग्रा वर्ग के लिए क्वालीफाई करने वाली पहली भारतीय महिला बनीं। दो बार की यूरोपीय चैंपियनशिप पदक विजेता नेगी की चुनौती को पार करते हुए हुड्डा क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं, जहां उनका सामना किर्गिस्तान की शीर्ष वरीयता प्राप्त एपेरी मेडेट काज़ी से होगा।

मैच की शुरुआत दोनों पहलवानों के सतर्क दृष्टिकोण से हुई। नागी ने सबसे पहले गतिरोध को तोड़ा, रीतिका के पैरों को निशाना बनाकर टेकडाउन का प्रयास किया। हालांकि, भारतीय पहलवान के रक्षात्मक रुख ने हमले को विफल कर दिया। रीतिका ने तब तक सुरक्षित खेलना जारी रखा जब तक कि घड़ी ने निष्क्रियता के लिए 'हिट टाइम' चेतावनी नहीं दे दी। अवसर को भांपते हुए, उसने आक्रामक तरीके से टेकडाउन शुरू किया, सफलतापूर्वक नागी को मैट पर धकेल दिया और महत्वपूर्ण चार अंक अर्जित किए। स्पष्ट रूप से घबराई हुई, नागी ने पलटवार करने और गति हासिल करने का प्रयास किया। फिर भी, रीतिका के फुर्तीले फुटवर्क ने हंगरी की पहलवान को बहुत अधिक प्रभावित किया, जिससे कोई महत्वपूर्ण स्कोरिंग अवसर नहीं मिला। जैसे ही पहला पीरियड समाप्त हुआ, भारतीय पहलवान ने अपनी बढ़त बनाए रखी। मैच के दूसरे हाफ में दोनों पहलवानों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। दोनों एथलीटों ने टेकडाउन के प्रयासों का आदान-प्रदान किया, जिसमें रीतिका ने मामूली बढ़त बनाए रखी, दो मिनट शेष रहते 6-2 से आगे चल रही थी।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

बैंकों को जमा जुटाने के लिए आकर्षक उत्पाद लाने चाहिए

नईदिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि बैंकों को जमा राशि जुटाने के लिए अनूठी और आकर्षक योजनाएं लानी चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल को संबोधित करने के बाद सीतारमण ने संवाददाताओं से कहा, ''जमा और उधार एक गाड़ी के दो पहिए हैं और जमा धीरे-धीरे रही है।'' उन्होंने कहा कि बैंकों को कोर बैंकिग यानी मुख्य कारोबार पर ध्यान देने की जरूरत है। इसमें जमा राशि जुटाना और जिन्हें कोष की जरूरत है, उन्हें कर्ज देना शामिल है। सीतारमण ने जमा और कर्ज के बीच अंतर को दूर करने के लिए बैंकों से लोगों से धन जुटाने के लिए 'अनूठी और आकर्षक' जमा योजनाएं लाने को कहा। आरबीआई गवर्नर शक्तिकान्त दास ने कहा कि ब्याज दरें नियंत्रणमुक्त हैं और अक्सर बैंक धन आकर्षित करने के लिए जमा दरें बढ़ाते हैं। दास ने कहा, ''बैंक ब्याज दर पर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं।''

मोदी की अपील के बाद तिरंगे की बिक्री में जबरदस्त उछाल

नई दिल्ली। अब से ठीक चौथे दिन देश अपनी आजादी का 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। ऐसे में शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर एक बार फिर देश के लोगों से हर घर तिरंगा अभियान चलाने की अपील की। उन्होंने लिखा कि अब स्वतंत्रता दिवस नजदीक है, ऐसे में आइए हम सब मिलकर हर घर तिरंगा अभियान को जन आंदोलन बनाएं। प्रधानमंत्री की मोदी की अपील का असर ऐसा रहा कि तिरंगे की सेल में 60-70 प्रतिशत तक का इजाफा हो गया। सदर बाजार में सूरज भाई झंडे वाले के नाम से झंडों का काम करने वाले सूरज प्रकाश ने बताया कि 15 अगस्त से हफ्ते-दस दिन पहले से ही तिरंगे झंडे और इससे जुड़े आइटम्स की सेल बढ़ जाती है। पिछले 3-4 दिनों में तिरंगा आइटम्स की सेल में 60-70 प्रतिशत तक का उछाल आया है।

छह तिमाही में पहली बार प्रॉफिट में आई इंडिया सीमेंट्स कंपनी

नई दिल्ली। दक्षिण भारत की दिग्गज सीमेंट कंपनी इंडिया सीमेंट्स ने शनिवार को अपना जून तिमाही का रिजल्ट जारी किया। लगातार पांच तिमाहियों तक घाटे में रहने के बाद कंपनी के दिन फिरने लगे हैं। जून तिमाही में उसके 57.5 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट हुआ है। पिछले साल समान तिमाही में कंपनी को 87 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। जून तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 28.5 फीसदी की गिरावट के साथ 1,027 करोड़ रुपये रहा जो पिछले साल समान तिमाही में 1,436 करोड़ रुपये था। अल्ट्राटेक सीमेंट जल्दी ही इंडिया सीमेंट्स को टेकओवर करने वाली है। आदित्य बिड़ला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला ने हाल में इंडिया सीमेंट्स में हिस्सेदारी खरीदने के लिए प्रमोटर परिवार के साथ 3,954 करोड़ रुपये की एक डील की थी। इस डील के मुताबिक आदित्य बिड़ला ग्रुप की कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट चेन्नई की कंपनी इंडिया सीमेंट्स में लगभग 33% हिस्सेदारी खरीदेगी।

तीन सरकारी बैंकों ने चुपचाप महंगा कर दिया लोन

नई दिल्ली। नीतिगत ब्याज दरों यानी रेपो रेट पर फैसला लेने वाली आरबीआई की मॉनीटरी पॉलिसी कमेटी की हाल में बैठक हुई थी। इसमें नौवीं बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया गया। रेपो रेट वह दर होती है जिस पर केंद्रीय बैंक देश के बैंकों को लोन देता है। आरबीआई ने तो रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया लेकिन तीन सरकारी बैंकों ने चुपचाप लोन महंगा कर दिया। बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक और यूको बैंक ने एमसीएलआर यानी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट बढ़ा दिया है। तीनों बैंकों ने एमसीएलआर में 5 बीपीएस की बढ़ोतरी की है। इस फैसले का सबसे ज्यादा असर उन ग्राहकों पर पड़ेगा जिन्होंने होम, ऑटो या पर्सनल लोन ले रखा है। देश के टॉप सरकारी बैंकों में से एक बैंक ऑफ बड़ौदा ने कुछ टेन्योर के लोन के लिए एमसीएलआर 12 अगस्त से बढ़ा दिया है।

भारत की आर्थिक प्रगति को रोकने हेतु अशांति फैलाने के हो रहे हैं प्रयास

प्रह्लाद सबनानी

भारत की लगातार तेज हो रही आर्थिक प्रगति पर विश्व के कुछ देश अब ईर्ष्या करने लगे हैं एवं उन्हें यह आभास हो रहा है कि आगे आने वाले समय में इससे उनके अपने आर्थिक हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। इस सूची में सबसे ऊपर चीन का नाम उभर कर सामने आ रहा है। और फिर, चीन की अपनी आर्थिक प्रगति धीमी भी होती जा रही है। दूसरे, विश्व को भी आज यह आभास होने लगा है कि विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन के मामले में केवल चीन पर निर्भर रहना बहुत जोखिम भरा कार्य है। इसका अनुभव विशेष रूप से विकसित देशों ने कोरोना महामारी के बाद से वितरण चैन में आई भारी परेशानी से किया है, जिसके चलते इन देशों में मुद्रा स्फीति की समस्या आज भी पूरे तौर पर नियंत्रण में नहीं आ पाई है। साथ ही, चीन की विस्तारवादी नीतियों के चलते उसके अपने किसी भी पड़ोसी देश से (पाकिस्तान को छोड़कर) अच्छे सम्बंध नहीं हैं। अत: कई देश अब यह सोचने पर मजबूर हुए हैं कि चीन+1 की नीति का अनुपालन ही उनके हित में होगा। अर्थात, यदि किसी उद्योगपति ने चीन में अपनी एक विनिर्माण इकाई स्थापित की है तो आवश्यकता पड़ने पर उसके द्वारा अब दूसरी विनिर्माण इकाई चीन में स्थापित न करते हुए इसे अब किसी अन्य देश में स्थापित किया जाना चाहिए। यह दूसरा देश भारत भी हो सकता क्योंकि भारत अब न केवल ईज आफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में अतुलनीय सुधार करता हुआ दिखाई दे रहा है बल्कि भारत में बुनियादी ढांचा के विस्तार में भी अतुलनीय प्रगति दृष्टिगोचर है।

केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक क्षेत्र में लागू की गई कई नीतियों के चलते भारत आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तो

बन ही गया है और अब यह तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। अर्थ के कई क्षेत्रों में तो भारत विश्व में प्रथम पायदान पर आ भी चुका है। इससे अब चीन के साथ अमेरिका को भी आने वाले समय में वैश्विक स्तर पर अपने प्रभाव में कमी आने की चिंता सताने लगी है। अत: विश्व के कई देशों में अब भारत की आर्थिक प्रगति को लेकर ईर्ष्या की भावना विकसित होती दिखाई दे रही है। इस ईर्ष्या की भावना के कारण वे भारत के लिए कई प्रकार की समस्याएं खड़ी करने का प्रयास करते दिखाई देने लगे हैं। यह समस्याएं केवल आर्थिक क्षेत्र में खड़ी नहीं की जा रही हैं बल्कि सामाजिक, राजनैतिक एवं आध्यात्मिक आदि क्षेत्रों में भी खड़ी करने के प्रयास हो रहे हैं।

सबसे पहिले तो कुछ देश प्रयास कर रहे हैं कि भारत में किस प्रकार सामाजिक अशांति फैलायी जाए। इसके लिए भारत की कुटुंब प्रणाली को तोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। दूसरे, कई देश अब भारत में सामाजिक समरसता के तानेबाने को भी विपरीत रूप से प्रभावित करने के प्रयास करते हुए दिखाई दे रहे हैं। विशेष रूप से हिंदू समाज में विभिन्न मत, पंथ मानने वाले नागरिकों को आपस में लड़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि इन्हें आपस में बांटा जा सके और भारत में अशांति फैलायी जा सके तथा जिससे देश की आर्थिक प्रगति विपरीत रूप से प्रभावित हो सके।

तीसरे, कई देशों द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप के अन्य देशों में भी अस्थिरता फैलाने के प्रयास किए जा रहे हैं। सबसे ताजा उदाहरण बांग्लादेश का लिया जा सकता है जहां हाल ही में सत्ता परिवर्तन हुआ है। अब बांग्लादेश में अतिवादी दलों के हाथों में सत्ता की कमान जाती हुई दिखाई दे रही है इससे अब बांग्लादेश में भी आर्थिक प्रगति विपरीत रूप से प्रभावित होगी। मालदीव में पूर्व में ही भारत विरोध के नाम पर अतिवादी दलों ने सत्ता हथिया ली है, जो वहां भारत गो बैक के नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं एवं चीन के साथ अपने राजनैतिक रिश्ते स्थापित कर रहे हैं। नेपाल में भी हाल ही में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद वे चीन के करीब जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। श्रीलंका पूर्व में ही राजनैतिक अस्थिरता के दौर से गुजर चुका है। पाकिस्तान तो घोषित रूप से अपने आप को भारत का दुश्मन देश कहलाता है।

नक्सलियों के लिए करते थे वसूली, 5 आरोपी गिरफ्तार

मोहला। मोहला पुलिस ने नक्सलियों के लिए वसूली करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास वसूली के मनी ट्रेल का खुलासा भी किया गया है। जिसमें इन्होंने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा लेव्ही वसूल कर नक्सलियों को पहुंचाई थी। इन्हीं पैसों से आरोपी सूरजू राम टेकाम के लिए फ्लाईट टिकिट बुक करना और नक्सलियों को सामान सप्लाई किया जाता था।

पुलिस की पूछताछ में पता चला कि आरोपी सुरजू राम टेकाम माओवादी संगठन के प्रचार- प्रसार के लिए और अपने नेटवर्क को आगे बढ़ाने के लिए लगातार शहरी क्षेत्रों में भ्रमण कर रहा था। भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) संगठन द्वारा पर्दे के पीछे से प्रायोजित ऑपरेशन कगार, कार्पोरेटीकरण, सैनिकीकरण के विरोध में 23 मार्च को कार्यक्रम आयोजित किया था। जिसमें शामिल होने के लिए सूरजू राम टेकाम 22 मार्च को फ्लाईट के माध्यम से वह रायपुर से दिल्ली गया था। दिल्ली जाने के लिए फ्लाईट टिकिट नक्सलियों द्वारा लेव्ही से प्राप्त पैसों से सुरजू राम टेकाम और सोनाराम फरसा के लिए टिकिट बुक कराई गई थी।

लेव्ही के पैसों से गया था दिल्ली- वहीं सोनाराम फरसा को सुरजू राम टेकाम के द्वारा उसे दिल्ली जाने के लिए लेव्ही से मिले पैसों में से कुछ पैसे भेजने के लिए कहा और साथ में चलने के लिए भी कहा। तब सोनाराम फरसा ने ठेकेदार से प्राप्त पैसों में से अपने खाते के माध्यम से सुरजू राम टेकाम के बताए खाते पर पैसे भेजे। तब सुरजू राम टेकाम ने उस अकाउंट से फ्लाईट टिकिट बुक करने के लिए विवेक सिंह को पैसे भिजवाया। विवेक सिंह द्वारा सूरजू राम टेकाम के कहने पर नक्सलियों के शहरी नेटवर्क को लगातार अलग-अलग माध्यम से सहयोग कर रहा था और ये लगातार एक- दुसरे से संपर्क में थे। नक्सलियों के द्वारा भैरमगढ़ क्षेत्र में तेंदूपत्ता ठेकेदारों को जान-माल नुकसान पहुंचाने की धमकी देकर सोनाराम फरसा, विजय जुर्री, रामलाल करमा और राजेंद्र कड़ती के माध्यम से लेव्ही वसूली की जा रही थी। इन चारों को वर्ष 2022 में एक करोड़ रुपए लेव्ही वसूलने का टारगेट दिया गया था। जिसके लिए भैरमगढ़ क्षेत्र में तेंदूपत्ता ठेकेदार से जंगल क्षेत्र में काम करने के एवज में नक्सलियों ने सोनाराम फरसा, विजय जुर्री, रामलाल करमा और राजेंद्र कड़ती की सहायता से ठेकेदार को जान-माल नुकसान पहुंचाने का धमकी देकर करोड़ो रुपयों की लेव्ही वसूली किए। वहीं सोनाराम फरसा, विजय जुर्री, रामलाल करमा, राजेंद्र कड़ती ने अपने बैंक अकाउंट के माध्यम से लेव्ही के तकरीबन 60 लाख रुपए प्राप्त किए और बाद में बैंक से नगदी निकालकर नक्सलियों को पहुंचाने का कार्य करते थे। राजेंद्र कड़ती का बड़ा भाई मोहन कड़ती कुख्यात नक्सली कमांडर भैरमगढ़ क्षेत्र का है। उक्त सभी कई सालों से नक्सलियों से मिलकर ठेकेदारों से लेव्ही वसूली, नक्सलियों को राशन, दवाई और अन्य जरूरत की सामाग्री का सप्लाई कर रहे थे। इस मामले में भैरमगढ़ क्षेत्र के निवासी सोनाराम फरसा, विजय जुर्री, रामलाल करमा और राजेंद्र कड़ती ने ठेकेदार से नक्सलियों के लिए लेव्ही वसूली ऑनलाइन की और बैंक से निकालकर पैसे नक्सलियों तक पहुंचाए।

नक्सलियों के सहयोगियों के द्वारा माओवादियों के आदेश पर शहरी नेटवर्क को सपोर्ट करने के लिए नक्सल संगठन के शहरी सदस्यों के यात्रा और अन्य खर्चों के लिए आनलाईन पैसे ट्रासफर करते थे। जिसके तहत सूरजू राम टेकाम के यात्रा के लिए लेव्ही के पैसों का उपयोग किया गया। फ़िलहाल इस मामले में जांच जारी है और आगे और भी संलिप्तता की जानकारी के लिए फायनेंशियल ट्रेल, इलेक्ट्रानिक और अन्य दस्तावेजों का विश्लेषण किया जा रहा है।

गिरफ्तार आरोपी

1. सोनाराम फरसा पिता स्व. पांडूराम उम्र 28 वर्ष पता पंचायत बिरियाभूमि आदवाड़ा थाना जांगला जिला बीजापुर
2. विजय जुर्री पिता स्व. संतूराम जुर्री उम्र 32 वर्ष सा0 मरकापाल ग्रां.पं. बांगोली थाना भैरमगढ़ जिला बीजापुर
3. रामलाल करमा पिता तुपाराम करमा उम्र 35 वर्ष ग्राम बांगोली थाना बांगापाल जिला बीजापुर
4. राजेंद्र कड़ती पिता स्व. बुगुर कड़ती उम्र 30 वर्ष ग्राम डेगमेटा ग्रा.पं. फुलगट्टा थाना मिरतुर जिला बीजापुर
5. विवेक सिंह पिता राम सुशील सिंह उम्र 35 वर्ष ग्राम मानपुर जिला मोहला, मानपुर-अंबागढ़, चौकी वर्तमान पता अर्जुन वेली सड्डू थाना विधानसभा, जिला रायपुर

उपमुख्यमंत्री पहुंचे रायपुर के आजाद हॉस्टल, वार्षिक हॉस्टल डे में हुए शामिल

सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं: शर्मा

रायपुर। उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि जीवन में सफलता के लिए कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता, कभी भी सफलता के लिए शॉटकट रास्ता ढूंढ़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, जो हम अपने प्रारब्ध को बदल नहीं सकते हैं। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगन और ईमानदारी के साथ उस दिशा में लग जाना चाहिए। कड़ी मेहनत से ही जीवन में आगे बढ़ा जा सकता है, सफलता हासिल की जा सकती है, जबकि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है।

उन्होंने कहा कि मुकाम प्राप्त करने के बाद बैठ जाना की सफलता नहीं कहा जा सकता, बल्कि उस विषय में दक्षता और महारथ हासिल होना चाहिए। साथ ही उस लक्ष्य को पाने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा आज पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय परिसर स्थित सभाकक्ष में आयोजित शहीद चंद्रशेखर आजाद हॉस्टल डे को सम्बोधित कर रहे थे। गौरतलब है कि उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा भी इस हॉस्टल में रहकर अध्ययन किए हैं। उपमुख्यमंत्री बनने के बाद पहुंचे श्री शर्मा को आजाद हॉस्टल के छात्रों सहित परिसर स्थित अन्य हॉस्टल के छात्र-छात्राओं ने उल्लासपूर्वक उनका अभिनंदन किया। इस मौके पर उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने पूर्व छात्रों, अधीक्षकों, प्रोफेसरों तथा उत्कृष्ट कार्य करने वाले छात्रों तथा कर्मचारियों को सम्मानित किया। छात्रावास के छात्र-छात्राओं द्वारा उपमुख्यमंत्री को स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। उपमुख्यंत्री श्री विजय शर्मा ने छात्रावास डे को सम्बोधित करते हुए कहा कि जीवन में सबकुछ योजना के मुताबिक हो, ऐसा सम्भव नहीं हो पाता, लेकिन हमें लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए योजना बनाकर मंजिल को प्राप्त करने की दिशा में हरसंभव प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें अपने संस्कार और परंपरा को नहीं भुलना चाहिए। बड़ों के प्रति सम्मान और संस्कार से हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, सफलता हासिल कर सकते हैं। उन्होंने सभी हॉस्टल छात्र-छात्राओं को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दीं। इस मौके पर सांस्कृतिक संध्या का आयोजन भी किया गया।

कार्यक्रम में पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. सच्चिदानंद शुक्ल, राज्य सूचना आयोग के सचिव श्री गोपाल वर्मा, कुलसचिव श्री शैलेन्द्र पटेल, डॉ. रविन्द्र मिश्र, डॉ. एम.एल. नायक सहित बड़ी संख्या में पूर्व छात्र तथा विभिन्न हॉस्टल के छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।

भाजपा ने कांग्रेस पर दागे सवाल महिला आदिवासी राष्ट्रपति न बने ऐसा प्रयास क्यों किया

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने कहा है कि झूठ का बाजार सजाकर अफवाह व भ्रम फैलाकर अब कांग्रेस विश्व आदिवासी दिवस को लेकर ओछी राजनीति कर रही है। श्री ठाकुर ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज भी अब आलाकमान के सामने अपना नंबर बढ़ाने की कवायद करके सत्य और तथ्य से परे बातें करने लगे हैं। बैज के बयान से यह साफ हो गया है कि आदिवासी विरोधी कांग्रेस अपने राजनीतिक आचरण से सौ-सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली की उक्ति को चरितार्थ कर रही है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्री ठाकुर ने कहा दरअसल कांग्रेस के पास अब कोई मुद्दा है नहीं, इसलिए ऊलजलूल बयानबाजी करके अपने राजनीतिक वजूद की आखिरी लड़ाई से जूझ रही है। भाजपा की प्रदेश सरकार ने आदिवासियों को जो सम्मानजनक स्थान देकर उनके सर्वतोमुखी कल्याण का सतत चिंतन करते हुए जो काम किया है, उससे कांग्रेस का आदिवासी विरोधी डीएनए जगजाहिर हो रहा है और इसीलिए कांग्रेसी जब-तब झूठ का सहारा लेकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने का हास्यास्पद उपक्रम करते रहते हैं। श्री ठाकुर ने कहा कि बेसिरपैर की बयानबाजी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके अनुषांगिक संगठनों को घसीटने की बुरी लत के शिकार कांग्रेस के लोग पहले अपने और अपनी पिछली भूपेश सरकार के आदिवासी विरोधी कारनामों को याद कर लिया करें।

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्री ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस को आदिवासियों और आदिवासी संस्कृति के बारे में बात करने का कोई हक नहीं है। कांग्रेस ने कभी भी छत्तीसगढ़ राज्य के लिए काम नहीं किया। आदिवासी बहुल छत्तीसगढ़ को एक पूर्ण राज्य का दर्जा भाजपा ने दिया।आदिवासी महिला जब राष्ट्रपति बन रही थी, तो कांग्रेस ने पूरा विरोध किया और द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति नहीं बनने देने के लिए पूरा दम लगाया और पूरी कोशिश की कि एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति न बन पाए। भारतीय जनता पार्टी ने ही आदिवासियों के लिए छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया, यह सही मायने में आदिवासियों का सम्मान है, एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया यह आदिवासियों का सम्मान है, एक आदिवासी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, यह सही मायने में आदिवासियों का सम्मान है, देश के 63 हजार ग्रामों के 5 करोड़ आदिवासियों के लिए प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम योजना का संकल्प सही मायने में आदिवासियों का सम्मान है।झभाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्री ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के राज में तो लगातार आदिवासियों का शोषण हुआ है, उन्हें कोई पद नहीं मिला है और जिन्हें पदों पर बिठाया गया, उन्हें कठपुतली बनकर बिठाया गया। मोहन मरकाम को किस प्रकार से अपमानित किया गया था, यह सबने देखा है। खुद दीपक बैज का क्या हाल है, यह पूरी कांग्रेस देख ही रही है, जिन्हें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुले तौर पर हमेशा अपमानित करते रहे.

दिवंगत से सवाल करना दुर्भाग्यजनकःभूपेश

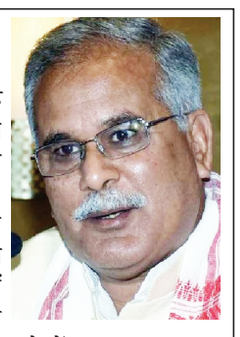

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कोई भी व्यक्ति स्वर्गवासी हो जाये तो उससे सवाल कैसे कर सकते है जब सवाल का जवाब देने के लिये वो व्यक्ति उपस्थित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा दिवंगत से सवाल करते है गांधी जी से, नेहरू जी से, इंदिरा जी से सवाल करते है। आज मेरे पिताजी से सवाल कर रहे है, मूर्खता की हद हो गयी। मेरे पिताजी से राजनीतिक विरोधाभास थे। उनकी लाइन अलग थी, मेरे लाइन अलग थी। वो कहां आते थे, कहां जाते थे? उन्होंने सर्वोदय से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की और अंतिम क्षणों में यही बात कर रहे थे कि बुद्ध की बात कहते थे बुद्ध के बिना पूरी दुनिया में शांति नहीं हो सकती। उस व्यक्ति के बारे में इस प्रकार ओछी बयान देना बताता है कि संतोष पांडेय की मानसिकता क्या है? ऐसी मानसिकता वाले व्यक्ति को मैं कोई जवाब नहीं देना चाहता। घटिया मानसिकता के व्यक्ति है। किसके साथ संबंध है, किसके साथ नहीं। सब लोग जानते है नक्सली भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के बंगले में उनके कार्यालय में हफ्ता वसूली किया करते थे। दिवंगत हो गये उनके बारे में सवाल खड़ा करना बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। मानव हाथी द्वंद को रोकने के लिये काम किये थे और हाथी मानव द्वंद को रोके थे और उसमें एमप्लीमेंट भी किया था उसका लाभ मिला। लगातार जंगल को काटते जायेंगे तो हाथी जायेंगे कहां? उनको रोकने का तरीका यही है हाथी प्रभावित क्षेत्र में हाथी जंगल में रहे और उसके लिये पानी और चारा का व्यवस्था करें। यदि उसके आश्रय को नष्ट करते जायेंगे तो हाथी जंगल से निकल कर गांव तरफ आयेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार वन इलेक्शन, वन नेशन कैसे करा सकती है? चुनाव केवल पंचायत, नगरीय निकाय के नहीं होते, चुनाव विधानसभा के भी होते है, लोकसभा के भी होते है जो राज्य सरकार के हाथ में नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में ये क्या चर्चा करेंगे, इनकी चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर होगी और यह संभव नहीं है वन नेशन, वन इलेक्शन। एक भी जगह अभ्यारण नहीं बना है।

छत्तीसगढ़/राजधानी

प्रमुख समाचार

भाजपा ने किया आदिवासियों का अपमान : कांग्रेस

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर 9 अगस्त को छत्तीसगढ़ में आयोजित कार्यक्रमों का बहिष्कार करके भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासियों के सम्मान को ठेस पहुंचाई है। भाजपा सरकार द्वारा रायपुर में आयोजित दो प्रमुख कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया, जिसमें आदिवासी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और वरिष्ठ आदिवासी मंत्री रामविचार नेताम को शामिल होना था। उन्होंने बताया कि रायपुर के इंडोर स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को शामिल होना था, लेकिन उन्होंने अंतिम समय पर इस कार्यक्रम में शामिल न होने का फैसला किया। वहीं महंत घासीदास संग्रहालय की कला वीथिका में आदिवासियों पर आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन रामविचार नेताम द्वारा किया जाना था, जिसे अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया। पीसीसी चीफ ने कहा कि विश्व आदिवासी दिवस के बहिष्कार का कारण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के दबाव को बताया जा रहा है। आरएसएस से जुड़े वनवासी कल्याण आश्रम के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह ने इस दिवस को अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र करार देते हुए इसे अप्रासंगिक बताया। उनके इस बयान के बाद भाजपा सरकार पर दबाव बढ़ा और उन्होंने आदिवासी दिवस के कार्यक्रमों का बहिष्कार किया।

पंजीयन विभाग के 3 सब रजिस्ट्रार निलंबित

रायपुर। पंजीयन कार्य में भ्रष्टाचार करने वाले तीन अधिकारियों पर निलंबन की गाज गिरी है। रायपुर, धमतरी और पाटन के सब रजिस्ट्रार को निलंबित किया गया है। इसका आदेश महानिरीक्षक पंजीयन विभाग ने जारी किया है। पंजीयन विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक रायपुर कार्यालय में पदस्थ मंजूषा मिश्रा, धमतरी कार्यालय में पदस्थ सुशील देहारी, पाटन कार्यालय में पदस्थ शशिकांता पात्रे को निलंबित किया गया है। वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग के विभागीय मंत्री ओपी चौधरी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा शासकीय कार्य में नहीं होनी चाहिए और विभाग में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विभाग के कुछ अधिकारी चुनिन्दा लोगों के साथ मिलकर गलत पंजीयन कर भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए, जिससे शासन को राजस्व की हानि हुई है, ऐसे अधिकारियों के विरूद्ध निलंबन की कार्रवाई की गई है। राज्य में सुशासन स्थापित करने जांच की कार्रवाई निरंतर चलती रहेगी, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाए जाने का कार्य जारी रहेगा। जो भी अधिकारी, कर्मचारी भ्रष्टाचार की गतिविधियों में संलिप्त पाए जाएंगे उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी।

यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट एसो. ने सांसद बृजमोहन से की मुलाकात

रायपुर। कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में बीते दिनों एक महिला ड्यूटी डॉक्टर का शव संदिग्ध हालात में मिलने से हड़कंप मच गया है। प्रारंभिक रिपोर्ट्स के अनुसार, पोस्टमॉर्टम के बाद यह संभावना व्यक्त की जा रही है कि मृतका के साथ शारीरिक और यौन हिंसा की गई हो। इस घटना ने राज्य की कानून व्यवस्था और सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस बीच यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट एसोसिएशन छत्तीसगढ़ के पदाधिकारियों ने रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल से मुलाकात कर इस घटना की सीबीआई जांच की मांग की है। यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट एसोसिएशन छत्तीसगढ़ के पदाधिकारियों ने रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल से कहा कि बंगाल के स्थानीय गुंडों और राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं द्वारा इस घटना को अंजाम देने की आशंका जताई जा रही है, जिससे राज्य पुलिस और प्रशासन से न्याय की उम्मीद कम लग रही है। इसीलिए हम आपसे निवेदन करते है की महिला डॉक्टर के साथ हुई घटना को अंजाम देने वालो को सजा दिलवाने के लिए इस घटना की सीबीआई जांच करवाई जाए वरना मृत महिला डॉक्टर को न्याय नहीं मिल पाएगा। यूडीएफए सीजी ने कहा कि इस घटना से सीख लेते हुए हमे छत्तीसगढ़ में कार्यरत डॉक्टर्स और विशेषकर महिला चिकित्सकों के लिए हर मेडिकल कॉलेज के साथ जिले एवं ब्लॉक के अस्पतालों में उपयुक्त सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए.

छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार नागपुर से चलती है - बैज

रायपुर। विश्व आदिवासी दिवस पर आरएसएस के खुले विरोध की वजह से भाजपा सरकार दबाव में आकर आदिवासियों का अपमान किया। रायपुर में दो कार्यक्रम थे और दोनों ही कार्यक्रमों की घोषणा के बाद सरकार के प्रतिनिधि वहां नहीं गए, एक रायपुर के इंडोर स्टेडियम में था जिसमें आदिवासी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को शामिल होना था पर ऐन वक्त पर उन्होंने तय किया कि वे इस कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। दूसरा कार्यक्रम महंत घासीदास संग्रहालय की कला वीथिका में आदिवासियों पर आयोजित एक प्रदर्शनी थी, जिसका उद्घाटन भाजपा सरकार के वरिष्ठ आदिवासी मंत्री रामविचार नेताम को करना था यह प्रदर्शनी अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया। पिछले पांच वर्षों में कांग्रेस की सरकार ने विश्व आदिवासी दिवस को एक उत्सव का रूप दिया और सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की थी। उक्त बातें पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहीं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार नागपुर से चलती है, क्रोनोलॉजी समझिए, छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से हर साल विश्व आदिवासी दिन विज्ञापन जारी किए जाते थे, मुख्यमंत्री की ओर से आदिवासी समाज को अग्रिम शुभकामनाएं दी जाती थीं, न तो सरकार ने कोई विज्ञापन जारी किया और न मीडिया को मुख्यमंत्री की ओर से कोई शुभकामना जारी की गई।

ओला पीड़ित किसानों को मिला 9 लाख का मुआवजा

रायपुर। राज्य शासन द्वारा किसानों को खेती-किसानी में प्राकृतिक रूप से 33 प्रतिशत से अधिक नुकसान होने पर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा दिए जाने का प्रावधान है। इस कड़ी में बिलासपुर जिले के बेलगहना तहसील के 4 गावों के 164 ओला पीड़ित किसानों को 9 लाख रुपए की मुआवजा राशि के चेक का वितरण किया गया है। कलेक्टर श्री अवनीश शरण के निर्देश पर एसडीएम युगल किशोर उर्वशा ने कोनचरा में आयोजित कार्यक्रम में प्रभावित किसानों को मुआवजा राशि के चेक वितरित किए। शेष किसानों को आरटीजीएस के जरिए राशि बैंक खातों में जमा करा दी गई। उल्लेखनीय है कि प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत प्रति हेक्टेयर नुकसान के लिए 8500 रुपए की मुआवजा दी जाती है। 33 प्रतिशत अथवा इससे अधिक नुकसान पर मुआवजा दिए जाने का प्रावधान है। गौरतलब है कि बेलगहना के ग्राम पहांदा, कोनचरा, सुखेना और जरगा के किसानों का रबी धान की फसल को ओला वृष्टि से नुकसान पहुंचा था। उन्होंने जनदर्शन में कलेक्टर को आवेदन देकर मुआवजा की मांग की थी। कलेक्टर ने टीएल में रखकर इसकी प्रगति की समीक्षा की। राजस्व निरीक्षक और पटवारियों को तेजी से सर्वे कर प्रकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। लाभान्वित किसानों में पहांदा के 116, कोनचरा के 33, सूखेना के 11 और जरगा के 4 किसान शामिल हैं।

कल से भाजपा के राष्ट्रीयता के अभियानों की शुरुआत

हर घर फहराएगा तिरंगा,होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम, 90 विस में होगी तिरंगा यात्रा

छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने बताया कि कल से भाजपा के हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो रही है 11 अगस्त से 14 अगस्त तक बड़े जोर शोर, हर्षोल्लाह और धूमधाम के साथ पूरे प्रदेश वासियों की सहभागिता के साथ हर बूथ पर 50 से ज्यादा झंडे लगाते हुए, हर घर तिरंगा का उत्सव भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ प्रदेश की जनता भी मनाने जा रही है। श्री श्रीवास्तव ने बताया कि हर घर तिरंगा अभियान अब लोगों की पहली पसंद बन गया है उन्हें अब इंतजार रहता है की कब अपने घर, अपने कार्यालय में अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में भारतीय तिरंगा लगाकर उसे सेल्यूट करें, गर्व का अनुभव करें। 4 दिनो तक चलने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में मा.मुख्यमंत्री विष्णु देव साय,उपमख्यमंत्री श्री अरुण साव ,विजय शर्मा,मंत्रीगण शामिल होंगे।विधानसभा स्तर पर होने वाले कार्यक्रमों का नेतृत्व विधायकगण करेंगे।कार्यक्रमो में भाजपा के सांसद गण, प्रदेश पदाधिकारी,प्रदेश कार्यसमिति सदस्य सहित जिलाध्यक्ष सहित मंडल और बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता शामिल होगे।अभियान में भाजपा के लाखो कार्यकर्ताओं की सहभागिता होगी।

श्री श्रीवास्तव ने बताया कि प्रदेश के 90 विधानसभा में भारत मां के जय घोष के साथ, तिरंगा यात्रा निकलने जा रही है 14 अगस्त को भारत के विभाजन की त्रासदी झेलने वाले सभी लोगों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर विशेष व्याख्यान आयोजित होंगे तथा 13 अगस्त को प्रदेश भर में बड़े स्तर पर राष्ट्रीय कार्यक्रमों की धूम होगी। श्री श्रीवास्तव ने बताया कि भाजपा के मंडल स्तर से लेकर बूथ स्तर के कार्यकर्ता इस अभियान में जुटे हैं व प्रदेश की जनता का अभूतपूर्व उत्साह देखने को मिल रहा है सभी देश की स्वतंत्रता के उत्सव को बड़े श्रद्धा भाव और गर्व के साथ मनाने जा रहे है।

निजात अभियान के तहत ड्राइंग-पेंटिंग प्रतियोगिता

रायपुर। रायपुर पुलिस द्वारा नशा मुक्ति अभियान निजात के अंतर्गत सालेम इंग्लिश मीडियम स्कूल में ड्राइंग और पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें रायपुर जिले के 35 स्कूलों से लगभग 530 छात्रों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाना और छात्रों को नशामुक्त समाज की दिशा में प्रेरित करना था।

रायपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. संतोष कुमार सिंह के निर्देशानुसार, रायपुर पुलिस ने निजात अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत न केवल ड्रग पेडलर्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है, बल्कि नशे से ग्रसित लोगों की काउंसलिंग भी की जा रही है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में आयोजित इस प्रतियोगिता में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों ने अपनी कला के माध्यम से नशे के खिलाफ संदेश दिया। प्रतियोगिता के अंत में, विजेता छात्रों को प्रथम, द्वितीय, और तृतीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जबकि अन्य प्रतिभागियों को सांत्वना पुरस्कार प्रदान किए गए।

कार्यक्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. संतोष कुमार सिंह ने खुद उपस्थित होकर छात्रों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया। उन्होंने कहा, अगर जिंदगी में खुशियां चाहिए तो नशे को न कहना है और जिंदगी को हां कहना है। सीएसपी आजाद चौक, अमन कुमार झा ने प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्रों की पेंटिंग्स की सराहना की और कहा कि सभी ने नशे के दुष्प्रभावों को सटीक रूप से व्यक्त किया है।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.